◆ सितम्बर, 2021 ◆ मूल्य: 35/-

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से अनुप्राणित

व्यक्ति विशेष

अभ्युदय वात्सल्यम्

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका

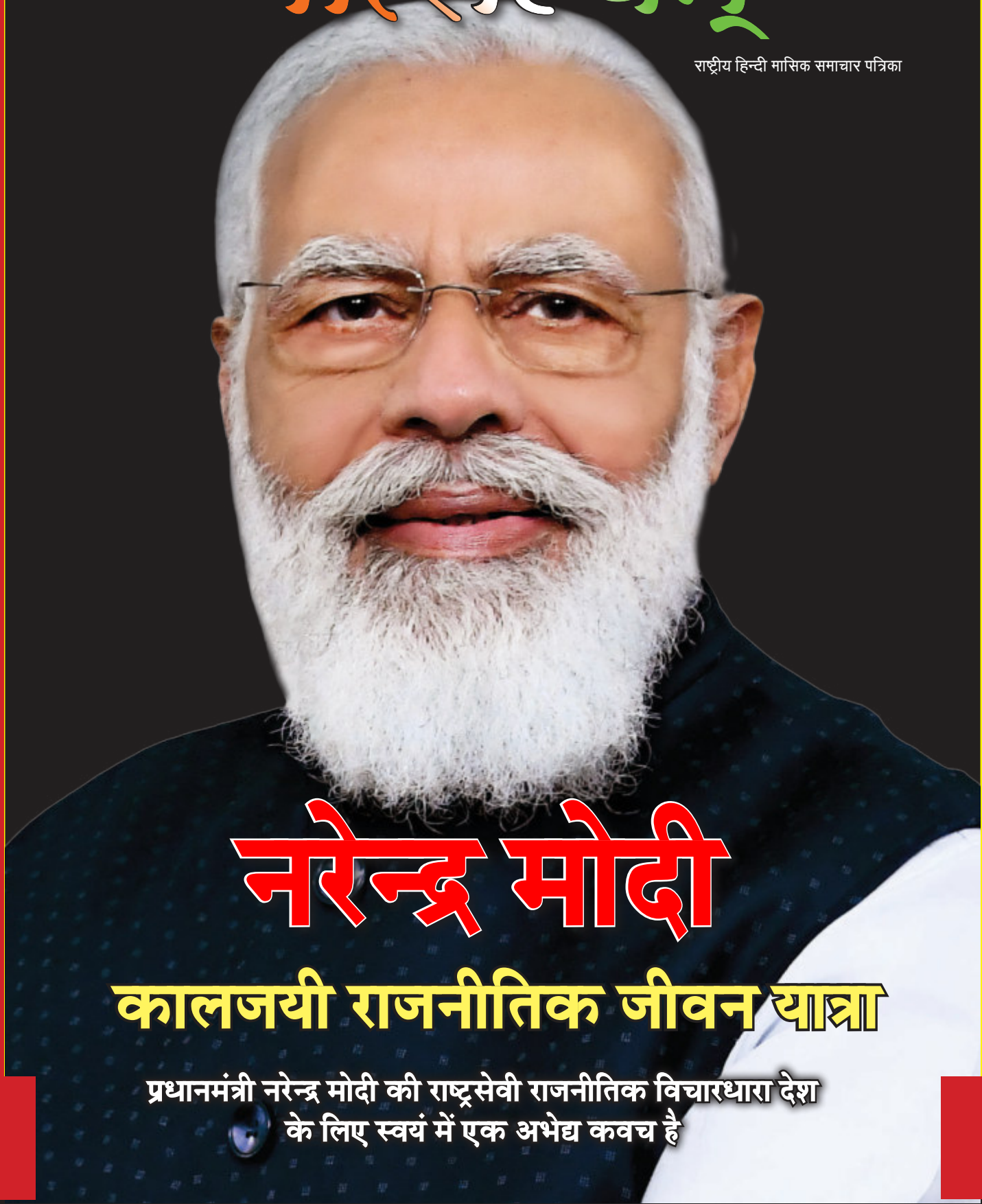

नरेन्द्र मोदी

कालजयी राजनीतिक जीवन यात्रा

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की राष्ट्रसेवी राजनीतिक विचारधारा देश के लिए स्वयं में एक अभेद्य कवच है

50%* ज़्यादा शक्तिशाली
नया गुडनाइट पावर ऐक्टिव+ लगाओ
और अपने परिवार को रखो मच्छरों से सुरक्षित
50% MORE POWER
Godrej
Good knight
नया
POWER ACTIV+
50% MORE POWER*
ज़्यादा पावर पुश करो, ज़्यादा ख़ुश रहो

वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना से अनुप्राणित

अभ्युदय वात्सल्यम्

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक समाचार पत्रिका

वर्ष-14 ■ अंक-02 सितम्बर, 2021 ■ मूल्य- 35/-

प्रधान सम्पादक : आलोक रंजन तिवारी
प्रबन्ध सम्पादक : शिवा तिवारी
दिल्ली - एनसीआर ब्यूरो : आशुतोष मिश्रा
लखनऊ ब्यूरो : हरिभजन शर्मा
विज्ञापन प्रबंधक - संजय सिंह
ग्राफिक डिजाइनर - अनमोल शुक्ल, अनिल मशालकर
फोटोग्राफर - हार्दिक रामगुड़े, राहुल पारकर

पत्राचार कार्यालय: आर - 2/608, आरएनए प्लाजा, निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प.), मुंबई - 400104

एनसीआर ब्यूरो : 748, वास्टो महागुन मॉडर्न, सेक्टर - 78, नोएडा - 201 305. सम्पर्क : 9167615266

लखनऊ ब्यूरो : 101, श्रद्धा विहार कॉलोनी, चिन्हट, लखनऊ - 226 028. सम्पर्क : 9452222370 / 8318252532

कृपा प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के लिए मुद्रक एवं प्रकाशक कृपाशंकर तिवारी द्वारा विनय ग्राफिक्स, युनिट नम्बर 13, रवि इंडस्ट्रियल प्रेमायसेस, महाकाली केव्स रोड, अन्धेरी (पूर्व), मुंबई - 400093 से मुद्रित एवं आर - 2/608, आरएनए प्लाजा, निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प.), मुंबई - 400104 से प्रकाशित।

सम्पादक : आलोक रंजन तिवारी
पंजीकृत कार्यालय: आर - 2/608, आरएनए प्लाजा, निकट आरएनए कॉर्पोरेट सेंटर, राम मंदिर रोड, गोरेगांव (प.), मुंबई - 400104

दूरभाष: 022 -26771428 / 9967718221 / 7800611428
ई-मेल: kst@avmagazine.co.in
वेबसाइट : www.avmagazine.co.in

पत्रिका में प्रकाशित सभी रचनाओं से सम्पादक की सहमति आवश्यक नहीं है। पत्रिका में प्रदर्शित समस्त पद अवैतनिक हैं। पत्रिका से संबंधित किसी भी विवाद का न्यायिक क्षेत्र मुंबई होगा।

साक्षात्कार
हमारे लिए सुरक्षा और विश्वास सबसे अनिवार्य विषय है : माथुर
पृष्ठ 38

आईटी
डेल की स्थापना की संक्षिप्त कहानी
पृष्ठ 46

आन्तरिक

उद्योग
व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रबल पक्षधर : रवि दोशी
पृष्ठ 52

समाचार
महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिए एक साल तक नहीं हो सकता इंतजार : सुप्रीम कोर्ट
पृष्ठ 57

20 भारत की वैश्विक छवि के नए शिल्पकार नरेन्द्र मोदी

विशेष आलेख

26
ई-रूपी से होगा वित्तीय जीवन आसान

42
रचनात्मक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं अनन्त माहेश्वरी

36
विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय आईटी कम्पनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

48
नवाचार, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय फिलिप्स इंडिया

सुरक्षा और विश्वास

आईटी क्षेत्र में निवेश के नये केंद्र बिंदु

आलोक रंजन तिवारी

अनेक समस्याओं के बाद भी इसमें कोई संदेह नहीं कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी ने एक नई आर्थिक – सामाजिक क्रांति को जन्म दिया है, जिसने विकास की प्रक्रिया को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है। सूचना प्रौद्योगिकी सामाजिक परिवर्तन का एक प्रभावशाली माध्यम है। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि सामाजिक परिवर्तन लाने में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी की अपनी कुछ सीमाएं हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने दुनिया की सम्पूर्ण कार्यप्रणाली के मूल स्वरूप को बदलने में बड़ी भूमिका अदा की है। आज शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार, प्रशासन, सरकार, उद्योग, अनुसंधान और विभिन्न क्षेत्रों की कार्यशैली में अहम बदलाव देखे जा रहे हैं। इन क्षेत्रों में काम करने के तरीके बदले हैं, कार्य निष्पादन में तीव्रता आयी है, पारदर्शिता का जन्म हुआ है और आधुनिक संसाधनों से सुसम्पन्न समाज विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।

कम्प्यूटर की खोज 20 वीं शताब्दी की सर्वाधिक महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक है। इस शताब्दी में आईटी क्रांति की शुरुआत हुई। सामाजिक परिवर्तन, प्रगति एवं विकास के साधन के रूप में सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की भूमिका व्यापक स्तर पर स्वीकार की गई और यह उम्मीद भी की गई कि इसके प्रयोग से मानव जीवन को बड़े सामाजिक और आर्थिक लाभ होंगे तथा विकास की प्रक्रिया में तेजी आयेगी और 21 वीं सदी में हम बेहतर समाज का गठन कर पायेंगे। लेकिन, मौजूदा दौर में तकनीक की दुनिया ने मानव समाज के समक्ष कई समस्याएं भी उत्पन्न कर दी है। आज सूचना (जिसे तकनीक की भाषा में डेटा कहा जाता है) का एक बड़ा व्यावसायिक साम्राज्य स्थापित हो गया है। लोगों की व्यक्तिगत सूचनाओं और जानकारियों के आधार पर व्यावसायिक कार्यशैली, उत्पादों की उपलब्धता और उसके प्रचार – प्रसार के तरीके तय किये जा रहे हैं। यह सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (कृत्रिम बुद्धिमत्ता) के कारण संभव हो पा रहा है।

डेटा का यह खेल बड़ा दिलचस्प है। जिन ऍप्लिकेशन्स की पहुँच हमारे मोबाइल – लैपटॉप तक है, वो हमारी जानकारियाँ इकट्ठा कर ऐसी कंपनियों या वाणिज्यिक निकायों को देते हैं, जो उन्हीं सूचनाओं के आधार पर ग्राहकों को अपने उत्पाद पेश कर भारी लाभ कमा रहे हैं। डेटा की चोरी ने मानव समाज की निजता को बुरी तरह प्रभावित किया है। यही कारण है कि हर जगह अब सिक्योरिटी (सुरक्षा) और ट्रस्ट (विश्वास) की बात होने लगी है। कोविड –19 महामारी के कारण डिजिटल माध्यम से अपने घरों से काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ने की वजह से साइबर हमलों और साइबर स्पेस में आपराधिक गतिविधियों में वृद्धि हुई है। महामारी के दौरान तमाम कंपनियों, उद्योग संगठनों और सरकारी संस्थानों ने इस दिशा में भारी निवेश किये हैं और अब सुरक्षा को लोग सर्वाधिक आवश्यक तत्व की दृष्टि से भी देख रहे हैं।

डिजिटल दौर में डेटा सिक्योरिटी आज की सबसे बड़ी जरूरत है। यही वजह है कि हर क्षेत्र में इसे लेकर सतर्कता बढ़ती जा रही है। मौजूदा डिजिटल युग में डेटा एक मूल्यवान संसाधन है, जिसे अनियमित नहीं छोड़ा जाना चाहिये। यह समय भारत के लिए एक मजबूत डेटा सुरक्षा कानून की दृष्टि से काफी महत्त्वपूर्ण है।

जिस तरह किसी भी राष्ट्र के विकास में सुरक्षित वातावरण का होना अधिक जरूरी होता है, उसी तरह सूचना प्रौद्योगिकी की दुनिया में सिक्योरिटी का होना भी जरूरी है। व्यक्तिगत सूचनाओं की चोरी होना निजता के उल्लंघन का एक बहुत बड़ा मुद्दा है। लेकिन, यह विषय अब सिर्फ एक व्यक्ति तक ही सीमित न होकर पूरे जन समुदाय, औद्योगिक निकायों, प्रशासनिक ढांचे और राष्ट्रीय सुरक्षा का विषय बन गया है। इसलिए, वर्तमान में इस क्षेत्र में भारी निवेश देखने को मिल रहा है। तकनीक पर हमारी निर्भरता तो है ही, चाहे आंशिक ही क्यों न हो। इसलिए, सुरक्षित कार्यप्रणाली का होना बहुत जरूरी हो गया है।

आज विश्व एक ऐसे दौर में है, जहां राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सुरक्षा पर बहुत अधिक निर्भर करेगी। इसलिए, साइबरस्पेस के इस्तेमाल हेतु शासी मानदंडों और ढांचे के निर्माण पर जोर देते हुए, रक्षात्मक और अति महत्वपूर्ण, आक्रामक साइबर क्षमताओं का निर्माण करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है। यही कारण है कि पूरी दुनिया में सिक्योरिटी (सुरक्षा) और ट्रस्ट (विश्वास) को लेकर तेजी से बात होने लगी है और लोग इस दिशा में सक्रियता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। व्यक्तियों या संस्थाओं को अपनी डाटा सुरक्षा हेतु केवल सरकार पर ही निर्भर नहीं रहना चाहिये बल्कि खुद भी जागरूक रहना चाहिये। अपने मीडिया उपकरणों की सुरक्षा सेटिंग को अपडेट रखने के साथ ही अच्छे एंटीवायरस का उपयोग और जाली संदेशों, लिंक और फ़ोनकॉल से सतर्क रहना चाहिये।

◆◆◆

PeaceGifts

Peace Mugs

Peace Fragrance

Peace Candies

Peace Frames

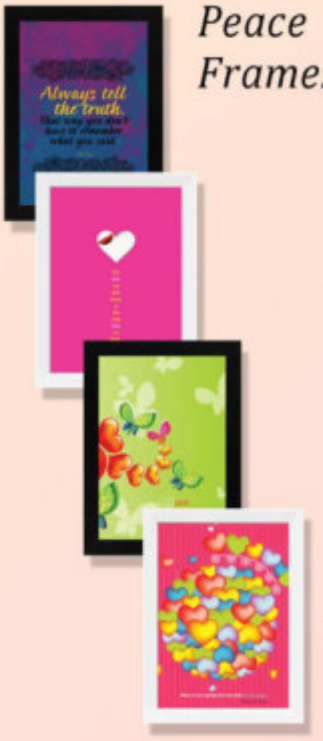

Peace Caps

Peace Watch

Peace T-shirts

Contact
Lamiya
+91 9167457769
lamiya@peacecafee.com

Or

Buy Online : **www.peacecafee.com**

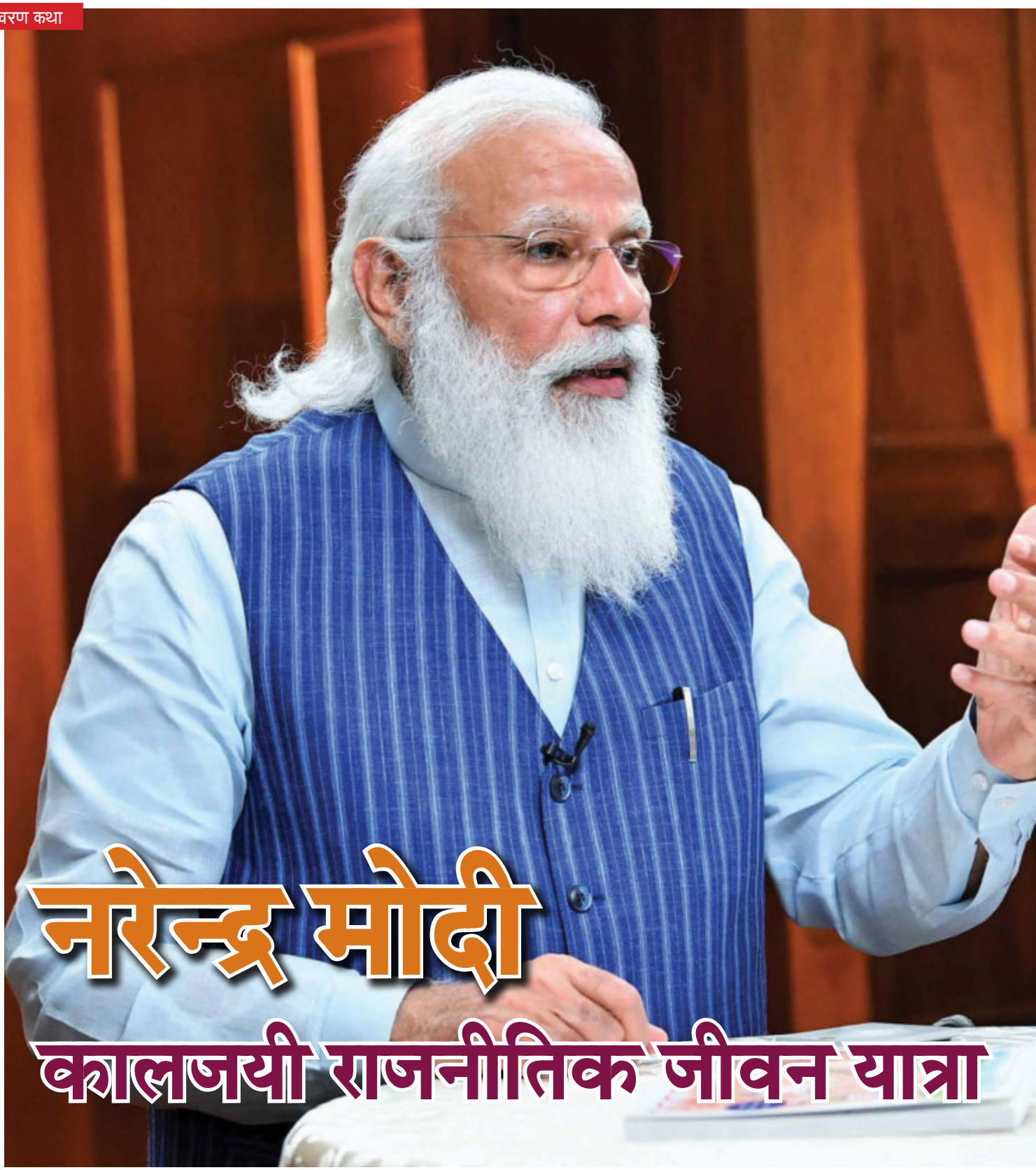

नरेन्द्र मोदी
कालजयी राजनीतिक जीवन यात्रा

मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को 'गुजरात मॉडल' के रूप में प्रस्तुत कर लगातार दो लोकसभा चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी लगभग अजेय रहे हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह किसी अचरज से कम नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता से देश के सर्वोच्च नेता की यात्रा प्रेरक भी है और राजनीतिज्ञों के लिए गुत्थी उलझाने वाला भी।

वर्तमान के चश्मे से देखें तो नरेन्द्र मोदी एक चमत्कार की तरह दिखते हैं। इनका व्यक्तित्व कुछ इस तरह उभरता है कि जिनके लिए सब कुछ बहुत आसान हो– चुनाव जीतना और देश के लिए विषय तय करना, जो जनता से जुड़ने का हुनर रखता है और विपक्ष को पटखनी देने की क्षमता भी। एक लंबी और सफल राजनीतिक विरासत जब मूर्त रूप लेती है तो ऐसी शख्सियत निर्मित होती है। हालाँकि, आज के इस जादू से थोड़ी दूर हटें तो नरेन्द्र मोदी की शुरुआत भी बहुत साधारण थी। खासकर, जिस विपक्ष से उनकी प्रतिस्पर्धा थी/है उसकी तुलना में नरेन्द्र मोदी के पास कुछ भी नहीं था। आइये, एकदम संक्षेप में उस घटनाक्रम को जानते हैं कि "कुछ नहीं से सब कुछ" की यह यात्रा कैसी रही।

आजादी के तीन बरस बीत चुके थे, जब 17 सितम्बर को नरेन्द्र मोदी का जन्म औद्योगिक राज्य गुजरात में हुआ। जगह थी वडनगर। एक बेहद साधारण पारिवारिक पृष्ठभूमि में नरेन्द्र मोदी का लालन–पालन हुआ और यही वजह है कि संघर्षों के सहारे एक बेहतर जीवन बुनने की उनकी जिजीविषा उनके व्यक्तित्व का सबसे मजबूत अंग बन गयी। कालांतर में उनकी रुचि राजनीति में बढ़ी और वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए। यह संयोग 70 के दशक में कभी घटित हुआ था। आने वाले कुछ वर्षों में भाजपा का भी गठन होना था और नरेंद्र मोदी का राजनीतिक सफर भाजपा तक आ पहुँचा। पहले गुजरात राज्य में संगठन को मजबूत करने, राज्य में चुनाव जिताकर सरकार बनाने में भूमिका निभाने और फिर केंद्रीय संगठन में आने की एक उत्तरोत्तर बढ़ती राजनीतिक हैसियत के साथ मोदी अपना कद ऊँचा करते गए। और फिर 21वीं सदी की शुरुआत में ही वो एक विभाजक समय भी आ गया, जिसने मोदी, भाजपा और भारतीय राजनीति का भाग्य उसी समय तय कर दिया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री चुने गए। मुख्यमंत्री के रूप में अपने कार्यों को 'गुजरात मॉडल' के रूप में प्रस्तुत कर लगातार दो लोकसभा चुनाव जीतने वाले नरेंद्र मोदी लगभग अजेय रहे हैं। अगर, प्रत्यक्ष नेतृत्व की बात करें तो वो अजेय ही रहे हैं। भारतीय राजनीति के संदर्भ में यह किसी अचरज से कम नहीं है। एक साधारण कार्यकर्ता से देश के सर्वोच्च नेता की यात्रा प्रेरक भी है और राजनीतिज्ञों के लिए गुत्थी उलझाने वाला भी। बहरहाल, अब यह देखना अधिक रोचक होगा कि आखिर नरेंद्र मोदी की यह यात्रा कैसे संभव हो सकी? वो कौन से कारक हैं जो इन्हें अपने प्रतिस्पर्धी नेताओं से अलग बनाते हैं?

वैचारिक स्पष्टता

नरेंद्र मोदी के नरेंद्र मोदी होने में जो एक बात बुनियादी रूप से कही जा सकती है वो है वैचारिक स्पष्टता। राजनीतिक विचार हो या सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा या फिर आर्थिक नीति, नरेंद्र मोदी शुरू से ही काफी स्पष्ट रहे हैं। और यही वजह है कि वो पूरे आत्मविश्वास से जनता से जुड़े और उनसे अपने लिए समर्थन मांगा। और, यह वैचारिक स्पष्टता क्या है?

सबसे पहले सांस्कृतिक मूल्यों के प्रति निष्ठा के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय राजनीति में भी संस्कृति के रोचक उपयोग होते रहे हैं, जिनमें सबसे सफल प्रयोग "सांप्रदायिकता–सेकुलरवाद" का है। धर्म के ही

– सन्नी कुमार

उपयोग पर ही दोनों प्रकार की राजनीति टिकी रही, लेकिन एक को सेकुलरवाद कहा गया और दूसरे को सांप्रदायिकता। यहाँ इस बात को ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि इन दोनों ही विचारों के व्यावहारिक (चुनावी) अनुप्रयोग इनकी सैद्धांतिक निर्मिति से एकदम अलग है। वस्तुत:, भारत में परस्पर विरोधी सांस्कृतिक मूल्यों के कारण पैदा हुई नैतिक असहमतियों का राजनीतिक हल खोजने की कभी कोशिश नहीं हुई। विविधता के नष्ट हो जाने के डर या बहुसंख्यक संस्कृति के हावी हो जाने के भय से यहाँ सामाजिक एकीकरण पर बहुत ध्यान नहीं दिया गया तथा सार्वभौम नागरिक निर्माण की परियोजना अधूरी ही रह गई। इसके अलावा वैविध्य बनाए रखने के लिए राज्य की तरफ से जो प्रयास हुए उसका एक संदेश यह भी गया कि जानबूझकर बहुसंख्यक की धार्मिक पहचान को बेअसर करने की कोशिश हुई और अल्पसंख्यक को अपनी पहचान धार्मिक रूप से गढ़ने के लिए न केवल छूट दी गई बल्कि प्रोत्साहित भी किया गया। इसी आधार पर हो रही राजनीति को नरेन्द्र मोदी ने बदला और पूरी निर्भीकता से खुद को उस खेमे में प्रस्तुत किया जिसे 'सांप्रदायिक' कहने का चलन है। यानी हिंदू धर्म के प्रति निष्ठा रखना, उसके प्रतीकों को सम्मान देना, इस समुदाय के आग्रह को राष्ट्रीय विषय बनाना आदि। अयोध्या में राम मंदिर के शिलान्यास से लेकर कश्मीर से अनुच्छेद-370 को प्रभावशून्य करने तक की यह यात्रा बहुत स्पष्ट रही है।

वैचारिक स्पष्टता का दूसरा पक्ष राजनीतिक–आर्थिक है। यह स्पष्टता और बेहतर ढंग से उभर सके इसलिए पहले इनकी प्रतिद्वंद्वी वर्तमान कांग्रेस का नजरिया देख लेते हैं। कांग्रेस कभी नेहरू –इंदिरा के समाजवाद के प्रति मोह दर्शाती है तो कभी राव– मनमोहन के पूंजीवाद के लाभ का श्रेय लेना चाहती है। दिलचस्प बात है कि 1990 में उदारवादी – पूंजीवादी व्यवस्था को पुरजोर तरीके से अपनाने में जिस मनमोहन सिंह की बड़ी भूमिका थी, वो नरेन्द्र मोदी के सत्ता में आने के पहले दस साल कांग्रेस की तरफ से नेतृत्व करते रहे, किंतु इसके ठीक बाद जिस राहुल गांधी के पास नेतृत्व आया वो समाजवाद का झंडा बुलंद करने की कोशिश करने लगे। चाहे संसद में नाम लेकर उद्योगपतियों की आलोचना करना हो या प्रधानमंत्री पर सूट बूट की सरकार होने का तंज कसना हो, राहुल गांधी खुलकर दूसरे खेमे में होने को दर्शाते रहे। वो भी तब जब राहुल जिस 'युवा कांग्रेस' के सहारे पार्टी की सूरत बदलना चाह रहे थे, उनमें से अधिकांश समाजवादी प्राप्ति की मरीचिका से ऊबे हुए लगते थे। इसके विपरीत नरेन्द्र मोदी एकदम स्पष्ट नजर आए। इन्होंने जनकल्याणकारी राज्य की धारणा से डिगे बिना समाजवादी नीति से चिपके रहने के संकोच को त्याग

दिया। नए समय के अनुकूल आर्थिक नीति जिसमें न्यूनतम शासन के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम, विदेशी निवेश के प्रति आकर्षण, विनिवेश, नागरिक उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने जैसी नीतियों के सहारे मोदी आगे बढ़े। ये सभी परंपरागत समाजवादी नीति से स्पष्ट विचलन के संकेत हैं। वस्तुत: नरेन्द्र मोदी ने खुद को एक ऐसे नेता के रूप में प्रस्तुत किया जो अपनी धार्मिक पहचान को लेकर किसी दुविधा में नहीं था। कश्मीर को शेष राष्ट्र से जोड़ने की कसम भी निभाई। न्यूजरूम से मंत्री बनाने का चलन खत्म किया, राजनीति को चंद अभिजनों के इशारे पर निर्देशित होने की परिपाटी मिटाई, देश को नई तकनीक के प्रति सहज होने का अभ्यास कराया, जन धन से लेकर उज्ज्वला तक तमाम ऐसे छोटे दिखने वाले बड़े उपाय किए।

कुशल संगठनकर्ता और नेतृत्व कौशल

नेतृत्व से आखिर हमारी क्या अपेक्षाएँ होती हैं? यही न कि वो कठिन समय में न केवल उचित निर्णय ले बल्कि दृढ़तापूर्वक डटे रहने का कौशल भी दिखाए! उसकी भंगिमा सकारात्मक हो। उसकी भाषा संयत हो। उसको साथ खड़ा होना आता हो। जोखिम लेने की प्रवृत्ति हो। जिसकी उपस्थिति उत्साहित करे और जो हार जीत को अपने बूते स्वीकार करने की क्षमता रखता हो। किसी संगठन का लीडर जितना कुशल, परिश्रमी और जोखिम उठाने वाला होता है वह संगठन भी उतना ही मजबूत हो जाता है। तमाम व्यावहारिक बातों के बावजूद नेतृत्व का एक अदृश्य प्रभाव होता है। अच्छे लीडर इस प्रभाव को और सघन कर देते हैं। और इस कसौटी पर देखें तो नरेन्द्र मोदी एकदम खरे उतरते हैं। देश की केंद्रीय सत्ता पर काबिज होने की लगातार कोशिशों के बाद भी ज्यादातर बार असफल ही रहे संगठन को जीत के लिए तैयार करना कोई साधारण बात नहीं। भाजपा भी 2004 और 2009 के लोकसभा चुनावों में हार के बाद काफी कुछ ऐसी ही निराशा महसूस कर रही थी। ऐसे में नरेन्द्र मोदी ने संगठन को जीत के लिए तैयार किया और कार्यकर्ताओं को आत्मविश्वास से भर दिया। इतना ही नहीं उन्होंने हर बार जीत-हार की जिम्मेदारी अपने ऊपर ली। चुनावी कोशिशों से अलग देखें तो उन्होंने राज्य के अन्य मूलभूत इकाइयों को भी राष्ट्रीय नेतृत्व से जोड़ा, चाहे वह इसरो का कोई अंतरिक्ष प्रयोग हो या फिर कोई सैन्य अभियान। यहाँ इस प्रसंग का जिक्र करना समीचीन होगा कि सीमा विवाद के समय प्रधानमंत्री के लेह जाने से कोई चमत्कार हो गया हो या फिर उससे सीमा तनाव क्षणभर में दूर हो गया हो, ऐसा नहीं है। किंतु, इन सब के बावजूद इस उपस्थिति में सीमा के दोनों पार के लिए एक संदेश था। सरहद के अंतर से संदेश की ग्राह्यता में अंतर जरूर आएगा लेकिन जो एक बात एकदम स्पष्ट थी वो यह कि प्रधानमंत्री अपने नागरिकों और सैनिकों के पक्ष में मुस्तैद है। दिल्ली और सेना के बीच एक दूरी होती है और वो होनी भी चाहिए, लेकिन एक सेतु भी हो जो एक दूसरे को जोड़े रखे। सिर्फ औपचारिक ही नहीं बल्कि भावनात्मक रूप से भी। प्रधानमंत्री को अपने बीच पाकर सेना का मनोबल निश्चय ही बढ़ा होगा। निर्णय लेने में मस्तिष्क और जुड़ने में हृदय का प्रयोग करना चाहिए। ये दोनों अपनी - अपनी जगह कायम रहे तो कोई भी दौड़ जीती जा सकती है। नरेंद्र मोदी ने ऐसा ही नेतृत्व देश को दिया है।

नरेंद्र मोदी ने भविष्य के भारत की ठोस बुनियाद तय कर दी है।

वस्तुत: नरेन्द्र मोदी आज केवल एक कुशल राजनेता ही नहीं हैं बल्कि उन्होंने भविष्य के भारत की ठोस बुनियाद भी तय कर दी है। "भारत गावों में बसता है" जैसे लोकप्रिय मुहावरे को वास्तविक रूप प्रदान करने के लिए आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना, नई तकनीकी दुनिया से कदमताल करने के लिए डिजिटल इंडिया का सपना, भ्रष्टाचार रहित शासन के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग और कैशलेस अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना, अंतरराष्ट्रीय मंचों पर भारतीय हितों को पूरे आत्मविश्वास से प्रस्तुत करने जैसे अनेक प्रयास हैं, जिनकी परिधि में आने वाला समय आकार लेगा। यह एक ऐसा समय है जब नरेंद्र मोदी एक प्रधानमंत्री के रूप में आने वाले समय को भी प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं और यही इनके कद को और बड़ा कर देता है। ◆◆◆

नए समय के अनुकूल आर्थिक नीति जिसमें न्यूनतम शासन के साथ मुक्त अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ते कदम, विदेशी निवेश के प्रति आकर्षण, विनिवेश, नागरिक उद्यमशीलता को प्रोत्साहित करने जैसी नीतियों के सहारे मोदी आगे बढ़े।

- राजीव चंद्रशेखर

Digital India
Power To Empower

डिजिटल इंडिया का सपना पूरा करने वाले प्रधानमंत्री

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कैशलैस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत किया जा सके।

वर्तमान में हम औद्योगिक क्रांति के चौथे चरण में प्रवेश कर रहे हैं जिसमें सूचना और संचार प्रौद्योगिकी अपनी मुख्य भूमिका में है। एक बेहतर संचार तंत्र और डिजिटल अर्थव्यवस्था के माध्यम से आज पूरी दुनिया आपस में जुड़ चुकी है। ऐसे में आज किसी भी देश की वास्तविक प्रगति के लिए आवश्यक है कि वह तकनीकी रूप से सहज,सक्षम और उन्नत हो। समय की इस अपरिहार्य आवश्यकता को अगर किसी व्यक्ति ने भली-भांति समझा है तो वह हैं हमारे दूरदर्शी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी। उम्र के इस पड़ाव में आकर भी तकनीक के प्रति जो लगाव व सहजता हमारे प्रधानमंत्री जी में है वह वास्तविक मायनों में एक बेहतर नेतृत्वकर्ता में ही हो सकती है। वे प्रौद्योगिकी के सर्वोत्तम उपयोग की बात करते हुए अक्सर सरकार के उन कदमों की ओर इशारा करते हैं जिसमें अत्याधुनिक तकनीक को

अपनाने से लेकर समाज में डिजिटल तकनीक को बढ़ावा देना शामिल है। उदाहरण के लिए नीति आयोग द्वारा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के लिए एक पर्यवेक्षण निकाय की स्थापना, उमंग और डिजिलॉकर ऐप के माध्यम से ई-गवर्नेंस को बढ़ावा देना, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने हेतु पीएलआई स्कीम, राष्ट्रीय सुपरकंप्यूटिंग मिशन और डिजिटल इंडिया कार्यक्रम जैसे महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। उनका कहना है कि पाषाण युग से औद्योगिक क्रांति तक आने में जहां लाखों वर्ष लग गए वहीं संचार क्रांति महज पिछले 200 वर्षों का परिणाम है जबकि डिजिटल क्रांति ने यह दूरी कुछ ही वर्षों में पूरी कर ली।

भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण में 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की पहल की है।

बदलाव की कहानी

प्रभाव के दृष्टिकोण से देखा जाए तो डिजिटल क्रांति ने आज हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित किया है। आज जो भी देश डिजिटल साक्षरता में जितना पीछे हैं वह प्रगति की रफ्तार में भी उतना ही धीमा है। इस तथ्य को भलीभांति समझते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने कैशलैस इकोनॉमी और डिजिटल इंडिया जैसे कार्यक्रम की शुरुआत की है ताकि भारत को डिजिटल रूप से एक सशक्त समाज और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था के रूप में परिणत किया जा सके। अब अगर बात डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की करते हैं तो यह मूलत: तीन दृष्टिकोण पर आधारित है -डिजिटल अवसंरचना का निर्माण, मांग आधारित ई गवर्नेंस सेवा और डिजिटल साक्षरता। यह कार्यक्रम नौ स्तंभों पर टिका हुआ है जो हैं ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल कनेक्टिविटी तक सार्वभौम पहुंच,पब्लिक इंटरनेट एक्सेस प्रोग्राम, ई-गवर्नेंस, ई-क्रांति:NeGP 2.0, सभी के लिए सूचना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण,रोजगार हेतु सूचना एवं प्रौद्योगिकी और अगली हार्वेस्ट प्रोग्राम, डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के तहत शिक्षा, अस्पताल समेत सभी स्वास्थ्य सेवाओं और सरकारी दफ्तरों को देश की राजधानी से जोड़ा जा रहा है। भारत सरकार ने डिजिटल इंडिया प्रोग्राम के पहले चरण में 2.5 लाख गांवों में ब्रॉडबैंड सेवा उपलब्ध कराने की पहल की है। साथ ही देश के प्रत्येक हिस्से में डिजिटल इंडिया का लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ढाई लाख से अधिक सामान्य सेवा केंद्रों का एक विशाल नेटवर्क सृजित किया गया है जिसने भारत के निर्धनों, हाशिए पर खड़े समूहों ,दलितों और महिलाओं के मध्य डिजिटल उद्यमियों का विकास किया है। इसी पहल का परिणाम है कि आज लोग लोग घर से काम करने, कैशलेस भुगतान पाने, छात्र ऑनलाइन शिक्षा पाने, मरीज टेली-कंसल्टेशन से डॉक्टरी सलाह लेने और किसान सीधे अपने बैंक खाते में पीएम-किसान जैसी योजना का लाभ लेने में सक्षम हो पाए हैं। यहीं पर हमें ई-क्रांति जिसे अन्य रूप में हम राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना 2.0 के नाम से भी जानते हैं, की बात कर लेना भी ज्यादा समीचीन होगा।

इस योजना का उद्देश्य परिवर्तनशील और परिणामोन्मुखी ई-गवर्नेंस पहलों को प्रोत्साहन देना, एकीकृत सेवाएं प्रदान करना तथा सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के इष्टतम उपयोग व नागरिक केंद्रित सेवाओं को बढ़ावा देना आदि शामिल है। इसके अलावा सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने कुछ अन्य एजेंसियों के माध्यम से डिस्ट्रीब्यूटर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन ब्लॉकचैन टेक्नोलॉजी जैसी बहु-संस्थागत परियोजना का भी समर्थन किया है जिसके माध्यम से शासन,बैंकिंग,वित्त,साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में ब्लॉकचेन आधारित अनुप्रयोगों को बढ़ावा देना व उनका विकास करना शामिल है। इसी तरह कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय द्वारा नैसकॉम की साझीदारी से फ्यूचर स्किल प्लेटफार्म को लांच किया गया है जो ब्लॉकचेन,कृत्रिम बुद्धिमत्ता सहित दस उभरती हुई तकनीकों पर केंद्रित है।

कहने का अर्थ यह है कि माननीय मोदी जी के दिशा निर्देशन में काम करते हुए प्रत्येक विभाग आधुनिक सूचना व प्रौद्योगिकी का बेहतर उपयोग व समन्वयन करते हुए इस क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात कर रहा है। यहां यह उल्लेख कर देना आवश्यक है कि भले ही सूचना व संचार प्रौद्योगिकी का प्रारंभ किसी भी सरकार के कार्यकाल में हुआ हो लेकिन उसे निरंतर नित नई ऊंचाइयों पर पहुंचाने का श्रेय निश्चित रूप से मोदी जी को जाता है। यहां हम कुछ मुद्दों पर गौर करें तो ये बातें और भी स्पष्ट हो जाती हैं।

तकनीक के सहारे गरीबों का भला करने की नीति

मोदी जी के आने से पहले अधिकांश भारतीय न्यूनतम बैंकिंग सेवाओं से भी वंचित थे। जो इन सेवाओं का लाभ उठा भी रहे थे उन्हें इसके लिए काफी कड़ी मशक्कत करनी पड़ती थी। ऐसे में कैशलेस इकोनॉमी तो और दूर की कौड़ी हुआ करती थी। लेकिन, मोदी जी के आगमन के बाद जहां इन कठिनाइयों ने सहजता का रूप लेना शुरू किया वहीं कैशलैस इकोनॉमी भी परिकल्पना से निकलकर यथार्थ के धरातल पर अवतरित हुई। अपने शपथ ग्रहण समारोह के कुछ ही महीनों बाद यानी 15 अगस्त, 2014 को मोदी जी ने विशाल जन-धन योजना के शुभारंभ की घोषणा की जिसके माध्यम से करोड़ों भारतीयों के बैंक खाते खुले और वे औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जुड़ने में समर्थ हो सके। हालांकि, शुरुआत में विरोधियों द्वारा इन खातों में जमा हुई न्यून राशि को आधार बनाकर मोदी सरकार का उपहास भी उड़ाया गया किंतु कोविड-19 महामारी के दौरान जब आवागमन और कामकाज पूरी तरीके से ठप्प पड़ गए थे तब इन्हीं बैंक खातों में विभिन्न माध्यमों और लोगों द्वारा अंतरित की गई राशि ने निर्णायक भूमिका अदा की। ठीक यही बात मोदी जी के वृहद सपने कैशलेस अर्थव्यवस्था पर भी लागू होती है। एक पल के लिए हम समय में पीछे जाएं और यह विचार करें कि अगर कोविड-19 के दौरान हमारे पास भुगतान का कैशलेस विकल्प नहीं होता तो हम किस प्रकार अपनी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ा पाते। दुनिया हमारा उपहास उड़ाती और हमारी भूखों मरने की नौबत आ जाती। किंतु मोदी जी की दूरदृष्टि की बदौलत हम उस नारकीय अवस्था में नहीं गए। अपने कार्यकाल की शुरुआत से ही जिस तरह से उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी एवं डिजिटल क्षेत्र के विकास व विस्तार पर अपना ध्यान केंद्रित किया वह

समग्र रूप से कहा जाए तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था समय की मांग थी जिसे मोदी जी ने ना केवल बखूबी समझा बल्कि उसे आम जनमानस के बीच प्रचारित व प्रसारित भी किया।

स्वयं में काबिले तारीफ है।

आज बैंकिंग,पेंशन, बीमा और सब्सिडी आदि का निपटारा चंद मिनटों में ऑनलाइन हो जा रहा है। एक बड़े दुकानदार से लेकर साधारण फेरीवाले तक के पास यूपीआई के माध्यम से भुगतान प्राप्त करने की सुविधा है। बच्चे घर बैठे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं और किसान टेलीविजन अथवा अन्य डिजिटल माध्यमों से फसलों और मौसम की जानकारी प्राप्त कर पा रहे हैं। इसके अलावा भी अनेक ऐसे कार्य हैं जिनके लिए पहले घर के बाहर जाना पड़ता था किंतु अब नहीं। इसका सबसे ज्यादा फायदा बुजुर्गों को तो हुआ ही साथ ही उन समूहों को भी हुआ जो सरकारी कार्यालयों तक पहुंच पाने में सक्षम नहीं थे।

समग्र रूप से कहा जाए तो सूचना एवं प्रौद्योगिकी और डिजिटल अर्थव्यवस्था समय की मांग थी जिसे मोदी जी ने ना केवल बखूबी समझा बल्कि उसे आम जनमानस के बीच प्रचारित व प्रसारित भी किया। भारत जैसे विकासशील और विशाल जनसंख्या वाले देश में जहां अभी भी व्यापक पैमाने पर गरीबी,भुखमरी व कुपोषण पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है वहां अत्याधुनिक संचार व तकनीकी व्यवस्था का विकास करना काफी दुरूह एवं जटिल कार्य था। इसके लिए एक ऐसे नेता की आवश्यकता थी जिनके पास भविष्य को लेकर एक सुस्पष्ट दृष्टिकोण हो और जो वैश्विक परिवर्तनों के प्रति पहले से ही सचेत एवं तैयार हो। मोदी जी ने इन बातों का ध्यान रखते हुए विभिन्न प्रयासों एवं माध्यमों से लगातार जनमानस को इन परिवर्तनों को अपनाने के प्रति जागरूक व विवेकशील बनाया और इसी का परिणाम है कि आज हम वैश्विक अर्थव्यवस्था की कतार में अग्रणी स्थान धारण करते हैं। फिर चाहे वह अंतरिक्ष क्षेत्र हो,साइबर क्षेत्र हो,रक्षा क्षेत्र हो अथवा अन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्र, हमने कई बार वैश्विक समूहों को भी अपनी अभूतपूर्व प्रगति के माध्यम से अचंभे में डाल दिया है। ◆◆◆

(लेखक केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री हैं)

aarav®

Global Products & Services Pvt. Ltd.

Digitize | Innovate | Optimize | Accelerate

End to End Customized solutions to meet your specific business needs

ABOUT US

A trusted technology partner operating worldwide, Aarav Global Products & Services Private Limited is an end-to-end software solution provider. We focus on delivering smart, next-generation enterprise solutions to help businesses overcome challenges and meet their goals.

OUR SERVICES

- BUSINESS INTELLIGENCE AND VISUALIZATION

- OFFSHORE DEVELOPEMENT CENTRE
- PORTAL & MOBILE APPS

- INFRASTRUCTURE MANAGEMENT
- LOW CODE APPLICATION DEVELOPMENT

- WORKFORCE SERVICES
- APPLICATION MODERNIZATION

WHY CHOOSE US

- Reliable Support
- On-time delivery
- Long term partnership
- Trust Advisor
- Affordable costing
- End-to-End services

ISO 9001 | ISO 27001 | CMMI Level 5

visit us: www.aaravsoftware.com

विश्व नेता नरेन्द्र मोदी

सोम प्रकाश

आज विश्व मंच पर भारत को एक विशेष दृष्टि से देखा जाने लगा है। भारत के कुशल व प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी स्पष्ट, पारदर्शी एवं विश्व हितैषी विचारधारा एवं कार्यों से न केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित किया बल्कि विश्व समुदाय के लिए नेतृत्व के स्तर पर स्वयं में एक आश्वासन के रूप में सामने आए हैं।

राष्ट्रीय राजनीतिक क्षितिज पर राष्ट्र नायक के रूप में नरेन्द्र मोदी के अभ्युदय की अनिवार्यता एक निर्विवाद तथ्य सिद्ध हुआ। देश के सुयोग्य, कर्मठ एवं दूरदर्शी प्रधानमंत्री के रूप में नरेन्द्र मोदी की अब तक की सेवाएँ भारत को द्रुतगति से राष्ट्रीय विकास पथ पर अग्रसर करने में न केवल वरदान सिद्ध हो रही हैं अपितु सम्पूर्ण देश में विकास, सुरक्षा, स्वच्छ शासन–व्यवस्था तथा जन कल्याणकारी कार्यों के माध्यम से सरकार ने भारतीय जनमानस में एक विश्वास एवं आश्वस्ति के भाव का निर्माण करने में भी सफलता प्राप्त की है। नरेन्द्र मोदी के रूप में देश को दूरदृष्टि सम्पन्न एवं वीरव्रती भाव से राष्ट्र सेवा करने वाला राष्ट्रीय प्रहरी प्राप्त हुआ है, जो भारत को उसकी गरिमा के अनुरूप योग्य शासन व्यवस्था एवं दिशा देने में सर्वथा सक्षम है। दृढ़ विचार, स्पष्ट लक्ष्य एवं दूरदर्शितापूर्ण सोच का मोदी के महान व्यक्तित्व के गठन में महत्वपूर्ण योगदान है। लक्ष्य के प्रति सम्पूर्णतया समर्पण, प्रखर पुरुषार्थ तथा अनथक परिश्रम उनके व्यक्तित्व का महनीय गुण है जो विरले लोगों में ही पाया जाता है। प्रधानमंत्री के रूप में उनके उत्कट प्रयास हमें भारत के गौरवशाली अतीत की याद दिलाते हुए माँ भारती की सेवा में सर्वस्व समर्पित करने हेतु महान प्रेरणा प्रदान करते हैं।

भारतीय जनता पार्टी सहित करोड़ों देशवासियों को अपने राष्ट्र नायक पर गर्व है और विश्वास है कि प्रधानमंत्री का दूरदर्शी नेतृत्व भारत का सर्वांगीण विकास करने में पूर्णतया समर्थ है, सुयोग्य है। दीर्घावधि के बाद देश को ऐसा राष्ट्र नायक मिला है जैसा देश को चाहिए था, जैसी देशवासियों की अपेक्षा थी। नरेन्द्र मोदी के विश्वसनीय एवं चमत्कारिक नेतृत्व में भाजपा को दूसरी बार प्राप्त हुआ प्रचंड जनादेश मोदी जी के सुयोग्य नेतृत्व के प्रति देश के उत्कट विश्वास और लोकप्रियता का परिचायक है। प्रधानमंत्री के रूप में उनकी कर्मठ सेवाएँ भारत को विकास एवं खुशहाली के पथ पर तीव्रगति से अग्रसर करते हुए शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। मोदी सरकार के अब तक के कार्यकाल में हम गर्व के साथ कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार की एक भी छोटी या बड़ी घटना नहीं हुई, कहीं भी किसी भी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं हुआ, इसे आप क्या कहेंगे? ऐसा कैसे संभव हुआ? वास्तविकता यह है कि मोदी सरकार की पारदर्शी नीतियाँ, जवाबदेह व ईमानदार शासन, राष्ट्रीय हितों के प्रति पूर्णतया समर्पण की उत्कट भावना और सबका साथ– सबका विकास के मंत्र के साथ सरकार की सुव्यवस्थित व कर्मठ कार्य प्रणाली ही सबसे बड़ी विशेषता है, जिसके कारण देश को भ्रष्टाचार मुक्त शासन प्रदान करना सम्भव हुआ। नरेन्द्र मोदी के विलक्षण नेतृत्व में भारत की आर्थिक स्थिति अपेक्षानुरूप सुदृढ़ हुई है और आज भारत को विश्व में सबसे तीव्र गति से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था के रूप में देखा जाने लगा है।

मोदी सरकार की अनेक राष्ट्र कल्याणकारी कार्यक्रम एवं योजनाएँ राष्ट्रीय जनजीवन को खुशहाल बनाने के साथ– साथ आम जनता के जीवन स्तर में सकारात्मक रूप से परिवर्तन ला रही हैं, सुधार ला रही हैं, देश को सुदृढ़ बना रही हैं। मोदी सरकार ने राष्ट्र कल्याणकारी नीतियों, कार्यक्रमों एवं योजनाओं के माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करने की दिशा में अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए। स्वच्छ भारत अभियान, नमामि गंगे, डिजिटल इंडिया, स्टैण्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया, आदर्श सांसद ग्राम योजना, प्रधानमंत्री जीवन बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, जन धन योजना, आयुष्मान भारत, आत्मनिर्भर भारत, अटल पेंशन योजना तथा अन्य अनेक महत्वपूर्ण योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से केन्द्र में सत्तारूढ़ मोदी सरकार देश का चहुंमुखी विकास करने का गंभीर प्रयास कर रही है।

आज विश्व मंच पर भारत को एक विशेष दृष्टि से देखा जाने लगा है। भारत के कुशल व प्रभावशाली नेतृत्व के रूप में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अपनी स्पष्ट, पारदर्शी एवं विश्व हितैषी विचारधारा एवं कार्यों से न केवल अंतर्राष्ट्रीय जगत को प्रभावित किया बल्कि विश्व समुदाय के लिए नेतृत्व के स्तर पर स्वयं में एक आश्वासन के रूप में सामने आए हैं। वास्तव में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी जब भी किसी अन्य देश में जाते हैं, भारत के प्रधानमंत्री से अधिक विश्वनेता प्रतीत होते हैं। डोकलाम मुद्दे को सुलझाना उनकी कूटनीतिक एवं राजनीतिक सूझ–बूझ का परिचायक है। भारत विश्व गुरू रहा है और वसुधैव कुटुम्बकम् की महान भावना हमारी सनातन संस्कृति एवं विश्व धर्म रहा है। आज भारत के प्रधानमंत्री की विलक्षण नेतृत्व क्षमता– दृष्टि– शैली को देखकर सुखद आश्चर्य होता है कि भारत वैश्विक जन – जीवन में एक बार फिर अपने प्राचीन गुरुत्तर दायित्व के निर्वहन हेतु तैयार है। ◆◆◆

(लेखक केन्द्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री हैं)

- दिनेश चौधरी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कुशल नेतृत्व में

देश का समावेशी विकास

पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सरकार ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, जिससे देश का विकास भी हुआ है और वह विकास देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों व सभी व्यक्तियों तक पहुँचा भी है।

समावेशी विकास एक अवधारणा के रूप में बहुत विशद् और व्यापक है। इसके सभी आयामों को समग्रता से समझना बेहद कठिन है और इससे भी कहीं अधिक कठिन है वास्तविक अर्थों में समावेशी विकास को मूर्त रूप दे पाना। मई 2014 में जब देश की जनता ने तीस वर्षों में पहली बार किसी राजनीतिक दल को लोकसभा में पूर्ण बहुमत के रूप में जनादेश दिया तो इस जनादेश के नायक भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के हाथों में देश को आर्थिक बदहाली, निर्धनता और असंतुलित विकास के दुश्चक्र से निकालने का दायित्व भी आया। यह अब सर्वज्ञात है कि 2014 से ठीक पहले के कुछ महीनों में देश पॉलिसी पैरालाइसिस की स्थिति में बुरी तरह फंस गया था और इस निराशा से देश को निकालने हेतु विकास से बेहतर कोई माध्यम नहीं हो सकता था। चुनौती केवल इतनी सी थी कि यह विकास पहले की तरह किसी एक क्षेत्र, किसी एक सेक्टर या किसी एक वर्ग के पक्ष में झुका हुआ न हो बल्कि सब तक पहुँचे और समानता के साथ पहुँचे। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने इस चुनौती से बखूबी पार पाते हुए और "सबका साथ – सबका विकास" के नारे को वास्तविकता में बदलते हुए विकास को समावेशी बनाया है और देश के कोने-कोने तक इसकी डिलीवरी सुनिश्चित करवाई है।

प्रधानमंत्री के रूप में अपने पहले स्वतंत्रता दिवस भाषण में मोदी जी ने वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए जन-धन योजना की घोषणा की। तब तक देश के जनसाधारण को शायद ही एक बैंक खाता होने की महत्ता का आभास रहा हो, परंतु इस योजना के अंतर्गत करोड़ों शून्य बचत बैंक खाते खोले गए और स्वतंत्रता के बाद पहली बार वास्तविक अर्थों में बैंकिंग व्यवस्था को जन-जन तक पहुँचाया जा सका। देश में सभी का बैंक खाता होने का ही लाभ बाद में तब मिला जब गैस सिलेंडर पर मिलने वाली सब्सिडी को बीच की सभी जटिलताएँ समाप्त करते हुए सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में भेजा जाने लगा। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण की इस नीति का बाद में कई तरीकों से लोगों तक प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ पहुँचाने के लिए किया गया। यहाँ तक कि कोरोना वायरस से उपजी विभीषिका के दौरान सरकार इसीलिए सहजता से लोगों की सहायता करने में सक्षम हो पाई क्योंकि उनके पास बैंक खाते मौजूद थे और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण का सुचारु तंत्र पहले ही स्थापित किया जा चुका था। जन-धन योजना के तहत लोगों के बैंक खाते खुलवाए जाना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ऐसा पहला बड़ा कदम था, जिसने समावेशी विकास को लक्षित किया और सफलता से इसे प्राप्त भी किया। साथ ही, यह आगे आने वाली अनेक समावेशी विकास पहलों का प्रस्थान बिंदु भी बना और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तथा प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी पहलों के माध्यम से देश के दूरस्थ वंचित वर्गों तक वे सुविधाएँ पहुँचाई गईं, जो पिछले 74 वर्षों में ऐसी तीव्रता और सफलता के साथ कभी नहीं पहुँचाई जा सकी थीं।

ऐसा भी नहीं कि सरकार के विकास कार्य सामाजिक कल्याण तक ही सीमित रहे, बल्कि सरकार ने सर्वांगीण व समावेशी रूप से प्रयास करते हुए सभी क्षेत्रों में विकास सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। डिजिटल इंडिया अभियान ऐसे ही एक प्रयास के उदाहरण के रूप में गिना जा सकता है। 2014 से पूर्व भारत में इंटरनेट केवल कुछ शहरों तक सीमित था और काफी महंगा हुआ करता था, जिससे यह आम भारतीय की पहुँच से बहुत दूर चला जाता था। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में सरकार द्वारा भारत को डिजिटलीकरण की राह पर ले जाने का प्रभाव आज देश के गाँव-गाँव में हर व्यक्ति तक इंटरनेट की पहुँच के रूप में दिखता है और डिजिटलीकरण को अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रकों (विशेष रूप से भुगतान) से जोड़ने के चलते आर्थिक विकास को भी समावेशी बना पाना संभव हुआ। और आज कहीं भी डिजिटल भुगतान की सुविधा देखकर यह अंदाजा लगाना बेहद आसान है कि इस पहल का जमीनी स्तर पर कितना व्यापक प्रभाव हुआ है।

महिलाओं के संदर्भ में विशेष रूप से बात की जाए तो 15 अगस्त, 2014 को ऐसा पहली बार देखा गया कि भारत के प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से खुले में शौच की समस्या को संबोधित करते हुए स्वच्छ भारत बनाने की बात की। यह समस्या देश के ग्रामीण इलाकों में विशेष तौर पर महिलाओं की अस्मिता से जुड़ती थी और आज जब लगभग समूचा देश खुले में शौच से मुक्त हो गया है तो इससे महिला सशक्तीकरण की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण प्रगति हुई है। वहीं दूसरी ओर "बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ" योजना और "सेल्फी विद डॉटर" जैसे अभियानों से देश में लिंगानुपात की बदहाल स्थिति को सुधारने की दिशा में निर्णायक प्रगति हुई है और शनैः-शनैः इसके सकारात्मक परिणाम भी देखे जा रहे हैं। मुस्लिम महिलाओं को फौरन तलाक के खतरे से बाहर निकालने हेतु तीन तलाक का अपराधीकरण किए जाने से अल्पसंख्यक महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में भी महत्त्वपूर्ण सफलता हासिल हुई है और स्टैंड अप इंडिया जैसी योजनाओं से वंचित वर्गों की महिला उद्यमियों को अपने और देश के विकास में भूमिका निभाने के अभूतपूर्व अवसर दिए जा रहे हैं। हाल में जब टोक्यो ओलंपिक व पैरालंपिक खेलों में भारत की बेटियों ने सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित किए तो उनकी सफलता में देश की सभी महिलाओं की सफलता व प्रधानमंत्री श्री मोदी द्वारा महिलाओं के समावेशी विकास हेतु उठाए गए कदमों का महत्त्व प्रतिबिंबित हो रहा था।

भारत अनेक कारणों से अब तक बहुत बड़ा विनिर्माण हब नहीं बन पाया है। इस बात की ओर कोरोना काल में अधिक ध्यान गया जब यह लगा कि सारा विश्व विनिर्माण के लिए चीन पर निर्भर नहीं रह सकता है और विनिर्माण चेनों का

जन-धन योजना के तहत लोगों के बैंक खाते खुलवाए जाना प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली सरकार का ऐसा पहला बड़ा कदम था, जिसने समावेशी विकास को लक्षित किया और सफलता से इसे प्राप्त भी किया।

वितरण अन्यत्र किया जाना आवश्यक है। ऐसे में भारत का नाम दुनिया की नई फैक्ट्री बनने के दावेदारों में सबसे आगे रहा। इसके पीछे भी मोदी सरकार की पिछले सात वर्षों की दूरदर्शी नीतियाँ जिम्मेदार हैं। कार्यभार संभालते ही प्रधानमंत्री ने 'मेक इन इंडिया' पहल की घोषणा की और विश्व को भारत में विनिर्माण करने व यहाँ निवेश करने हेतु आमंत्रित किया। और उन्होंने इसे कोई खोखला वादा नहीं बनने दिया बल्कि अपनी सरकार के अनेक प्रयासों के माध्यम से भारत में निवेश व निर्माण को सुगम बनाया। इन्हीं प्रयासों के फलस्वरूप भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में कई स्थानों की छलांग लगाते हुए 63वें स्थान तक पहुँच गया और विश्व के एक प्रमुख विनिर्माण व व्यापार बाजार के रूप में उभरा। इसके बाद हाल ही में क्रांतिकारी श्रम सुधारों के माध्यम से सैंकड़ों श्रम कानूनों को चार प्रमुख श्रम संहिताओं में समायोजित करते हुए उन्हें श्रमिकों व व्यवसायियों दोनों के लिए परस्पर हितकारी बनाया गया। इसी क्रम में 2020 में ही कृषि क्षेत्र में ऐतिहासिक सुधार करते हुए कृषकों को मंडी व बिचौलियों की जंज़ीरों से मुक्त किया गया और महत्त्वपूर्ण कृषि कानूनों के माध्यम से भारतीय किसान को मुक्त बाजार से जोड़ने और कृषि को लाभ का सौदा बनाने की दिशा में एक युगांतरकारी कदम उठाया गया। इन कानूनों से पहले भी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों की आय 2022 तक दुगुनी करने, उन्हें सीधे आर्थिक लाभ पहुँचाने, सिंचाई अवसंरचना दुरुस्त करने और किसानों को संधारणीय उर्वरक उपलब्ध कराने की पहलों से किसानों की स्थिति पहले की तुलना में आज कहीं अधिक बेहतर है और आज भारत में लोग कृषि केवल विवशता के चलते ही नहीं कर रहे, बल्कि इससे होने वाले लाभ भी उठा रहे हैं।

पिछले सात वर्षों में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के यशस्वी नेतृत्व में भारत सरकार ने ऐसे अनेक कदम उठाए हैं, जिससे देश का विकास भी हुआ है और वह विकास देश के सभी भौगोलिक क्षेत्रों व सभी व्यक्तियों तक पहुँचा भी है। वास्तव में इसे ही समावेशी विकास माना जाता है। इन विकास कार्यों का सबसे बड़ा प्रतिफल 2019 के चुनाव में और बड़े जनादेश के रूप में मिला, जिसके बाद यह पूर्ण विश्वास से कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के विकास कार्यों का समग्र समर्थन देशवासियों द्वारा किया जा रहा है। सरकार के अब तक के कार्यकाल में इतने महत्त्वपूर्ण विकास कदम उठाए गए हैं कि उन सब को गिनाने में भी शब्द सीमा का कई बार उल्लंघन हो जाएगा। लेकिन समग्रत: एक बात समझना बहुत महत्त्वपूर्ण है कि भारत बीते सात दशकों के अधिकांश भाग में विकास से उतना वंचित नहीं रहा जितना वह विकास के असंतुलित और असंगत वितरण से पीड़ित रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने इस प्रवृत्ति में निर्णायक बदलाव करते हुए अपने अब तक के कार्यकाल में विकास को अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति तक पहुँचाया है। यही सही मायनों में विकास के समावेशी होने का द्योतक है। अभी भी देश के समक्ष विकास की असीमित संभावनाएँ मौजूद हैं। कोरोना महामारी ने प्रगति को काफी हद तक बाधित किया है और इससे उबरने का भी सबसे बेहतर रास्ता समावेशी विकास के जरिए ही निकलेगा। यह हमारा सौभाग्य है कि इतिहास के ऐसे निर्णायक क्षण में देश का नेतृत्व ऐसे सही व्यक्ति के हाथ में है जिसके कुशल नेतृत्व में देश सभी बाधाओं को पार करते हुए प्रगति के नवीन प्रतिमान स्थापित करता रहेगा। ◆◆◆

(लेखक केराकत विधानसभा क्षेत्र, जौनपुर, उत्तर प्रदेश से भाजपा विधायक तथा राष्ट्रीय रजक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं)

FLF
FUTURE LIFESTYLE FASHIONS

*Terms & Conditions Apply.

KARMA

200 BEST BRANDS | 20%-70% OFF | SALE 365 DAYS

BRAND FACTORY

BEST BRANDS ▸ SMART PRICES

SKECHERS | Levi's | Lee Cooper | Buffalo | W | VanHeusen | United Colors of Benetton | U.S. Polo Assn. | Gini & Jony | Peter England

23 CITIES. 55 STORES

www.brandfactoryonline.com | brand factory | CUSTOMER CARE NO.: 18002101888

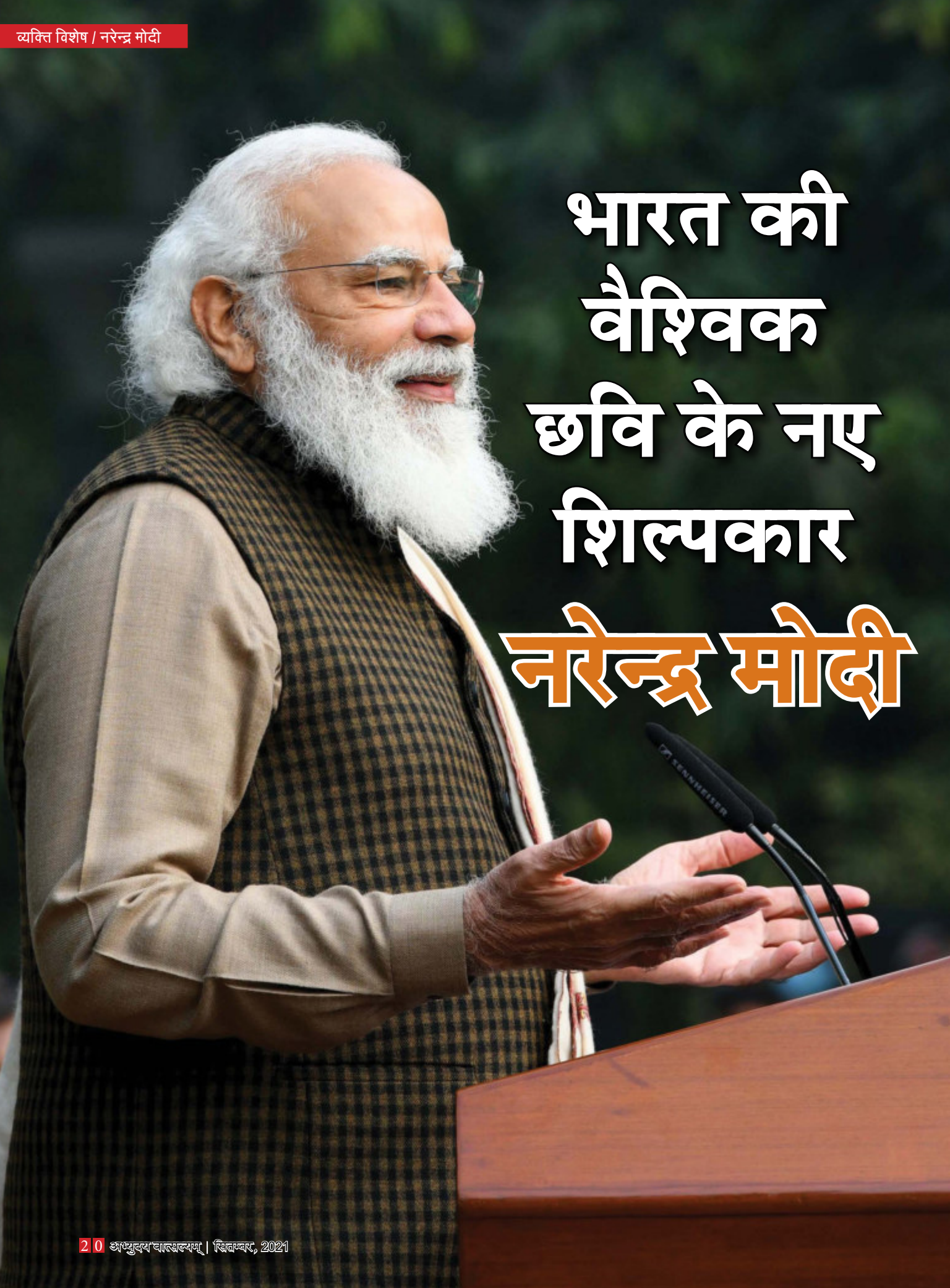

भारत की वैश्विक छवि के नए शिल्पकार नरेन्द्र मोदी

- एड.अखिलेश चौबे

प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है।

साल वर्ष के ऐतिहासिक कालखंड में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वैश्विक स्तर पर भारत की सफलता और साख के नए कीर्तिमान गढ़े हैं। उन्होंने जहाँ एक ओर अपनी सफल कूटनीति से अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, जापान और रूस सरीखे ताकतवर देशों को अपना मुरीद बनाया है वहीं चीन और पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मोर्चे पर करारी पटकनी दी है। किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति को प्रभावित करना अथवा अपने अनुकूल बनाना आसान नहीं होता। लेकिन, प्रधानमंत्री मोदी ने यह कमाल कर दिखाया है। पड़ोसी देशों की बात करें तो बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाइलैंड से भारत के संबंध प्रगाढ़ हुए हैं। अभी चंद माह पहले प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश की आजादी के 50 साल पूरे होने के अवसर पर यात्रा कर दोनों देशों के ऐतिहासिक व सभ्यतागत संबंधों को मिठास से भर दिया। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर सहमति बनी जो कि संपर्क, ऊर्जा, व्यापार, स्वास्थ्य और विकास के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पहली बार सत्ता संभाली तो सबसे पहले भूटान की यात्रा की। तब उन्होंने "भारत के लिए भूटान और भूटान के लिए भारत" की जरुरत बताकर दोनों देशों के अटूट रिश्तों को सहेजने की कोशिश की। उन्होंने भूटानी संसद के माध्यम से भूटान को भरोसा दिया कि दोनों देशों के रिश्ते पहले से अधिक प्रगाढ़ होंगे। 2019 में जब उन्होंने प्रधानमंत्री पद की दोबारा शपथ ली तब बिम्सटेक देशों के नेताओं को अपने शपथ समारोह में आमंत्रित किया और उसमें भूटान के प्रधानमंत्री लोते शेरिंग भी शामिल थे। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत के छोटे भाई सरीखे नेपाल के साथ संबंधों को नया आयाम दिया है। उन्होंने अपनी नेपाल यात्रा के दौरान जनकदुलारी मां सीता की पावन जन्मस्थली जनकपुर स्थित जानकी मंदिर में दर्शन-पूजन कर दोनों देशों की धार्मिक-सांस्कृतिक विरासत को सहेजने की पहल की। तब उन्होंने कहा था कि वह बतौर प्रधानमंत्री नहीं बल्कि मुख्य तीर्थयात्री बनकर आए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के दिल से निकला यह उद्गार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त है कि नेपाल भारत के दिल में बसता है और भारत उसके सुख-दुख का साथी है। प्रधानमंत्री मोदी ने धार्मिक-सांस्कृतिक संबंधों से इतर दोनों देशों की उन्नति के लिए एक नई परिकल्पना 5-टी यानी ट्रेडिशन (परंपरा), ट्रेड (व्यापार), टूरिज्म (पर्यटन), टेक्नोलॉजी (तकनीक), और ट्रांसपोर्ट (परिवहन) के क्षेत्र में मिलकर काम करने की वकालत की और नेपाल ने भी सहमति जतायी। प्रधानमंत्री मोदी ने श्रीलंका का भी दिल जीता है और आज की तारीख में दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामरिक और आर्थिक कारोबार को नई ऊंचाई मिल रही है। पड़ोसी देशों से इतर प्रधानमंत्री मोदी की पहल से मध्य एशिया और यूरोप से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी के प्रयास से मध्य एशिया में भारत की भू-राजनीतिक स्थिति लगातार मजबूत हो रही है। व्यापार, ऊर्जा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण और सुरक्षा क्षेत्र को नया पंख लग रहा है। नियमित आदान-प्रदान, यात्राएं, विचार-विमर्श, सैन्यकर्मियों का प्रशिक्षण, सैन्य तकनीकी सहयोग तथा संयुक्त अभ्यास जैसे कार्यक्रमों को बढ़ावा मिल रहा है। उम्मीद है कि प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीति से मध्य एशिया के देशों से व्यापार, निवेश, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य सुविधाओं, कृषि, सूचना एवं संचार प्रौद्यागिकी के क्षेत्र में भारत को पैठ बनाने में मजबूती मिलेगी। मध्य एशिया से संबंधों की बेहतरी इसलिए भी आवश्यक है कि यह एक बहुत बड़ा उपभोक्ता बाजार है। इस क्षेत्र में भारत के लिए स्वयं को स्थापित करने का बड़ा अवसर है। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक प्रयास से मुस्लिम देशों से भी बेहतर संबंध स्थापित हुए हैं। याद होगा 2019 में संयुक्त अरब अमीरात के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी

को यूएई के सर्वोच्च नागरिक सम्मान "ऑर्डर ऑफ जायद" से नवाजा। यह भारत के लिए गर्व का क्षण था। क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने तब प्रधानमंत्री मोदी को भाई बताया था और 'अपने दूसरे घर' आने के लिए आभार जताया। तब प्रधानमंत्री ने अबू धाबी में व्यापार जगत के प्रवासी भारतीयों को संबोधित कर जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद स्पष्ट किया और साथ ही भारतीय रूपे कार्ड को भी लांच किया। इस तरह पश्चिम एशिया में यूएई पहला देश बन गया जहां रूपे कार्ड चलता है। सऊदी अरब से भी भारत के संबंध मजबूत हुए हैं। याद होगा पुलवामा हमले के दोषियों को सजा दिलाने की भारत की मुहिम को दुनिया भर में मिल रहे समर्थन के बीच फरवरी 2019 में भारत यात्रा पर आए सऊदी अरब के युवराज ने भी भारत के साथ कंधा जोड़ने का वादा किया। जबकि यह सच्चाई है कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच गहरी निकटता है। वैश्विक मसलों पर अमूमन दोनों का सुर एक जैसा रहता है। लेकिन, इसके बावजूद भी सऊदी अरब का आतंकवाद के मसले पर भारत का समर्थन बदलते वैश्विक परिदृश्य में प्रधानमंत्री मोदी की बढ़ती महत्ता और सकारात्मक कूटनीतिक विजय का ही नतीजा है। प्रधानमंत्री मोदी की कूटनीतिक पहल से मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, ईरान, नाइजीरिया, अल्जीरिया, कुवैत, कजाकिस्तान, कतर, मिस्र, बहरीन, ट्यूनीशिया, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और जॉर्डन सरीखे अन्य मुस्लिम देशों से भी संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल के साथ भारत के रिश्ते को पुनर्परिभाषित किया है। दोनों देशों के रिश्ते को स्वर्ग में बनने और धरती पर लागू करने के भावुक विचार रेखांकित करने के लिए पर्याप्त हैं कि दोनों देश भावनात्मक रूप से एक दूसरे के कितने निकट हैं। दक्षिण एवं पश्चिम एशिया के साथ-साथ भारत और यूरोपीय संघ के बीच भी रिश्ते परवान चढ़े हैं। भारत और यूरोपीय संघ 'स्टैंड-अलोन', निवेश संरक्षण पर सहमति के साथ साझा हितों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, कानून का शासन, मानवाधिकारों का सम्मान जैसे कई अन्य मानवीय मसलों पर सहमति जताते हुए स्वीकार किया कि यह हमारी सामरिक साझेदारी का मूल्य है। अच्छी बात है कि दोनों पक्षों ने भारत-यूरोपीय संघ ढांचा 2025 को लेकर तय कार्य बिंदुओं पर आगे बढ़ने तथा टिकाऊ विकास एवं पेरिस समझौता 2030 के

एजेंडे पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। दुनिया की महाशक्ति अमेरिका की बात करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने अपने कूटनीतिक-रणनीतिक धार से दशकों पुराने अमेरिका की पाक नीति को बदलकर रख दिया है। उनकी कूटनीतिक पहल का ही नतीजा है कि अमेरिका की प्रतिनिधि सभा भारत के साथ रक्षा संबंध विकसित करने और रक्षा उपकरणों की बिक्री तथा प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के मामले में अन्य नाटो के सहयोगी देशों के साथ लाने की पहल के तहत द्विदलीय समर्थन वाले बिल को मंजूरी दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कूटनीतिक पहल से अमेरिका और पाकिस्तान के बीच दूरिया बढ़ी हैं। पहले अमेरिका और पाकिस्तान के बीच कितनी निकटता थी, इसी से समझा जा सकता है कि मई, 1965 में प्रधानमंत्री लालबहादुर शास्त्री ने जब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन्सन के निमंत्रण पर वहां की यात्रा का कार्यक्रम बनाया तब उसी समय पाकिस्तान के अयूब खान के दौरे के कार्यक्रम के कारण अमेरिका ने अपना निमंत्रण वापस ले लिया। यही नहीं जब भी कभी प्रतिबंधों की बात आयी तो अमेरिका पाकिस्तान के साथ-साथ भारत को भी किसी प्रकार की अमेरिकी सहायता प्रदान करने पर रोक लगाया। यानी तब अमेरिका के पलड़े पर भारत और पाकिस्तान बराबर थे। लेकिन आज, प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के असली चेहरे को बेनकाब कर अमेरिका को उससे न सिर्फ दूर किया है बल्कि अमेरिकी संसद के जरिए भारत और अमेरिका के अपरिहार्य संबंधों को भी निरूपित कर दिया है। न्यूक्लियर सप्लाई ग्रुप यानी एनएसजी और एमटीसीआर के मसले पर अमेरिका के समर्थन को इसी दृष्टिकोण से देखा जाना चाहिए। मानकर चलना चाहिए कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में पाकिस्तान को पहले जैसा न तो अमेरिका से करोड़ों डॉलर की आर्थिक मदद मिलने वाला

है और न ही कूटनीतिक समर्थन। मजेदार तथ्य यह भी कि अमेरिका की लाख धौंसपट्टी के बावजूद भी भारत ने रूस के साथ 40 हजार करोड़ रुपए के एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम की खरीद को अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा की जरूरत बताकर स्पष्ट कर दिया कि उसके लिए देश की सुरक्षा सर्वोपरि है। वह किसी के दबाव में आने वाला नहीं है। यही नहीं भारत ने एस-400 को लेकर काउंटरिंग अमेरिकाज एडवर्सरीज थ्रू सैंक्शंस एक्ट यानी काटसा के तहत प्रतिबंधों के सवाल पर अपना नजरिया स्पष्ट करते हुए कह भी चुका है कि भारत का रूस के साथ संबंधों का लंबा इतिहास रहा है जिसकी वह अनदेखी नहीं कर सकता। मतलब साफ है कि भारत अमेरिका या रुस के दबाव में अपनी विदेश नीति को नए सिरे से परिभाषित करने वाला नहीं है। अभी गत माह पहले ही द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर सोवियत जीत की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर आयोजित रूस की विक्ट्री डे परेड उत्सव में भारतीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने शिरकत किया। उस दरम्यान रूस ने चीन की लाख मनाही के बावजूद भी भारत को एस-400 एयर डिफेंस सिस्टम देने की प्रतिबद्धता दोहराकर रेखांकित किया कि दोनों देश सदाबहार और भरोसेमंद साथी हैं। गौर करें तो ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत का रूस और अमेरिका दोनों से रिश्ते प्रगाढ़ हैं। आमतौर पर भारतीय कालखंड में ऐसा दौर कभी नहीं रहा है। प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक दांव के आगे पड़ोसी देश चीन भी घुटने के बल है। उसके लाख विरोध के बावजूद भी भारत मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हो गया है। यह उपलब्धि हासिल करने के बाद अब भारत दूसरे देशों को अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी बेचने को तैयार है और जरूरत पड़ने पर अमेरिका से प्रिडेटर ड्रोन्स को खरीद भी सकेगा। अच्छी बात यह कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सुपरसोनिक मिसाइल तैयार करने वाली कंपनी ब्रह्मोस एयरोस्पेस को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दे दिए हैं। इससे चीन बौखलाया हुआ है। क्योंकि मलेशिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने की कतार में हैं। ध्यान देना होगा कि ये वहीं देश हैं जो दक्षिणी चीन सागर में चीन की साम्राज्यवादी नीति से परेशान हैं। भारत-जापान, भारत-जर्मनी, भारत-फ्रांस मजबूत होते रिश्ते और दोनों देशों के बीच असैन्य परमाणु सहयोग, रक्षा उपकरण तकनीक और गोपनीय सैन्य सूचना संरक्षण समेत कई महत्वपूर्ण समझौते से भी चीन परेशान है। भारत और जापान के एक साथ आने से दक्षिणी चीन सागर में चीन के बढ़ते हस्तक्षेप को लगाम लगा है। दूसरी ओर अमेरिका के साथ लॉजिस्टिक एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट सप्लाई एग्रीमेंट (एलईएमओ) ने भी चीन की चिंता बढ़ा दी है। इस समझौते से दोनों देशों के युद्धपोत और फाइटर एयरक्राफ्ट एक दूसरे के सैनिक अड्डों का इस्तेमाल तेल भराने एवं अन्य साजो-सामान की आपूर्ति के लिए कर सकेंगे। इससे चीन खौफजदा है और उसे लग रहा है कि भारत और अमेरिका उसकी घेराबंदी कर रहे हैं। चीन इसलिए भी असहज है कि चार देशों के राजनीतिक समूह क्वाड (क्वाड्रिलेटरल सेक्युरिटी डायलॉग) के सदस्य देशों-भारत, अमेरिका, जापान और आस्ट्रेलिया ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में विस्तारवादी रूख अपना रखे चीन पर नकेल कसना शुरु कर दिया है। मोदी ने साफ संकेत दे दिया है कि चीन को अब अपने हद में रहने की जरूरत है। गौर करें तो प्रधानमंत्री मोदी ने सात वर्ष के कालखंड में एक ऐसा ताकतवर भारत गढ़ा है जो हर चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए तैयार है। ◆◆◆

प्रधानमंत्री मोदी के कूटनीतिक दांव के आगे पड़ोसी देश चीन भी घुटने के बल है। उसके लाख विरोध के बावजूद भारत मिसाइल टेक्नोलाजी कंट्रोल रिजीम (एमटीसीआर) में शामिल हो गया है।

(लेखक भाजपा नेता और मुम्बई के युवा उद्योगपति हैं)

चन्द्रकान्त चौधरी

नरेन्द्र मोदी
अपराजेय राजनीतिक योद्धा

प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व अतीव प्रभावशाली है तथा स्वयं की सकारात्मक व्यापक सोच के कारण वह आज भारत की आशाओं एवं अपेक्षाओं की सम्पूर्ति के लिए प्रकाश पुंज सदृश स्वयं में एक आश्वासन हैं।

श्री नरेन्द्र मोदी – भारत के महान जननायक, देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री, स्वयं में आध्यात्मिक, यौगिक, साहित्यिक, गम्भीर लेखक, अत्यंत प्रभावशाली वक्ता, यथार्थ के धरातल पर अत्यंत कल्पनाशील कवि, पूर्व सम्पादक, कहानीकार, विपुल जनाधार वाले चमत्कारी राजनेता,वैश्विक नेतृत्व दृष्टि एवं क्षमता से सुसम्पन्न एक बहुआयामी व्यक्तित्व, अपराजेय राजनीतिक योद्धा, भारतीय राजनीति के दिशानायक ..!

उपरोक्त समस्त विशेषताओं से अलंकृत प्रधानमंत्री मोदी का व्यक्तित्व अतीव प्रभावशाली है तथा स्वयं की सकारात्मक व्यापक सोच के कारण वह आज भारत की आशाओं एवं अपेक्षाओं की सम्पूर्ति के लिए प्रकाश पुंज सदृश स्वयं में एक आश्वासन हैं। मोदी जी का दूरदर्शी एवं कर्मठ व्यक्तित्व जहाँ एक ओर भारत के सर्वांगीण विकास की ईमानदार कोशिश एवं परिणामपरक राष्ट्र हितैषी व राष्ट्र कल्याणकारी कार्यों के प्रति प्रतिबध्दता का प्रतीक है, वहीं दूसरी ओर विविधतापूर्ण विशेषताओं से सुसज्जित उनका रोमांचकारी व अत्याकर्षक बहुआयामी व्यक्तित्व सम्पूर्ण विश्व के लिए, विश्व मानवता के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। अपनी वैश्विक हितकारी दृष्टि एवं प्रयासों के लिए आज वह विश्व नेता के रूप में देखे जा रहे हैं।

क्या कभी किसी ने सोचा होगा कि एक चाय बेचने वाला व्यक्ति भारत जैसे सुविशल राष्ट्र का प्रधानमंत्री बन सकता है? शायद कभी नहीं। कर्मठता, पुरुषार्थ, संघर्ष, त्याग, नि: स्वार्थ भावना, देश के प्रति समर्पण तथा भारत को दुनिया का सर्वाधिक शक्तिशाली राष्ट्र बनाने की महती भावना, प्रखर विचार तथा प्रतिबद्धता के माध्यम से राष्ट्रोत्थान हेतु भगीरथ प्रयास करनेवाले महान जननायक श्री नरेन्द्र मोदी जी विलक्षण व्यक्तित्व हैं, राष्ट्रीय- अंतर्राष्ट्रीय नेतृत्व की दृष्टि, विचार तथा गरिमा को स्व व्यक्तित्व में समेटे हुए अद्भुत विभूति हैं। श्री नरेन्द्र मोदी जी के कृतित्व, व्यक्तित्व एवं संघर्ष को कुछ पृष्ठों में लिख पाना सम्भव नहीं है। आपके सम्पूर्ण व्यक्तित्व पर एक वृहद् ग्रन्थ लिखे जाने की महती आवश्यकता है।

भाजपा के सर्वाधिक प्रभावशाली नेता के रूप में श्री मोदी ने पार्टी में स्वयं की सर्वरूपेण स्वीकार्यता स्थापित कर यूपीए सरकार के कुशासन एवं भ्रष्टाचार से मुक्त कराने हेतु सिंह गर्जना करते हुए देश को अपने दृष्टिकोण एवं ओजस्वी विचारों से झकझोर कर रख दिया है और उन्होंने भावी भारत की समग्र विकासपरक व कल्याणकारी तस्वीर प्रस्तुत की है। देश की जनता ने श्री मोदी के विचारों एवं सपनों को मूर्तरूप देने हेतु दोबारा प्रधानमंत्री बनाकर जबर्दस्त समर्थन दिया और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। सभी देशों से राष्ट्रीय मित्रता व सौहार्दपूर्ण- सम्मानजनक सम्बन्ध बनाने के मामले में भारत को न केवल एक अतिदूरदर्शी, आत्मविश्वासी, साहसी एवं प्रभावशाली नेतृत्व मिला है बल्कि विश्व को भी मोदी के रूप में एक ऐसा नेता मिला है, जिसकी दुनिया के महत्वपूर्ण व ज्वलंत मुद्दों पर स्पष्ट व सर्वहितैषी राय है, दृष्टिकोण है।

देश के विकास एवं सुरक्षा के मुद्दे पर मोदी सरकार न केवल बेहद गंभीर है बल्कि देश के व्यापक हित में अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों के माध्यम से देश के वास्तविक विकास को सुनिश्चित कर राष्ट्रीय जन- जीवन को समुन्नत बना रही है। दीर्घावधि से यौगिक जीवन जीने वाले श्री मोदी तन- मन, चिंतन- मनन एवं आत्मरूपेण सर्वथा बलशाली व्यक्तित्व हैं और यही आनंदप्रदायी स्थिति जन-जन को प्राप्त हो की कामना करने वाले मानवता प्रेमी, विश्वसेवी- विश्वनेता हैं।

◆◆◆

(लेखक मुंबई के सम्मानित उद्योगपति एवं समाजसेवी हैं)

DESAI HARMONY

WADALA (W)

MAHA RERA NO.P51900009455

Follow Us On

Swimming Pool

Ample Car Parking

Podium Garden

Health & Fitness Center

Luxurious 2, 3 & 4 BHK Apartments

Centrally located in the heart of the city (Wadala, West), Desai Harmony makes your life convenient as the best of the metropolis surrounds you. It's a two minutes drive from all the major infrastructure facilities and the most happening destinations of Mumbai. **Stay closer to life.**

Call :+91 9209206206 / +91 75061 18929 / +91 98198 51644

E : sales@sparkdevelopers.in | sms Spark Wadala to 56677

Our Projects At : Worli | Andheri | Ghatkopar | Vile-Parle

Site Address : Desai Harmony, G.D Ambekar Marg, Opp. Hanuman Industrial Estate, Near Dadar Workshop, Wadala, Mumbai - 400 031

Corp. Office : 102, Saroj Apartment, 1st Floor, N.P. Marg, Opp. Matunga Gujarati Club, King's Circle, Matunga, Mumbai – 400 019

SPARK DEVELOPERS
creating world for you

www.sparkdevelopers.in

Disclaimer: This advertisement is merely conceptual and is not a legal document. It cannot be treated as a part of final purchase agreement. All dimensions are approximate and subject to construction variances. The developer reserves sole rights to amend architectural specifications during development stages.

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर,2016 में शुरू किए गए भीम-यूपीआई भुगतान प्रणाली की तरह ई-रुपी को भी डिजिटलीकरण की दिशा में किया गया एक बड़ा सुधार मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूपीआई प्रणाली ने भारत में भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है।

ई-रूपी से होगा वित्तीय जीवन आसान

– सतीश सिंह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 अगस्त, 2021 को ई–वाउचर आधारित डिजिटल भुगतान प्रणाली ई–रुपी का आगाज किया। इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलने और भ्रष्टाचार पर लगाम लगने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अनुसार इस नई भुगतान प्रणाली से सबसे अधिक फायदा विभिन्न सामाजिक योजनाओं के मौजूदा लाभार्थियों को मिलेगा। इसका इस्तेमाल आगे जाकर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी)के विकल्प के रूप में किया जा सकेगा। इसकी मदद से सामाजिक योजनाओं के लाभार्थियों को पारदर्शी और सुरक्षित तरीके से नकदी एवं अन्य सुविधाएँ मिल सकेंगी। इस सुविधा का लाभ लेने के लिए लाभार्थी को न तो किसी से मिलना पड़ेगा और न ही किसी से कोई पैरवी करनी पड़ेगी।

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मौजूदा समय में डीबीटी यह सुनिश्चित करता है कि पैसा सही लाभार्थी तक पहुंचे। इससे सरकार को अरबों–खरबों रूपये की बचत हो रही है। डीबीटी के जरिये 90 करोड़ से अधिक नागरिकों को फायदा मिला है। इसके जरिये पीएम किसान सम्मान निधि, सार्वजनिक वितरण सेवाएं, एलपीजी गैस सब्सिडी आदि योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ हुआ है।

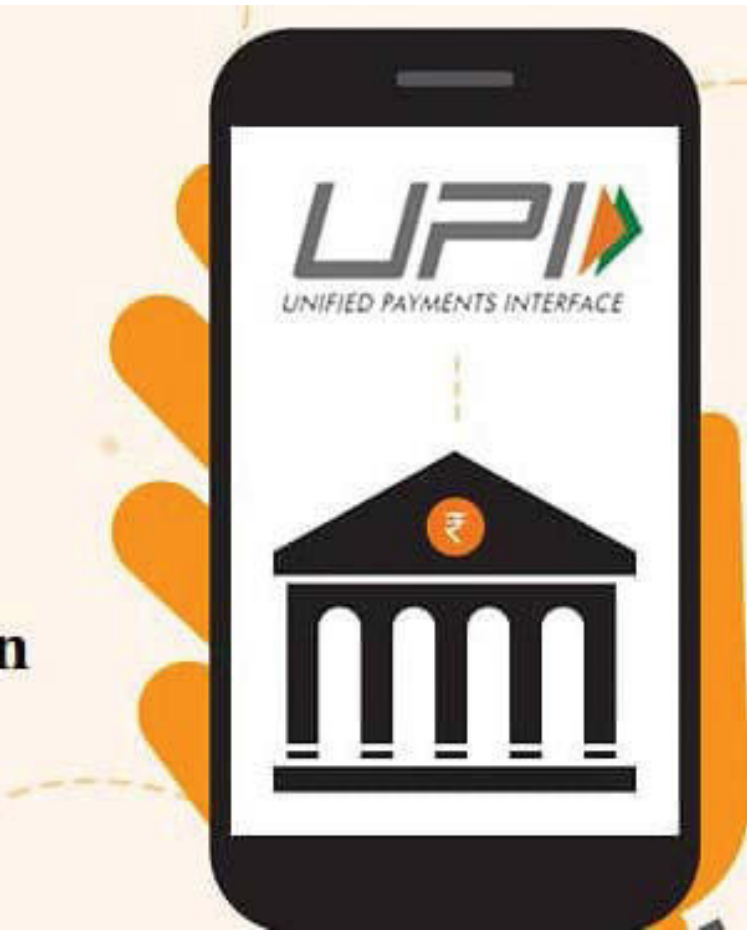

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिसंबर, 2016 में शुरू किए गए भीम-यूपीआई भुगतान प्रणाली की तरह ई-रुपी को भी डिजिटलीकरण की दिशा में किया गया एक बड़ा सुधार मान रहे हैं। उल्लेखनीय है कि यूपीआई प्रणाली ने भारत में भुगतान प्रक्रिया को पूरी तरह से बदल दिया है। इसमें अंतर्निहित फ़ायदों की वजह से आज यह सभी वर्गों के बीच डिजिटल भुगतान करने का सबसे पसंदीदा माध्यम बना हुआ है। जुलाई, 2021 में यूपीआई के जरिये 3 अरब लेनदेन किए गए, जो राशि में 6 लाख करोड़ रुपये से अधिक थी।

क्या है ई-रूपी

ई- रूपी एक प्रीपेड ई-वाउचर है, जिसे नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआई) ने वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ मिलकर विकसित किया है। ई-रूपी के विकास में एनपीसीआई के अलावा दूसरे विभाग इसलिए शामिल हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा विभिन्न सामाजिक योजनाओं के तहत सबसे अधिक संख्या में लाभार्थियों को डीबीटी किया जाता है।

ई-रूपी डिजिटल करेंसी को विकसित करने की दिशा में पहला कदम है। यह गिफ्ट वाउचर के समान है, जिसे क्रेडिट या डेबिट कार्ड या मोबाइल ऐप या फिर इंटरनेट बैंकिंग के बिना बैंक की चुनिंदा शाखाओं पर इसका भुगतान लिया जा सकता है। यह एक क्यूआर कोड या एसएमएस स्ट्रिंग आधारित ई-वाउचर है, जिसे सीधे लाभार्थियों के मोबाइल पर भेजा जाता है।

ई-रूपी के जरिए सरकारी योजनाओं से जुड़े विभाग या संस्थान शारीरिक रूप से बिना किसी व्यक्ति के संपर्क में आए सीधे लाभार्थियों को लाभ पहुंचा सकते हैं। इस प्रणाली में यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि लेनदेन पूरा होने के बाद ही सर्विस प्रोवाइडर को भुगतान किया जाए। प्रीपेड होने की वजह से इस प्रक्रिया में किसी भी मध्यस्थ को शामिल किए बिना सर्विस प्रोवाइडर को समय पर भुगतान किया जा सकेगा।

ई-रूपी के फायदे

इस प्रणाली का उपयोग बहुआयामी है, लेकिन इसका सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य ऑनलाइन भुगतान को आसान एवं सुरक्षित बनाना है। इससे लेनदेन बिना नकदी के किया जा सकता है। इस प्रणाली में बिचौलिये की कोई भूमिका नहीं है, क्योंकि यह प्रणाली भुगतान करने वाले और भुगतान लेने वाले को सीधे तौर पर जोड़ती है। इससे सरकारी योजनाओं का लाभ लाभार्थियों को सीधे मिलेगा, जिससे भ्रष्टाचार के मामलों में कमी आयेगी। इस डिजिटल वाउचर का उपयोग निजी क्षेत्र में कंपनियाँ अपने कर्मचारियों के कल्याण और कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी के निर्वहन के लिए भी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल माँ एवं बच्चे के कल्याण,टीबी उन्मूलन,आयुष्मान भारत,खाद सब्सिडी आदि योजनाओं के तहत लाभार्थियों की भुगतान जरूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है। कोरोनाकाल में कोई भी कंपनी अपने कर्मचारियों का टीकाकरण करने के लिए इस सुविधा का लाभ उठा सकती है। लाभार्थी को चिन्हित अस्पताल में मुफ्त टीके तभी मिलेंगे, जब वह ई-रुपीएसएमएस या क्यूआर कोड दिखायेगा।

ई-वाउचर्स जारी करने की प्रक्रिया

ई-रूपी वाउचर को बैंक जारी करेंगे। अगर किसी कॉरपोरेट या सरकारी एजेंसी को किसी खास व्यक्ति को ई-रूपी वाउचर देना है तो उसे सरकारी या निजी बैंक से संपर्क करना होगा। लाभार्थी की पहचान मोबाइल नंबर के जरिए होगी और सर्विस प्रोवाइडर को बैंक एक वाउचर आवंटित करेगा, जो किसी व्यक्ति विशेष के नाम से जारी किया जायेगा और जिसके नाम से यह ई-रूपी वाउचर जारी किया गया,सिर्फ वही इसका भुगतान ले सकेगा।

ई-रूपी जैसे वाउचर विदेशों में भी हैं प्रचलित

अमेरिका में शिक्षा के क्षेत्र में ई-वाउचर प्रणाली प्रचलित है,जिसके जरिए सरकार छात्रों की पढ़ाई के लिए उनके माता-पिता को सीधे तौर पर भुगतान करती है,ताकि बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा नहीं आये। अमेरिका के अलावा ई-वाउचर प्रणाली कोलंबिया, चिली, स्वीडन,हांगकांग आदि देशों की स्कूलों में भी प्रचलित है।

डिजिटल करेंसी और ई-रूपी में अंतर

भारतीय रिजर्व बैंक डिजिटल करेंसी लाने की योजना पर काम कर रही है। हालांकि,ई-रूपी वाउचर वर्चुअल करेंसी से अलग है, क्योंकि यह एक तरह से वाउचर आधारित भुगतान प्रणाली है।

फिर भी, ई-रूपी के आगाज से डिजिटल भुगतान की अवसंरचना को मजबूत करने वाले विकल्पों को समझने में मदद मिलेगी और उसे मजबूत करने की दिशा में कालांतर में अग्रतर कार्रवाई की जा सकेगी।

ई-रूपी की मुश्किलें

भले ही ई-रूपी का आगाज देश में हो गया है। फिर भी,अभी तक यह साफ नहीं हुआ है कि वैसे लाभार्थियों के संदर्भ में सरकार या निजी संस्थान या फिर कॉर्पोरेट क्या करेंगे, जिनके पास मोबाइल फोन नहीं है, क्योंकि 31 जनवरी 2020 तक देश में 115.6 करोड़ लोग मोबाइल का इस्तेमाल जरूर कर रहे थे, लेकिन स्मार्टफोन इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगभग 50 करोड़ थी। हालाँकि,इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार डीबीटी योजना को कुछ और समय तक ई-रूपी प्रणाली के साथ-साथ जारी रख सकती है। फिर भी, सरकार को गरीबों और वंचित तबके के लोगों को इसके फ़ायदों एवं इसके इस्तेमाल के तरीकों के बारे में शिक्षित करना होगा, क्योंकि लाभार्थी मोबाइल पर आए क्यूआर कोड या एसएमएस को गलती से डिलीट भी कर सकते हैं, क्योंकि आज कल मोबाइल पर रोज 20 से 25 फालतू संदेश जरूर आते हैं, जिन्हें मोबाइल में स्पेस बनाये रखने के लिए नियमित तौर पर मोबाइल यूजर्स को डिलीट करना पड़ता है।

फिलहाल, सरकार के 54 मंत्रालयों द्वारा 315 डीबीटी योजनाएं संचालित की जा रही हैं। हालाँकि,सभी योजनायेँ सभी के लिए लागू नहीं हैं। फिर भी, सभी लागू योजनाओं के लाभार्थियों की संख्या अच्छी-ख़ासी है। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के आंकड़ों के मुताबिक अब तक डीबीटी योजनाओं के तहत 7.32 लाख करोड़ लेनदेन किए गए हैं और इसके अंतर्गत लाभार्थियों को लगभग 1.42 लाख करोड़ रुपये अंतरित किए गए हैं।

ई-रूपी वाउचर प्रणाली को अमलीजामा पहनाने में बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बैंक पहले से ही कई सामाजिक योजनाओं को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं। इस नई प्रणाली के आने से बैंकों पर और भी कार्यभार बढ़ेगा, लेकिन बैंक के

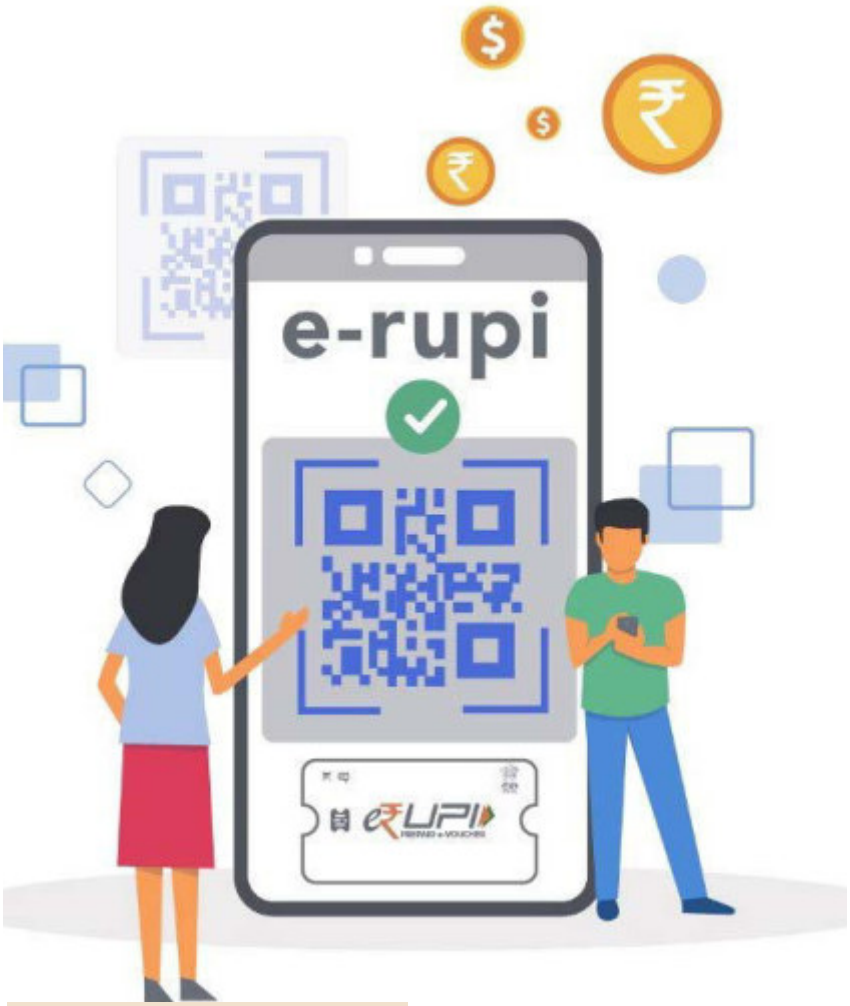

ई-रूपी वाउचर प्रणाली को अमलीजामा पहनाने में बैंकों की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन बैंक पहले से ही कई सामाजिक योजनाओं को पूरा करने में अपनी अहम भूमिका निभा रहे हैं।

कर्मचारियों की संख्या में फिलहाल इजाफा करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, जिससे बैंकों को इस नई प्रणाली को अमलीजामा पहनाने में मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा।

निष्कर्ष

कहा जा सकता है कि ई-रुपी वाउचर एक ऐसी भुगतान प्रणाली है, जिसका इस्तेमाल डीबीटी के विकल्प के तौर पर भविष्य में किया जा सकता है। फिलवक्त,डीबीटी के जरिये राशि लाभार्थी के बैंक खाते में सीधे अंतरित की जाती है, जबकि ई-रुपी के माध्यम से एक समान राशि वाला वाउचर सीधे लाभार्थियों के मोबाइल फोन पर एसएमएस स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के रूप में भेजा जा सकेगा। लाभार्थी एसएमएस या क्यूआर कोड बैंकों के चिन्हित शाखा में दिखाकर उसका भुगतान ले सकेंगे। अगर ई-रूपी वाउचर किसी सुविधा का लाभ लेने के लिए जारी किया जायेगा तो लाभार्थी को उक्त संस्थान या विभाग में जाकर लक्षित सुविधा का लाभ लेना होगा, क्योंकि इ-रूपी वाउचर का इस्तेमाल सिर्फ लक्षित मकसद के लिए किया जा सकता है। अन्य उद्देश्य के लिए इसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा। उदाहरण के तौर पर अगर ई-रुपी को टीकाकरण करवाने के लिए जारी किया गया है तो इसका इस्तेमाल लाभार्थी केवल टीकाकरण केंद्र पर ही कर सकेंगे। ◆◆◆

(लेखक भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक अनुसंधान विभाग में सहायक महाप्रबंधक हैं)

FLF
FUTURE LIFESTYLE FASHIONS

*Terms & Conditions Apply.

KARMA

200 BEST BRANDS | 20%-70% OFF | SALE 365 DAYS

BRAND FACTORY

BEST BRANDS ▸ SMART PRICES

SKECHERS | Levi's | Lee Cooper | Buffalo | W | Van Heusen | United Colors of Benetton | U.S. Polo Assn. | Gini & Jony | Peter England

23 CITIES. 55 STORES

www.brandfactoryonline.com | brand factory | CUSTOMER CARE NO.: 18002101888

शिक्षा का भारतीयकरण

– प्रमोद भार्गव

भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद एक समय तक अंग्रेजों की भाषा-नीति में बदलाव होता रहता था। सन् 1833 में मैकाले मिनिट्स के होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालती तथा अन्य शासकीय कार्यों में अरबी-फरसी का मिश्रित रूप अपनाया था।

नई शिक्षा नीति के चलन में आने के बाद मातृभाषाओं में शिक्षा की जो सर्वश्रेष्ठ देन होगी, वह नागरिक में राष्ट्रबोध जगाने के साथ उसका व्यक्ति के स्तर पर भारतीयकरण करना। कल का विद्यार्थी ही कालांतर में देश का नागरिक होता है। दरअसल, अब नई शिक्षा नीति के अंतर्गत वास्तव में राष्ट्र की लुप्त कर दी गई सांस्कृतिक संपदा के महत्व को अंगीकार करते हुए ज्ञान, कर्म, संस्कार,भाषा, संस्कृति और कौशल दक्षता को विद्यार्थी में विकसित करने का काम मातृभाषाएं करेंगी। मानव को मानवीय बनाने के यही मानविकी विषय हैं। व्यक्तित्व निर्माण की यही परिकल्पना व्यक्ति में राष्ट्रबोध का प्रादुर्भाव करती है। मूल्य-बोध के इन संस्कारों से संपूर्ण राष्ट्र में सांस्कृतिक चेतना का लोकव्यापीकरण होगा और सनातन मानवीय मूल्यों की सुरक्षा होगी। यही मूल्य न केवल व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनाएंगे, बल्कि देश को भी आत्मनिर्भता के शिखर पर पहुंचाएंगे। देश की सांस्कृतिक संप्रभुता की पहचान को भी अक्षुण्ण बनाए रखने

का काम करेंगे। कोरोना महामारी के दंश ने भी पुरातन मूल्यों को अपनाने का संदेश दिया है। योग, आयुर्वेद और भारतीय ज्ञान-परंपरा में अंतर्निहित मूल्यों को भी समझने का रास्ता इस संकट ने खोला है। एकल परिवारों की अवधारणा कौटुम्बिक महत्ता को जानने को उत्सुक हुई है। यही सब वे मूल्य थे, जिन्हें औपनिवेशिक अंग्रेजी शिक्षा ने सुनियोजित ढंग से पृथक किया और भारतीय नागरिक भारतीय सनातन मूल्यों को भूलता चला गया।

भारत में अंग्रेजों का शासन स्थापित होने के बाद एक समय तक अंग्रेजों की भाषा-नीति में बदलाव होता रहता था। सन् 1833 में मैकाले मिनिट्स के होते हुए ईस्ट इंडिया कंपनी ने अदालती तथा अन्य शासकीय कार्यों में अरबी-फरसी का मिश्रित रूप अपनाया था। हिंदू राजाओं के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी अपने पत्र-व्यवहार में स्थानीय बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग करती थी। सन् 1880 में कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना हुई। उस समय अंग्रेजी शासन की राजधानी कलकत्ता थी। जॉन ग्रिलक्राइस्ट उस कॉलेज के भाषा विभाग के अध्यक्ष बनाए गए। उन्होंने खड़ी बोली के प्रयोग को प्रोत्साहित किया और कंपनी सरकार की भाषा नीति तय करने में आवश्यक सुझाव दिए। वह हिंदी को हिंदुई तथा हिंदुस्तान कहते थे और उसके लिए रोमन लिपि को आवश्यक मानते थे, किंतु न तो हिंदी का नाम बदल सके और न ही लिपि। देवनागरी लिपि से संबंधित हिंदी का संघर्ष सफल रहा। गिलक्राइस्ट के बाद मैकाले की भाषा-नीति मानी गई और उच्च शिक्षा से संस्कृत एवं हिंदी का माध्यम समाप्त कर दिया गया। उन्नीसवीं शताब्दी के चौथे दशक में सरकारी कामकाज में उर्दू को वरीयता दी गई और हिंदी को उपेक्षित कर दिया गया। उस युग में बनारस हिंदी का केंद्र था और बनारस की दो बड़ी हस्तियां हिंदी में लिख रहीं थीं। एक थे राजा शिवप्रसाद 'सितारे हिंद' और दूसरे भारतेंदु हरिशचंद्र। राजा शिवप्रसाद अंग्रेजी सरकार की सेवा में थे और अंग्रेजों की भाषा नीति का समर्थन करते हुए उन्होंने उर्दू का पक्ष लेते हुए हिंदी की निंदा की। उनकी वफादारी देखकर सरकार ने उन्हें 'सितारे हिंद' की उपाधि दी। हरिशचंद्र ने सरकार की भाषा-नीति का विरोध किया और जगह-जगह जाकर हिंदी के समर्थन में सभाएं कीं। जनता ने हरिशचंद्र को 'भारतेंदु' की उपाधि से विभूषित किया। भारतेंदु की लोकप्रियता के सामने सितारे हिंद अस्त-पस्त हो गए। जॉन गिलक्राइस्ट जैसे अनेक अंग्रेज हिंदी के समर्थक थे। ऐसे अंग्रेजों में हेनरी पिनकोट ने भारतेंदु के समर्थन में हिंदी के पक्ष में बहुत काम किया। राजा शिवप्रसाद की तरह राजा लक्ष्मण सिंह (1826-96) भी सरकारी नौकर थे, किंतु उन्होंने हिंदी का समर्थन किया और उसी में लिखा भी।

इस दौरान देश में जो विवि और राज्यस्तरीय शिक्षा मंडल अस्तित्व में आए, उन्होंने अंग्रेजी विषयक पाठ्यक्रमों में आंग्ल साहित्य का अध्ययन, अध्यापन बीसवीं सदी की शुरूआत में ही कर दिया था। इस समय भारतीय लेखक जो भी कुछ अंग्रेजी में लिख रहे थे, उसे पाठ्यक्रम में शामिल कर दिया गया। इनमें ज्यादातर लेखक बंगाली थे और इन पाठ्यक्रमों की शुरूआत भी बंगाल में हुई। इन लेखकों की लिखने की पद्धति लगभग अंग्रेजियत में सराबोर थी। चारण-भाटों की शैली में इन्होंने अंग्रेजी का स्तुतिगान तो किया ही, तात्कालिक लाभ के लिए इनमें से कई क्रिश्चियन भी हो गए। भारत की धरती पर अंग्रेजी का बीज बोने और इसे उर्वरा बनाने के पैरोकार मैकाले ने ऐसे लोगों को वजीफे दिलाए और लंदन की मुफ्त में सैर भी कराई। सही मायनों में ये तथाकथित अंग्रेजी के लेखक इंग्लैंड के बंधुआ साहित्यकार थे। इन्होंने अंग्रेजी के प्रभुत्व को स्थापित करने के उपायों के साथ विस्तार के मार्ग भी प्रशस्त किए। इनमें तोरूदत्त, माइकल मधुसूदन दत्त और मनमोहन घोष प्रमुख थे। गोया, ब्रिटिश हुक्मरानों के भय के चलते इन बंधुआओं से लेखन में भारतीयता का प्रभाव डालने की उम्मीद कतई नहीं की जा सकती थी। जिस राष्ट्रीय चेतना को हम स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में लेते हैं, उस तरह के लेखन का भारतीय अंग्रेजी लेखकों में सर्वथा अभाव था। हालांकि, वंदे मातरम् गीत के रूप में भारत को उसकी व्यापक राष्ट्रीयता की पहचान देने वाले महान बंगला उपन्यासकार बंकिमचंद्र चटर्जी न केवल बंगाल के चुनिंदा लेखकों में से एक थे, बल्कि उन्हें भारतीय अंग्रेजी साहित्य के शुरूआती लेखन का श्रेय भी जाता है। उन्होंने राजमोहन्स वाइफ नामक उपन्यास अंग्रेजी में लिखा था। किंतु राष्ट्रीय स्वाभिमान के चलते कालांतर में उन्होंने केवल बंगला और संस्कृत में लिखने का संकल्प लिया और फिर अंग्रेजी में रचना-सृजन पर विराम लगा दिया। भाषाई अस्मिता और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के प्रकल्प का ऐसा अनूठा संकल्प था, जिसने वंदे मातरम् के माध्यम से फिरंगी सत्ता को चुनौती देते हुए जनमानस में सर्वाधिक राष्ट्रबोध जगाने का काम किया।

साहित्य, मानविकी और मानवाधिकार विषयों का अध्ययन-अध्यापन व्यक्ति में वैचारिक ऊर्जा पैदा करने का काम करते हैं। इनके पढ़ने से इच्छाशक्ति प्रबल होती है। लेकिन, 1991 में लाए गए भूमण्डलीय आर्थिक उदारवाद के बाद जिस बेतुके ढंग से शिक्षा संस्थानों का व्यवसायीकरण हुआ और साहित्य व मानविकी विषयों को भी जिस बेढंगेपन से रोजगारोन्मुखी बनाने की कोशिशें हुईं, इससे शिक्षा के मूल पर आघात हुआ। विश्वविद्यालय अप्रजातांत्रिक हो गए। शिक्षा परिसरों में व्यावसायिक स्थापना के लिए थाने तक खोलने पड़े। जाहिर है, ये उपाय शिक्षा के लोकव्यापीकरण, शिक्षा में गुणवत्ता लाने अथवा छात्र के चरित्र निर्माण की दृष्टिगत नहीं

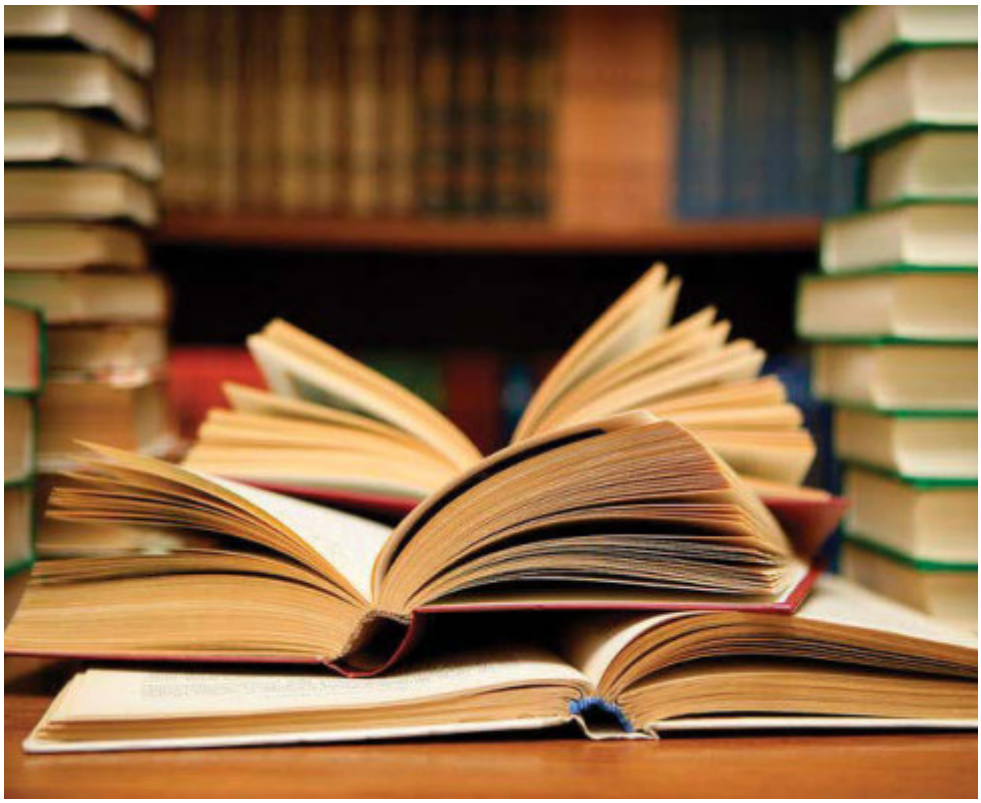

किए गए, बल्कि शिक्षा को औद्योगिक उत्पाद बना देने के लिए हुए। मनुष्य का सशक्तिकरण, जीवनस्तर में सुधार और निर्णय लेने की प्रक्रिया में शिक्षा की सबसे अहम् भूमिका है। मानविकी और मानवाधिकार शिक्षा के वास्तविक अर्थ अपने इतिहास, भूगोल, भाषा और लोक व्यवहार के परिप्रेक्ष्य में समाज और सामाजिक समस्याओं को जानना है। तत्पश्चात उन्हें लोक व्यवहार में अपनाना और उनके वैधानिक निदान तलाशना है। जिससे समाज में समरसता बढ़े और उसका लोकतांत्रिक नजरिया मुखर हो। महात्मा गांधी ने कहा था, ''कोई समुदाय तभी लोकतांत्रिक हो सकता है, जब समुदाय के सबसे कमजोर व्यक्ति को सर्वोच्च नागरिक जैसे सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक अधिकार मिले।'' लेकिन आर्थिक उदारवादी नीतियां लागू होने के बाद देश में आवारा पूंजी का दबाव इस हद तक बढ़ा कि हम पूंजी आधारित लिप्सा और औपनिवेशिक शक्तियों की व्यवस्था को विकास व प्रगति का आदर्श मानक मानने लगे। नतीजतन, आर्थिक विसंगति बढ़ी और असंतोष उपजा। माओवाद बनाम नक्सलवाद की जड़ें गहरी करने में इस असंतोष ने ऊर्जा का काम किया। वामपंथी चरमपंथ ने इस असंतोष को अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए भुनाने का काम किया।

समरसता व समावेशन संबंधी जो मूल अवधारणाएं हैं, वे सभी हमारे आधुनिक और प्रगतिशील माने जाने वाले संविधान में परिभाषित हैं। उनका उल्लंघन होने पर एक कानूनी प्रक्रिया से गुजरने के बाद दंड का समुचित विधान है। बावजूद 73 सालों में हम एक समान समाज की संरचना करने की बजाय विषमता और वैमनस्यतापूर्ण समाज की रचना करने में लगे रहे। जबकि, नागरिक समाज में हमें संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार हासिल करने की सैद्धांतिकी लगातार पढ़ाई जा रही है। आज यदि हम इस कथित नागरिक संहिता द्वारा निर्मित पीढ़ी का तटस्थ मूल्यांकन करें तो हमें यह पूरी की पूरी पीढ़ी संकीर्ण, जातीय और सांप्रदायिक संस्कारों में जकड़ी नजर आती है। त्याग, संवेदनशीलता, अपरिग्रह और परोपकार की बजाय यह पीढ़ी संवेदनशून्यता, स्वार्थ और धनलिप्सा में ज्यादा जकड़ी है। दरअसल, कल्याणकारी संस्कार पाठ्यक्रमों में निहित सूचनात्मक संदेशों या उपदेशों की बजाय समाज में मौजूद उदात्त वातावरण से ग्रहण किए जाते हैं। ऐसे में मातृभाषा, साहित्य और मानविकी विषयों के अध्ययन हमारे भीतर वैचारिक ऊर्जा का संचयन करते हैं और इससे उपजी आंतरिक शक्ति हमें समरस समाज बनाने की अंत:प्रेरणा देती है। राजनीतिक चेतना के विकास में भी यह उर्जा संवाहक का काम करती है। लेकिन विचार स्वातंत्र्य को यदि खूंटी से बांध दिया जाएगा तो बौद्धिक-एकरूपता के खतरे बढ़ जाएंगे। अंतत:, भूमण्डलीय आर्थिकी ने इसी एकरुपता को आगे बढ़ाने का काम किया है, जो अब नई शिक्षा नीति में उल्लेखित मातृभाषाओं के प्रावधानों से खंडित होना तय है।

दरअसल, विचार-निर्माण के लिए शैक्षिक परिसरों में लोकतांत्रिक खुलेपन की जरूरत है, जिससे शिष्य, शिक्षक से प्रश्न करने में कोई संकोच न करे। दुर्भाग्यवश हमने आज्ञाकारी शिष्य को आदर्श माना हुआ है। यह आज्ञाकारिता नव-सृजनशीलता के लिए बाधक है। यही कारण है कि हम नवोन्वेष, वैज्ञानिक अनुसंधान और देशज उत्पादकता में पिछड़ते जा रहे हैं। हमारी पूरी शिक्षाजन्य ढांचा, आज्ञापालन को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करता है। स्वंतत्र्य-चेता विद्यार्थी की नूतन पहल, जिज्ञासा और प्रश्नाकूलता को फटकारा जाता है। विचार नियंत्रण की यह क्रूरता नव-सर्जक की भ्रूण हत्या कर देती है। यही कारण है कि हम आजादी के इन 73 सालों में न तो नचिकेता, अष्टावक्र और विवेकानंद पैदा कर पाए और न ही सीवी रमन, जगदीशचंद्र बासु और रामानुजन!

दरअसल औपनिवेशिक शिक्षा पद्धति और अंग्रेजी की अनिवार्यता के चलते हमारे शिक्षा संस्थान महज डिग्रीधारी नकलचियों की फौज खड़ी करने में लगे हैं। वे रोबोट और क्लोन बनाने की दक्षता को ही श्रेष्ठता का पर्याय मानकर चल रहे हैं, क्योंकि रोबोट विरोध नहीं करते और क्लोन से विकसित प्राणी प्रकृति प्रदत्त विलक्षणता खो देते हैं, अतएव उनकी मौलिक सृजनशीलता बचपने में ही कुंठित हो जाती है। आज्ञापालकों के ये उत्पाद अंतत: सृजन से जुड़ी वैचारिकता के लिए आघातकारी सिद्ध होते हैं, केवल कैरियर बनाना और पैसा कमाना इनका मुख्य ध्येय रह जाता है। शिक्षा में भारतीयकरण के नए उपायों से वे सब मिथक टूटेंगे, जो अंग्रेजी की अनिवार्यता के लिए गढ़े गए थे। ◆◆◆

(लेखक, साहित्यकार और वरिष्ठ पत्रकार हैं)

भारत में स्वास्थ्य सेवाएँ सिर्फ बीमारी का इलाज़ करती हैं, रोकती नहीं

– डॉ. चंद्रकांत लहारिया

अभी कोविड -19 की महामारी चल ही रही है, इस बीच केरल में निपाह वायरस का एक मरीज मिला। यह बीमारी आमतौर पर नहीं पाई जाती है। इसलिए, एक भी मरीज का मतलब होता है बीमारी का आउटब्रेक। केरल में 2018 में भी यह बीमारी पाई गई थी और तब 18 में से 17 मरीजों की मृत्यु हो गई थी। लगभग इसी समय उत्तर प्रदेश के कई जिलों से बुखार और शरीर दर्द के साथ अन्य लक्षणों के मरीज दिन – ब – दिन बढ़ने की खबरें आ रही हैं। आधिकारिक रूप से 65 लोग, जिनमें अधिकतर बच्चे हैं, की मृत्यु हो चुकी है। जांच के शुरुआती नतीजे बताते हैं कि ये मरीज डेंगी (आम बोलचाल में डेंगू), मलेरिया , लेप्टोस्पायरोसिस या स्क्रब टाइफस के हैं।

पिछले दो दशकों से सारे विश्व में नई बीमारियां होने लगी हैं और पुरानी बीमारियां नई जगहों पर पांव पसार रही हैं। कई वजहें हैं, जैसे कि जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापमान बढ़ने से परिस्थितियां कई कीटाणुओं और विषाणुओं, जैसे कि डेंगी वायरस, के लिए उपयुक्त होती जा रही हैं। उसी प्रकार, जंगलों में अतिक्रमण और उनकी कटाई की वजह से अब तक जो रोगजनक वनों में रहते थे, जैसे कि निपाह वायरस, उनका सामना मनुष्यों से होने लगा है और नई बीमारियां फैलने लगी हैं। साथ ही गंदगी और संक्रमण का तो पुराना रिश्ता है। स्क्रब टाइफस गंदगी में पाए जाने वाले माईटस से फैलती है और लेप्टोस्पाइरोसिस, इसके बैक्टीरिया से संक्रमित सूअर, कुत्तों और चूहों के मूत्र से पानी के संक्रमित हो जाने पर। इन सब बीमारियों की जल्द पहचान होने के बाद, रोकथाम ही बचाव है। इसके लिए मजबूत जन स्वास्थ्य तंत्र,

पिछले दो दशकों से सारे विश्व में नई बीमारियां होने लगी हैं और पुरानी बीमारियां नई जगहों पर पांव पसार रही हैं।

जिसमें रोग निगरानी तंत्र शुरुआत में ही बीमारी की पहचान कर ले, निहायत जरूरी है। साथ ही, ऐसे सिस्टम के लिए पर्याप्त स्वास्थ्य कार्यकर्ता, नमूनों की जांच के लिए प्रयोगशालाएं जरूरी हैं, जहां समय रहते रिपोर्ट आएं। ऐसा होने के लिए, सरकारों को जन स्वास्थ्य सेवाओं में समुचित निवेश करना होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि भारत में हम जिन्हें स्वास्थ्य सेवाएं कहते हैं, वे दरअसल चिकित्सा सेवाएं मात्र हैं। अंतर यह है कि स्वास्थ्य सेवाएं एक स्वस्थ व्यक्ति को बीमार होने से बचाने के लिए भी कदम उठाती हैं और बीमार का इलाज भी करती हैं, लेकिन चिकित्सा सेवाएं इंतजार करती हैं कि लोग बीमार पड़े, उनका लोगों को बीमारी से बचाने पर ध्यान नहीं होता।

बात फिर से कोविड -19 की करते हैं। बीमारी को पकड़ने और फैलने से रोकने में रोग निगरानी तंत्र की अहम् भूमिका रही। लेकिन चौथे सीरो – सर्वे के नतीजे बताते हैं कि कई राज्यों जैसे कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में औसतन 100 संक्रमण में से मात्र एक ही रिपोर्ट किया गया (अर्थात यहां रोग निगरानी तंत्र कमजोर है), जबकि केरल हर 6 में से एक, महाराष्ट्र 12 में से एक और कर्नाटक 16 में से एक संक्रमण को पकड़ सका। यह राज्यों के बीच में रोग निगरानी तंत्र का अंतर दर्शाता है। अगर रोग निगरानी तंत्र कमजोर है तो जब तक बीमारी को पहचाना जा सकेगा, ये बड़े स्तर पर फैल चुकी होती हैं, जैसे उत्तरप्रदेश में चार बीमारियां एक साथ कई जिलों में फैल चुकी हैं। अगर समय रहते इनकी पहचान की गई होती तो रोकथाम के लिए जरूरी कदमों का पालन करके इन्हें रोका जा सकता था। इसके विपरीत केरल में निपाह वायरस का पहला केस समय रहते पहचान लिया गया।

कोविड -19 महामारी के खत्म होने के बाद इसके भी एंडेमिक हो जाने की बात की जा रही है अर्थात कोरोनावायरस हमारे बीच में रहेगा लेकिन इससे प्रभावित लोगों की संख्या कम होगी और कुछ लोगों में संक्रमण मिलता ही रहेगा। लेकिन क्या हम भविष्य में होने वाले कोविड -19 के ऑउटब्रेक्स को रोक पाएंगे, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि उस राज्य का रोग निगरानी तंत्र कितना क्रियाशील है ? हमें भविष्य के लिए अभी से तैयारी करनी होगी। सभी सरकारों को जन स्वास्थ्य सेवाओं और रोग निगरानी तंत्र में निवेश करना और इन्हें सुदृढ़ करना चाहिए।

◆◆◆

आरती खोसला
निदेशक, क्लाइमेट ट्रेंड्स

अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया सहित कई देशों ने पूर्व - महामारी के स्तरों की तुलना में कम बिजली क्षेत्र से सीओटू उत्सर्जन हासिल किया, जिसमें पवन और सौर ने कोयले की जगह ली, लेकिन ऐसा केवल दबी हुई बिजली की मांग में वृद्धि के संदर्भ में हुआ।

दुनिया में बढ़ती बिजली की माँग के साथ बढ़ रहा कॉर्बन उत्सर्जन

जलवायु परिवर्तनका असर इतना अव्यवस्थित और गहरा होता जा रहा है कि अमेरिका के एक हिस्से में जंगलों में आग और दूसरी तरफ बाढ़ आती है। एक के बाद एक चक्रवाती तूफान आए, इसके अलावा और भी पर्यावरणीय घटनाएं हुई हैं, जिनसे जलवायु परिवर्तन के प्रभाव अब जाहिर हो चुके हैं। मूलभूत आर्थिक गतिविधियों, जैसे बिजली उत्पादन, परिवहन में पर्यावरण संरक्षित रखने और जलवायु परिवर्तन की रोकथाम के लिए कदम उठाना बहुत जरूरी है। मगर, जलवायु परिवर्तन के खिलाफ कदमों में समानता होनी चाहिए क्योंकि किसी को भी एक दूसरे से अलग करके नहीं देखा जा सकता। ऐसे में एनर्जी ट्रॉजिशन या ऊर्जा रूपांतरण आज के समय की मांग है। इसका सरोकार सिर्फ कार्बन न्यूनीकरण से नहीं है, बल्कि इसका संबंध जलवायु के प्रति सतत अर्थव्यवस्था और लोगों से है। 2021 में तेजी से बढ़ते उत्सर्जन को दुनिया भर में खतरे की घंटियों की गूंज की शक्ल में देखना चाहिए।

वैश्विक तापमान को 1.5 डिग्री तक सीमित करने के लिए इस दशक में बहुत तेज एनर्जी ट्रॉजिशन महत्वपूर्ण है। इसकी जरूरत दुनिया भर में हो रही बिजली की खपत और उसके उत्पादन के तरीकों से स्पष्ट होती दिख रही है। एम्बर द्वारा प्रकाशित ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू में 63 देशों के बिजली के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है, जो बिजली की मांग के 87% का प्रतिनिधित्व करते हैं। रिपोर्ट से पता चलता है कि 2021 की पहली छमाही में वैश्विक बिजली क्षेत्र के उत्सर्जन में वापस उछाल आया, जो निम्न स्तर से बढ़ गए हैं, जिससे उत्सर्जन अब पूर्व महामारी के स्तर से 5% अधिक है। महामारी से पहले के स्तर की तुलना में 2021 की पहली छमाही में वैश्विक बिजली की मांग में भी 5% की वृद्धि हुई, जो ज्यादातर पवन और सौर ऊर्जा (5%) से पूरी हुई, लेकिन उत्सर्जन – गहन कोयला बिजली (43%) में भी वृद्धि हुई। गैस लगभग अपरिवर्तित रही, जबकि हाइड्रो और न्यूक्लियर में मामूली गिरावट देखी गई। पहली बार, पवन और सौर ने वैश्विक बिजली के दसवें हिस्से से अधिक उत्पन्न किया। किसी भी देश ने बिजली क्षेत्र में सही मायने में 'ग्रीन रिकवरी' हासिल नहीं की है। कई देशों ने "बिल्ड बैक बेटर" (वापस निर्माण बेहतर) करने और अपनी अर्थव्यवस्थाओं को एक नए ग्रीन नॉर्मल (सामान्य हरित स्थिति) में आगे बढ़ाने का संकल्प लिया है। पर विश्लेषण से पता चलता है कि किसी भी देश ने अभी तक अपने बिजली क्षेत्र के लिए सही मायने में 'ग्रीन रिकवरी' हासिल नहीं की है, जिसमें बिजली की उच्च मांग और कम सीओटू उत्सर्जन के लिए बिजली क्षेत्र में संरचनात्मक परिवर्तन शामिल हैं। हालांकि नार्वे व रूस 'ग्रीन रिकवरी' क्वाडेंट में दिखते हैं, यह अस्थायी कारकों के कारण है। इसमें बिजली क्षेत्र में महत्वपूर्ण संरचनात्मक सुधार के बजाय, बेहतर बारिश से उच्च हाइड्रो बिजली उत्पादन का हाथ ज्यादा है।

अमेरिका, यूरोपीय संघ, जापान और कोरिया सहित कई देशों ने पूर्व – महामारी के स्तरों की तुलना में कम बिजली क्षेत्र से सीओटू उत्सर्जन हासिल किया, जिसमें पवन और सौर ने कोयले की जगह ली, लेकिन ऐसा केवल दबी हुई बिजली की मांग में वृद्धि के संदर्भ में हुआ। बिजली की बढ़ती मांग वाले देशों में भी उच्च उत्सर्जन देखा गया, यहां कोयला उत्पादन के साथ – साथ पवन और सौर में भी वृद्धि हुई। ये 'ग्रीन रिकवरी' देश ज्यादातर एशिया में हैं, जिनमें चीन, बांग्लादेश, भारत, कजाकिस्तान, मंगोलिया, पाकिस्तान और वियतनाम शामिल हैं। इन देशों ने अभी तक उत्सर्जन और बिजली की मांग में वृद्धि को एक दूसरे से अलग नहीं किया है, जो बहुत जरूरी है ।

◆◆◆

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय आईटी कम्पनी

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज

टीसीएस अपने ग्राहकों के लिए गहरी प्रतिबद्धता, व्यापक उद्योग विशेषज्ञता तथा नवाचार और वितरण केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से उच्चतम स्तर की संतुष्टि सुनिश्चित करने में विशेष ध्यान देती है। अपने ग्राहकों को नवीन एवं सर्वोत्तम परामर्श, सूचना तकनीकी सेवाएं और समाधान द्वारा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कराना तथा सभी हितधारकों को आनंदपूर्ण वातावरण प्रदान करना ही कंपनी का प्रमुख उद्देश्य है।

आलोक रंजन तिवारी

टा कंसल्टेंसी सर्विसेज आईटी सेवा, कंसल्टिंग और व्यावसायिक समाधान प्रदान करने वाली विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय कंपनियों में से एक है। टीसीएस पिछले 50 से अधिक वर्षों से दुनिया के कई बड़े व्यवसायों की शानदार परिवर्तन यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। टीसीएस व्यापार, प्रौद्योगिकी और इंजीनियरिंग सेवाओं और समाधानों का एक परामर्श-आधारित एकीकृत पोर्टफोलियो प्रदान करती है। यह अपने अद्वितीय लोकेशन इंडिपेंडेंट एजाइल वितरण मॉडल के माध्यम से उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करती है, जिसे सॉफ्टवेयर विकास में उत्कृष्टता के बेंचमार्क के रूप में मान्यता प्राप्त है। भारत की इस बहुराष्ट्रीय कंपनी में दुनिया के 46 देशों के लगभग 5,09,058 कर्मचारी काम करते हैं। कंपनी ने मौजूदा वित्तीय वर्ष में 22.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर का समेकित राजस्व अर्जित किया है।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की स्थापना सन् 1968 में हुई। इसकी शुरुआत टाटा समूह के एक विभाग के तौर पर टाटा कंप्यूटर सेंटर के नाम से हुई। तब इसका मुख्य व्यवसाय अपने ही समूह की अन्य कंपनियों को कंप्यूटर सेवाएं प्रदान करना था। जल्द ही कम्प्यूटरीकरण तथा कंप्यूटर सेवाओं की क्षमताएं उजागर होने लगीं और तब टाटा इलेक्ट्रिक कंपनी के एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ़कीर चंद कोहली को टाटा कंप्यूटर सेंटर का महाप्रबंधक बनाया गया। कुछ ही समय

बाद कंपनी का नामकरण टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेस कर दिया गया। टीसीएस ने अपना पहला सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रोजेक्ट 1974 में आरम्भ किया जब कंपनी ने हॉस्पिटल इन्फोर्मेशन सिस्टम को बुर्होज़ (Burroughs) मीडियम सिस्टम्स कोबोल (COBOL) से बुर्होज़ स्मॉल सिस्टम्स कोबोल में बदल दिया। इस प्रोजेक्ट को पूरी तरह से टीसीएस मुंबई में आईसीएल 1903 कंप्यूटर पर अंजाम दिया गया। 1980 में भारतीय सॉफ्टवेर उद्योग के कुल निर्यात में 63% योगदान टीसीएस और उसकी एक सहयोगी फर्म ने दिया, जबकी अन्य कंपनियों की हिस्सेदारी मात्र 40 लाख डॉलर थी। 1984 में टीसीएस ने सान्ताक्रुज़ इलेक्ट्रोनिक्स एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग ज़ोन, मुम्बई में अपना एक दफ्तर स्थापित किया।

1990 के दशक में टीसीएस के कारोबार में ज़बरदस्त बढ़ोत्तरी हुई, जिसके परिणाम स्वरूप कंपनी ने बड़े पैमाने पर भर्तियाँ की। 1990 के दशक के आरंभिक एवं मध्य के वर्षों में, टीसीएस ने ख़ुद को एक सॉफ्टवेर उत्पाद निर्माता कंपनी के तौर पर पुन: स्थापित किया। 1990 के दशक के आखिरी सालों में, टीसीएस ने तीन आयामों वाली रणनीति का प्रयोग किया – खूब पैसा कमाने वाले नए उत्पादों का विकास करना, घरेलू तथा अन्य तेज़ी से प्रगति करने वाले बाजारों पर कब्ज़ा ज़माना और दूसरी कंपनियों के विलय व अधिग्रहण से अपना आकार बढ़ाना। 1990 के दशक के अंत में ई–बिजनेस पर कंपनी ने ख़ास ध्यान दिया।

जलवायु परिवर्तन पर टीसीएस के सक्रिय रुख और दुनिया भर के समुदायों के साथ पुरस्कृत कार्य ने इसे एमएससीआई ग्लोबल सस्टेनेबिलिटी इंडेक्स और एफटीएसई फॉर गुड इमर्जिंग इंडेक्स जैसे प्रमुख स्थिरता सूचकांकों में स्थान दिलाने में अग्रणी भूमिका निभाई है। टीसीएस अपने ग्राहकों के लिए गहरी प्रतिबद्धता, व्यापक उद्योग विशेषज्ञता तथा नवाचार और वितरण केंद्रों के वैश्विक नेटवर्क के माध्यम से उच्चतम स्तर की संतुष्टि सुनिश्चित करने में विशेष ध्यान देती है। अपने ग्राहकों को नवीन एवं सर्वोत्तम परामर्श, सूचना तकनीकी सेवाएं और समाधान द्वारा व्यावसायिक लक्ष्यों को प्राप्त कराना तथा सभी हितधारकों को आनंदपूर्ण वातावरण प्रदान करना ही कंपनी का प्रमुख उद्देश्य है।

8 अक्टूबर, 2020 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में एक्सेंचर को पीछे छोड़ते हुए 144.73 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई। 25 जनवरी, 2021 को टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने फिर से एक्सेंचर को बाजार पूंजीकरण में पीछे छोड़ दिया और 170 बिलियन डॉलर की मार्केट कैप के साथ दुनिया की सबसे मूल्यवान आईटी कंपनी बन गई। उसी दिन टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज भारत की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई, जब उसने 12.55 लाख करोड़ की मार्केट कैप के साथ रिलायंस इण्डस्ट्रीज लिमिटेड को पीछे छोड़ दिया।

दुनिया भर में टीसीएस के ग्राहकों ने विश्वस्तरीय समाधानों का उपयोग कर महत्वपूर्ण व्यावसायिक परिणाम प्राप्त किए हैं। यूरोप के सबसे बड़े सेवा प्रदाता प्रदर्शन के सर्वेक्षण में टीसीएस को ग्राहक संतुष्टि के मामले में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। यह लगातार तीसरा वर्ष है जब कंपनी ने आईटी सेवा उद्योग के लिए ग्राहक संतुष्टि रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। टीसीएस को टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टिट्यूट द्वारा ग्लोबल टॉप एम्पलॉयर की मान्यता भी प्राप्त है। 2016 में दुनिया भर में 1,072 कंपनियों के अपने मूल्यांकन में, टॉप एम्प्लॉयर्स इंस्टिट्यूट ने टीसीएस को नौ प्रमुख मानव संसाधन

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड, दीर्घकालिक साझेदारी, सहयोगात्मक नवाचार और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के आधार पर आईटी सेक्टर की सर्वाधिक तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली कंपनी है।

(एचआर) क्षेत्रों – प्रतिभा रणनीति, कार्यबल योजना, ऑनबोर्डिंग, सीखने और विकास, प्रदर्शन प्रबंधन, नेतृत्व विकास, कैरियर और उत्तराधिकार प्रबंधन, मुआवजा और लाभ तथा कंपनी संस्कृति के मामले में एक असाधारण प्रदर्शनकर्ता का दर्जा प्रदान किया।

मौजूदा दौर में टीसीएस अपने कर्मचारियों के बीच व्यापक सहयोग और जुड़ाव सुनिश्चित करने के लिए आंतरिक सामाजिक प्लेटफॉर्म का उपयोग कर एक हाइपर कनेक्टेड कंपनी बनने की दिशा में अग्रसर है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज उत्कृष्ट ट्रैक रिकॉर्ड, दीर्घकालिक साझेदारी, सहयोगात्मक नवाचार और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी के आधार पर आईटी सेक्टर की सर्वाधिक तीव्र गति से आगे बढ़ने वाली कंपनी है।

देश की इस सबसे बड़ी आईटी कंपनी में 5 लाख से भी ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं। इसके साथ ही टीसीएस अब इंडियन रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा लोगों को नौकरी देने वाली दूसरी बड़ी नियोक्ता बन गई है। टीसीएस वित्त वर्ष 2022 में भी 40,000 फ्रेशर्स को नौकरी देने वाली है। टीसीएस केवल भारत तक ही सीमित रहने वाली कंपनी नहीं है। चूंकि, यह कंपनी बड़ी संख्या में फ्रेशर्स को नौकरी देती है, इसीलिए कंपनी ने ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इन्फ्रास्ट्रक्चर पर जबरदस्त निवेश कर रखा है ताकि कम समय में ही फ्रेशर्स को प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जा सके। ऐसी सुविधा के लिए टीसीएस फ्रेस्कोप्ले प्लेटफॉर्म की मदद लेती है। इसके तहत फ्रेशर्स के लिए व्यक्तिगत रूप से ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार किया जाता है। कंपनी की कोशिश होती है कि फ्रेशर्स को कम से कम समय में प्रोजेक्ट के लिए तैयार किया जाए। ◆◆◆

हमारे लिए सुरक्षा और विश्वास सबसे अनिवार्य विषय है : उज्ज्वल माथुर

उज्ज्वल माथुर
वाइस प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड
टाटा कंसलटेंसी सर्विसेज

उज्ज्वल माथुर वर्तमान में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में वाइस प्रेसिडेंट एवं कंट्री हेड (इंडिया बिजनेस) हैं और वह टीसीएस के साथ विगत 24 वर्षों से जुड़े हुए हैं। वर्तमान में वह ग्राहक संबंधी बिक्री एवं संचालन का प्रबंधन सँभालते हैं और टीसीएस की सहायक कंपनियों के बोर्ड में भी हैं। इसके पहले उज्ज्वल टीसीएस बोस्टन क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक थे और उन्होंने अमेरिका के न्यू इंग्लैंड क्षेत्र में ग्राहकों के साथ रणनीतिक संबंध स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वह एपीएसई क्षेत्र के लिए ई-बिजनेस प्रैक्टिस डायरेक्टर भी रह चुके हैं और उन्होंने इस क्षेत्र में कई वैश्विक ग्राहकों के लिए टीसीएस को उत्कृष्ट परिवर्तन लाने वाले भागीदार के रूप में स्थापित करने का शानदार काम किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स में स्नातक की डिग्री और आईआईएम कोलकाता से कार्यकारी प्रबंधन की डिग्री प्राप्त करने वाले उज्जवल माथुर को आईटी सेक्टर में बहुत ही शालीन और विनम्र व्यक्ति के रूप में देखा जाता है। उत्कृष्ट प्रबंधन को आकार देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं है। अभ्युदय वात्सल्यम् के प्रधान सम्पादक आलोक रंजन तिवारी ने उज्ज्वल माथुर से अनेक विषयों पर विस्तार से बातचीत की। प्रस्तुत है बातचीत के प्रमुख अंश –

● **टीसीएस ने एक नवोन्मेषी बिजनेस मॉडल बनाने में मदद करने के लिए सोनीलिव के साथ रणनीतिक साझेदारी की है। इस साझेदारी के दूरगामी परिणाम क्या होंगे ?**

सोनीलिव के साथ इस रणनीतिक साझेदारी का मकसद ओटीटी स्ट्रीमिंग मंच को एक अभिनव व्यवसाय मॉडल बनाने में मदद करना और ग्राहक अनुभव को बेहतर बनाना है। इस साझेदारी की मदद से सोनीलिव के लिए भविष्य में वृद्धि का रास्ता आसान होगा और वह डिजिटल प्रौद्योगिकी की मदद से चुनौतियों का सामना कर सकेगी। साझेदारी से सोनीलिव को टीसीएस की अगली पीढ़ी की डिजिटल क्षमताओं, वैश्विक

विशेषज्ञता, डोमेन ज्ञान और नवाचार परिवेश का लाभ मिलेगा। यह सोनीलिव को कॉन्टेंट मॉनेटाइज करने और नये आर्थिक स्त्रोत बनाने के लिए डेटा और इनसाइट्स का उपयोग करने में भी मदद करेगा। इसके अतिरिक्त, टीसीएस अपनी इनोवेशन लैब का लाभ उठाते हुए एक विश्व स्तरीय एक्सपीरियंस डिजाइन सेंटर स्थापित करेगी, जहां यह तेजी से प्रोटोटाइप करके और सोनी लिव को सर्वश्रेष्ठ सुविधाओं को लॉन्च करने में मदद करने के लिए अपने लोकेशन इंडिपेंडेंट एजाइल मॉडल को नियोजित करेगी। यह साझेदारी सोनीलिव को ग्राहक अनुभव और जुड़ाव को नवीन स्वरुप प्रदान करने, अपने ब्रांड को बढ़ाने, बाज़ार में प्रतिस्पर्धी विशेषज्ञता स्थापित करने और विकास को गति देने में मदद करेगी।

- **कोरोना महामारी ने आपके व्यवसाय को किस तरह प्रभावित किया है ?**

मूल रूप से महामारी ने हम सभी को किसी न किसी रूप में प्रभावित किया है। चाहे वह व्यावसायिक रूप से प्रभावित किया हो, मानसिक रूप से प्रभावित किया हो या भावनात्मक रूप से। लेकिन व्यवसाय संचालन के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे व्यावसायिक संचालन पर काफी हद तक सीमित प्रभाव पड़ा है। यदि आप हमारे आंकड़ों पर नजर डालें तो सभी कार्यक्षेत्रों ने अच्छी वृद्धि हासिल की है। विकास और परिवर्तन थीम को मजबूत करने से कई सेवाओं की त्वरित मांग बढ़ी है। मौजूदा तिमाही में क्लाउड प्लेटफॉर्म सेवाओं, साइबर सुरक्षा, विश्लेषण अंतर्दृष्टि और उद्यम अनुप्रयोग सेवाओं द्वारा वृद्धि दर्ज की गई है।

- **टीसीएस की मौजूदा हायरिंग योजनाएँ क्या हैं ?**

हम निश्चित रूप से नये कर्मचारियों की भर्ती करते रहेंगे। 30 जून, 2021 की स्थिति के अनुसार 5,09,058 कर्मचारियों के साथ वित्त वर्ष 2022 की पहली तिमाही में टीसीएस कर्मचारियों की संख्या 5 लाख का आंकड़ा पार कर गई है। पहली तिमाही में कंपनी में 20,409 अतिरिक्त कर्मचारी जुड़े और कंपनी के कुल कर्मचारियों में महिलाओं की भागीदारी 36.2 प्रतिशत है। वहीं, टीसीएस के कर्मचारी साल-दर-साल 17.3 प्रतिशत बढ़े हैं। हमारी कम्पनी के कार्यबल में व्यापक विविधता है। 4,78,000 से अधिक कर्मचारियों को एजाइल तरीके से प्रशिक्षित किया गया है और 4,07,000 से अधिक कर्मचारियों को कई नई तकनीकों का प्रशिक्षण दिया गया है।

- **हम सभी ने इस महामारी के दौरान वर्चुअल हायरिंग, रिमोट वर्किंग और रिमोट इंटर्नशिप जैसे कई नये चलन देखे। क्या आपको लगता है कि ये चीजें महामारी के बाद भी जारी रहेंगी ?**

सेक्योर बॉर्डरलेस वर्कस्पेसेस (SBWS) और 25 /25 हमारा थीम है। हमें विश्वास है कि यह क्लाउड पर प्रतिभा की व्यापक दृष्टि के साथ गेम चेंजर साबित होगा। हम दुनिया में कहीं से भी, किसी भी कार्य को मूर्त रूप देने के लिए सही कौशल वाले व्यक्तियों को सक्षम बनाने के संरचित तरीकों पर काम कर रहे हैं और अभी भी निश्चित रूप से अपने ग्राहकों की प्रतिबद्धताओं पर खरा उतर रहे हैं। सेक्योर बॉर्डरलेस वर्कस्पेसेस किसी संकट की अल्पकालिक प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक नई शुरुआत है। व्यवसायों के काम करने और प्रबंधित करने के ये नए तरीके संकट के परिणामों से न केवल निपटने के लिए, बल्कि परिवर्तन में तेजी लाने के लिए एक अच्छा अवसर प्रदान कर रहे हैं। इसलिए वर्चुअल हायरिंग, रिमोट वर्किंग और दूर से लोगों को प्रशिक्षित करते समय इन सभी प्रथाओं का उपयोग जारी रहेगा।

- **कितने कर्मचारी घर से काम कर रहे हैं और उन्हें ऑफिस वापस बुलाने की क्या योजना है ?**

टीसीएस ने कोरोना महामारी को देखते हुए एक सिक्योर सुरक्षा मॉडल विकसित किया जिसे सेक्योर बॉर्डरलेस वर्कस्पेसेस का नाम दिया गया है। मौजूदा दौर में हमारे 98% कर्मचारी टीसीएस के ग्राहकों की सेवा में इसी मॉडल के आधार पर सुरक्षित और सहयोगात्मक तरीके से घर पर बैठकर काम कर रहे हैं। टीसीएस बहुत सारे वित्तीय संस्थानों, बैंकों, बीमा कंपनियों को अपनी सेवाएं प्रदान करती है। इसलिए चाहे बड़े वित्तीय संस्थानों को उत्कृष्ट सेवाएँ प्रदान करना हो या यूरोप की सबसे बड़ी डाक सेवा कंपनी के साथ काम करने की बात हो, हमने इसी सुरक्षा मॉडल के अनुरूप व्यवस्थित और सहयोगात्मक तरीके से काम किया है। इस परिवर्तनकारी मॉडल ने कर्मचारियों के लिए रिमोट एक्सेस को सक्षम बनाया है और व्यवस्थित कार्य आवंटन, निगरानी और रिपोर्टिंग सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त साइबर सुरक्षा ढांचा और सभी परियोजना प्रबंधन प्रथाओं और प्रणालियों की स्थापना की गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि यह कोई अल्पकालिक मॉडल नहीं है, बल्कि हमारे लिए यह एक नई कार्य प्रणाली की शुरुआत है। व्यवसायों के कामकाज और प्रबंधन के ये नए तरीके न केवल संकट के परिणामों से उबरने के लिए बल्कि परिवर्तन में तेजी लाने के लिए बहुत अधिक अवसर प्रदान करेंगे। इसलिए हम महामारी की स्थितियों पर नजर रख रहे हैं और इसी आधार पर निर्णय लेंगे कि ऑफिस कब से शुरू किया जाये या कितने कर्मचारियों को ऑफिस बुलाया जाए।

- **भारत को डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वैश्विक केंद्र बनाने, निवेश, नौकरियाँ और नवाचार सृजित करने में आप किस तरह का अवसर देखते हैं ?**

भारत के पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एनालिटिक्स इनसाइट्स के मामले में ग्लोबल हब बनने के बहुत अधिक अवसर हैं। इस अवसर का लाभ उठाने के लिए सबसे अधिक जरुरी है टैलेंट पूल बनाना, जो डेटा और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस के लिए तैयार रहे। आने वाले समय में नौकरियां तकनीक पर आधारित होंगी। इसलिए, भारत के विकास के लिए डिजिटल कौशल निर्मित करना बहुत महत्वपूर्ण है। डेटा और आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस दुनिया के प्रत्येक देशों के डिजिटल परिवर्तन और आर्थिक सुधार में महती भूमिका निभा रहे हैं। हर उद्योग और क्षेत्रों में हमने पिछले कुछ महीनों में डिजिटल परिवर्तन देखा है। पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर ग्राहकों का काम करने और उनकी सेवा करने के लिए नए तरीकों को तेजी से अपना रहे हैं। नवाचार हर जगह लागू किया जा रहा है और नए

बिजनेस मॉडल खोजे जा रहे हैं और मौजूदा तकनीक अब तक की सबसे विषम परिस्थिति में भी तमाम संस्थानों के परिचालन में सहायक साबित हो रही है।

● बहुत सारे उद्यम अचानक ट्रस्ट और सिक्योरिटी की बात क्यों करने लगे हैं ?

जैसे–जैसे हम हाइब्रिड कार्यक्षेत्र की ओर बढ़ रहे हैं, प्रौद्योगिकियों और प्रौद्योगिकी समाधानों में निवेश करने का महत्व बढ़ रहा है। इसके साथ यह प्राथमिकता और भी बढ़ रही है कि आप ग्राहकों को सुरक्षित वातावरण में सेवाएँ मुहैया करायें। इसलिए ट्रस्ट (विश्वास) और टेक्नोलॉजिज (प्रौद्योगिकियां) शायद कभी भी अधिक महत्वपूर्ण नहीं रहे। अब दुनिया के अधिकांश लोग दूरस्थ रूप से जुड़ रहे हैं, इसलिए साइबर सुरक्षा आज हर संस्थान के लिए रणनीतिक प्राथमिकता है कि वे अपने कार्यबल की गोपनीयता, सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए अपने डेटा की रक्षा करें। महामारी की शुरुआत के बाद से साइबर हमलों में तेजी से वृद्धि हुई है। इस तरह के खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और साइबर हमलों से बचाव के लिए एक मजबूत साइबर सुरक्षा ढांचा और उद्यमों के बीच सहयोग की आवश्यकता है। मौजूदा दौर में सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण चीज है इसलिए इसका महत्व दिन–ब–दिन बढ़ता जा रहा है।

● टीसीएस के लिए ट्रस्ट और सिक्योरिटी कितना महत्वपूर्ण है ?

हमारे लिए सुरक्षा और विश्वास सबसे अनिवार्य विषय है क्योंकि हम दुनिया भर में हजारों ग्राहकों को सेवा प्रदान करते हैं। इसलिए हम उन्हें एक बहुत ही सुरक्षित और भरोसेमंद वातावरण में सेवा प्रदान करने के लिए इसे बहुत गंभीरता से लेते हैं।

● जब कोरोना में कर्मचारियों की छंटनी हो रही थी, वैसी स्थिति में भी टीसीएस का एट्रिशन रेट 8.6 प्रतिशत रहा जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में सबसे कम है। क्या सामान्य स्तर तक इसके बढ़ने की कोई संभावना है ?

टीसीएस की एट्रिशन रेट (छंटनी दर) को कम रखने का श्रेय कंपनी और कर्मचारियों की संलग्नता को जाता है, क्योंकि उन्होंने महामारी के दौरान महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। हमने अपने कर्मचारियों को मानसिक रूप से उत्साहित बनाये रखने के योगा क्लासेस और फूड सेशंस का आयोजन किया। महामारी के दौर में एक जिम्मेदार कंपनी के रूप में हमने बहुत कुछ किया जिससे लोग आपस में जुड़े रहें और इसी वजह से एट्रिशन रेट (छंटनी दर) कम बनाये रखने में हमें मदद मिली। इसके अलावा हमने विशेष रूप से महिला सहयोगियों पर ध्यान केंद्रित किया। इसके लिए हमने कई सत्र आयोजित किये ताकि काम के बीच तनाव से निपटने में आसानी हो। हो सकता है आने वाले समय में एट्रिशन रेट (छंटनी दर) बढ़ जाये लेकिन हमारा ध्यान अपने कर्मचारियों के स्वास्थ्य और उनकी सलामती पर केंद्रित है।

● आपके अनुसार कोरोना महामारी के बाद की दुनिया में बने रहने के लिए हमारे पास किस तरह का कौशल होना चाहिए ?

मेरे हिसाब से सिर्फ 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं और वो हैं – खुद को हमेशा अपडेट रखना, सीखते रहना और अपग्रेड करना तथा अपने ग्राहकों के लिए हमेशा प्रासंगिक बने रहना।

◆◆◆

WITH BEST COMPLIMENTS

FROM A
WELL WISHER

रचनात्मक तरीके से माइक्रोसॉफ्ट इंडिया का नेतृत्व कर रहे हैं

अनन्त माहेश्वरी

तेजी से बदलते सूचना प्रौद्योगिकी के इस दौर में अनन्त माहेश्वरी भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए कुशल और प्रतिभावान कार्यबल के साथ एक गतिशील, अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और मूल्य आधारित व्यावसायिक कार्यप्रणाली को मूर्त रूप दे रहे हैं।

– शिवा तिवारी

अनन्त

माहेश्वरी वर्तमान में माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट हैं। वह माइक्रोसॉफ्ट के समग्र व्यापार, व्यावसायिक विकास, नीति निर्माण और समावेशी विकास जैसे अन्य महत्वपूर्ण प्रबंधन दायित्वों का कुशल निर्वहन करते हैं। अनन्त भारत में सरकारी संस्थाओं और निजी कंपनियों की डिजिटल परिवर्तन की यात्रा में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। वह नैसकॉम कार्यकारी परिषद के सदस्य, सीआईआई की विभिन्न आईटी समितियों के अध्यक्ष और एस्पेन लीडरशिप इंस्टीट्यूट के फेलो के रूप में भी अपनी महत्वपूर्ण सेवाएँ देते हैं। इसके साथ ही साथ अनन्त हिंडाल्को इंडस्ट्रीज के बोर्ड में एक स्वतंत्र निदेशक भी हैं। माइक्रोसॉफ्ट से पहले, अनंत हनीवेल इंडिया के अध्यक्ष के रूप में भी काम कर चुके हैं। अनन्त की योग्यता, पात्रता और उत्कृष्ट व्यावसायिक क्षमता से प्रभावित होकर माइक्रोसॉफ्ट ने अपने भारतीय व्यवसाय का नेतृत्व उनके हाथों में सौंपा है। अनंत माहेश्वरी भारत में माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट, सर्विस और सपोर्ट का व्यापक कार्य देखते हैं और वह कंपनी की प्रगति को रचनात्मक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं।

अनन्त का मानना है कि आईटी बूम को अब डेटा एवं आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस की तरफ ले जाना होगा। इन क्षेत्रों में काफी कुछ निवेश, शोध एवं विकास और कौशल विकास हो रहा है। वह कहते हैं कि डेटा गवर्नेंस को मजबूत करना होगा ताकि इसे सही तरीके से प्रबंधित कर इंडस्ट्री, कारोबारियों, स्टार्टअप, सरकार, एकेडमिक जगत और सबको मिलकर डेटा एवं आर्टिफिसियल इंटेलिजेंस के व्यावहारिक प्रयोग को बढ़ावा देने पर काम किया जा सके।

हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत की प्रमुख आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के साथ आस्ट्रेलिया की एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ऑसग्रिड के साथ एक डील साइन की है। यह डील एक बहुवर्षीय डील है। इन्फोसिस और माइक्रोसॉफ्ट के ऑसग्रिड के साथ डील करने का सबसे बड़ा मकसद ऑसग्रिड के क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन में तेज़ी लाना है। ऑसग्रिड ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी एनर्जी और इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनियों में से एक है। ऐसे में इस डील से उसको काफी फायदा मिलेगा, पर इसी के साथ-साथ माइक्रोसॉफ्ट और इन्फोसिस को भी फायदा होगा।

आज के आईने में माइक्रोसॉफ्ट

माइक्रोसॉफ्ट विश्व की सर्वाधिक लोकप्रिय आईटी कंपनियों में से एक है। यह मुख्य रूप से कम्प्यूटर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में काम करती है और विश्व की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कम्पनी है। माइक्रोसॉफ्ट को एप्पल, एमेजन, गूगल, और फेसबुक इंक के साथ प्रौद्योगिकी के बिग फाइव में से एक माना जाता है। 100 से भी अधिक देशों में फैली इसकी शाखाओं में लगभग 1 लाख 82 हजार से भी अधिक लोग काम करते हैं। यह कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, व्यक्तिगत कम्प्यूटर और सम्बन्धित सेवाओं का विकास, निर्माण, लाइसेंस, समर्थन और बिक्री का काम करती है। इसके सबसे प्रसिद्ध सॉफ्टवेयर उत्पाद ऑपरेटिंग सिस्टम, माइक्रोसॉफ़्ट ऑफिस सूट और इण्टरनेट एक्सप्लोरर और एज वेब ब्राउजर के माइक्रोसॉफ्ट विण्डोज लाइन काफी लोक्रप्रिय रहे हैं।

1990 में माइक्रोसॉफ्ट ने भारत को अपना कार्यक्षेत्र बनाया था। माइक्रोसॉफ्ट भारत स्थित अपने लोकल डेटा सेंटर को अपने वैश्विक डेटा संग्रह की सेवाएं प्रदान करता है ताकि भारतीय नव उद्योग, व्यवसायों और सरकारी संस्थाओं में डिजिटल रूपांतरण की प्रक्रिया को निरंतर आगे बढ़ाया जा सके। आज भारत के 11 शहरों – अहमदाबाद,बेंगलुरु, चेन्नई, नई दिल्ली,गुरुग्राम,नॉएडा, हैदराबाद,कोच्ची, कोलकाता, मुंबई और पुणे में माइक्रोसॉफ्ट की विभिन्न संस्थाओं में 16 हजार से ज्यादा कर्मचारी काम करते हैं जो बिक्री, विपणन, अनुसंधान, विकास और ग्राहक सेवा से संबंधित क्षेत्रों में अपनी सेवाएं निरंतर प्रदान कर रहे हैं। माइक्रोसॉफ्ट प्रत्येक व्यक्ति, संस्था को एक संसाधन युक्त संसार में विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है। पर्यावरण के प्रति अनुकूल व्यवहार और सुरक्षा उपायों में जिम्मेदार बनने की माइक्रोसॉफ्ट की प्रतिबद्धता उसकी कार्यप्रणाली में स्पष्ट तौर पर परिलक्षित होती है। प्रौद्योगिकी का उपयोग कर व्यक्ति और संस्थाओं को उनकी पूरी क्षमता का एहसास कराना, नए व्यवसायों को बढ़ावा देना, एक कुशल कामकाज का वातावरण तैयार करना और सभी को समान अवसर प्राप्त कराने की प्रतिबद्धता ही माइक्रोसॉफ्ट का प्रमुख उद्देश्य है।

माइक्रोसॉफ्ट की कॉरपोरेट नीतियों के केंद्र में दुनिया भर के समुदाय हैं और उनको गुणवत्तापूर्ण सेवाएं प्रदान करना ही इसका लक्ष्य है। माइक्रोसॉफ्ट उन महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण पहल करना चाहता है जो किसी ना किसी कारणवश अपनी नौकरी छोड़कर स्थिरता के दौर में हैं और भविष्य में कार्य करना चाहती हैं। महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाने की इसकी प्रतिबद्धता व्यक्तिगत और संस्थागत स्तरों पर बदलाव करने के पहल से शुरू होती है। यह कम्पनी ऐसे कौशल प्रदान करने के लिए प्रयासरत है जो सभी महिलाओं और युवाओं को उनके कैरियर में स्थिरता लाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाये। माइक्रोसॉफ्ट व्यावसायिक जिम्मेदारियों के साथ-साथ अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों का भी पूरा ख्याल रखता है और यह विभिन्न गैर लाभकारी संस्थाओं को सामाजिक हितों एवं उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान करता है ताकि समाज की बेहतरी के लिए सकारात्मक तरीके से कुछ किया जा सके। ◆◆◆

डेल की स्थापना की संक्षिप्त कहानी

छोटे-से कारोबार से मिली पहली सफलता ने माइकल डेल का आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि सन् 1988 में उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बनाने का साहसिक निर्णय ले लिया। पीसी कम्प्यूटर्स लिमिटेड को उन्होंने डेल कम्प्यूटर्स के नाम से रजिस्टर करवाया और पब्लिक इश्यू के जरिए 80 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए।

– आशुतोष मिश्रा

माइकल डेल
सीईओ, डेल टेक्नोलॉजीज

डेल टेक्नोलॉजीज एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय राउंड रॉक, टेक्सास में है। डेल के उत्पादों में पर्सनल कंप्यूटर, सर्वर, स्मार्टफोन, टेलीविजन, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर सुरक्षा और नेटवर्क सुरक्षा के साथ ही सूचना सुरक्षा सेवाएं भी शामिल हैं। डेल सम्पूर्ण राजस्व के हिसाब से संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे बड़े निगमों की रैंकिंग में 35वें स्थान पर है। डेल तमाम कंपनियों और उद्योग समूहों को बेहतर डिजिटल भविष्य बनाने और उनकी कार्यशैली को बदलने में मदद करती है। यह कंपनी ग्राहकों को डेटा युग के लिए आईटी उद्योग की सबसे व्यापक और नवीन प्रौद्योगिकी तथा विभिन्न

प्रकार की सेवाएँ प्रदान करती है। डेल और ईएमसी के विलय के परिणामस्वरूप 2016 में इसे डेल टेक्नोलॉजीज के रूप में जाना जाने लगा। बहुत कम लोगों को डेल की स्थापना के बारे में पता होगा कि कब और कैसे दुनिया की इस लोकप्रिय कम्पनी की शुरुआत हुई।

दरअसल, अमेरिका के ह्यूस्टन में माइकल नाम के एक लड़के का जन्म हुआ। स्कूल की पढ़ाई के बाद बॉयलॉजी पढ़ने के लिए उसका टेक्सास विश्वविद्यालय में दाखिल हो गया। माता-पिता चाहते थे कि उनका होनहार बेटा डॉक्टर बने। माता-पिता ने उन्हें 15 साल की उम्र में कम्प्यूटर भी लाकर दिया। माइकल की कम्प्यूटर में खासी रुचि थी और फिर एक ही साल बाद माइकल का बॉयलॉजी से मन ऊब गया। माइकल को कम्प्यूटर ज्यादा रोमांचक लगने लगा। माइकल का दिमाग इसमें दौड़ने लगा कि आखिर कम्प्यूटर काम कैसे करता है। माइकल ने अपने कम्प्यूटर के सारे पुर्जे खोलकर देखा कि आखिर यह बना कैसे है। माता-पिता को माइकल का ऐसा करना अजीब भी लगा। एक कंपनी के कम्प्यूटर को खोल देने के बाद माइकल ने दूसरी कंपनी का कम्प्यूटर खरीदकर लाया और उसे भी खोलकर देखा और समझा। दौड़-भाग रंग लाई। माइकल की समझ में आ गया कि कम्प्यूटर कैसे काम करता है और फिर माइकल ने स्टूडेंट रहते हुए डाक टिकट और अखबार बेचकर जो थोड़े बहुत पैसे कमाए थे, उनसे 1984 में यूनिवर्सिटी के अपने कमरे में खुद कम्प्यूटर बनाना शुरू किया। उन्होंने कम्प्यूटर बना भी लिया। माइकल का सोचना था कि ग्राहकों की जरूरत के हिसाब से कम्प्यूटर बनाना चाहिए। माइकल ने कंपनी शुरू कर दी और नाम रखा पीसीज लिमिटेड। माइकल ग्राहकों को सीधे कम्प्यूटर बेचने में विश्वास करते थे इसलिए उनके कम्प्यूटर सस्ते थे। फिर वह ग्राहकों की सुविधा का भी ध्यान रखते थे। तो उनकी तरकीब और कारोबार दोनों चल निकले। 1983 में माइकल ने कंपनी का नाम बदला और नया नाम दिया- डेल कम्प्यूटर कॉर्पोरेशन। धीरे-धीरे कारोबार बढ़ता गया, क्योंकि माइकल डेल के काम करने का तरीका लोगों को बहुत पसंद आया। जब माइकल की उम्र 27 साल थी, तभी उनकी कंपनी की दुनियाभर में धूम मच गई। माइकल डेल दुनिया के सफलतम सीईओ की फोर्ब्स सूची में शामिल हो गए। आज माइकल डेल की कंपनी कम्प्यूटर के साथ अन्य बहुत-सी चीजों का कारोबार भी करती है। यह सब कुछ माइकल डेल के कुशाग्र बुद्धि के कारण संभव हुआ और महत्वपूर्ण बात तो यह है कि माइकल ने जब काम शुरू किया था, तब वह किशोरावस्था में ही थे।

छोटे-से कारोबार से मिली पहली सफलता ने माइकल डेल का आत्मविश्वास इतना बढ़ा दिया कि सन् 1988 में उन्होंने अपने नाम को ब्रांड बनाने का साहसिक निर्णय ले लिया। पीसी कम्प्यूटर्स लिमिटेड को उन्होंने डेल कम्प्यूटर्स के नाम से रजिस्टर करवाया और पब्लिक इश्यू के जरिए 80 मिलियन डॉलर इकट्ठा किए। आगामी चार साल में डेल कम्प्यूटर्स का कारोबार इतना बढ़ गया कि सन् 1992 में माइकल डेल सबसे कम उम्र (27 वर्ष) में ऐसी कंपनी के संस्थापक सीईओ घोषित कर दिए गए, जो दुनिया की 500 बड़ी कंपनियों में एक थी। सन् 1996 में उन्होंने सर्वर लॉन्च किया, अचल सम्पदा क्षेत्र में प्रवेश किया और होम एन्टरटेन सिस्टम व पर्सनल डिवाइसेस भी बनाने लगे। सन् 1998 में अपने व अपने परिवार के निवेश पर अधिकतम मुनाफा कमाने की मंशा से माइकल डेल ने एमएसडी कैपिटल की स्थापना की और शेयरों व सिक्योरिटीज की ट्रेडिंग, प्राइवेट ईक्विटी में लेन-देन व रियल एस्टेट मार्केट में खरीद-फरोख्त करने लगे। माइकल डेल ने सांता मोनिका, न्यू यॉर्क व लंदन में कार्यालय खोलकर उन्हें प्रोफेशनल्स के सुपुर्द किया और खुद वॉच डॉग बनकर दैनिक गतिविधियों से दूर होने लगे। उनके अनुसार, मैंने जो भी कारोबार किया, उसमें ग्राहकों को ऑनलाइन बेहतर सेवा देने की कोशिशों को प्राथमिकता दी है। जो तेज गति से दौड़ते हैं, वे अक्सर दुर्घटना भी कर बैठते हैं। सन् 2010 में निवेशकों को आधी-अधूरी जानकारी देने व अकाउंटिंग में गड़बड़ी के लिए माइकल डेल ने जहां 4 मिलियन डॉलर दंड चुकाया है, वहीं उनके द्वारा स्थापित माइकल सुजैन फाउंडेशन सारी दुनिया खासकर अमेरिका व भारत के बच्चों की शिक्षा व स्वास्थ्य पर अरबों डॉलर खर्च कर रहा है।

तेज चलने वाले जिंदगी के हर मैदान में खेल की तरह दौड़ लगाते हैं। ऐसे लोगों को सही समय पर, सही सुविधा व मार्गदर्शन के साथ मौका मिल जाए तो वे दूसरों से आधी उम्र में शिखर पर पहुंच जाते हैं। नि:संदेह तेज दौड़ लगाने के कारण उनसे चूक भी होती है, पर वे अपनी भूल सुधारने में भी देर नहीं करते। दुनिया के 25 वें सबसे धनी माइकल डेल इसी श्रेणी के सफल उद्यमी हैं। वर्तमान में माइकल, डेल टेक्नोलॉजीज के चेयरमैन और सीईओ हैं।

◆◆◆

भारत में डेल की सफलता के उत्कृष्ट शिल्पकार आलोक ओहरी

भारत में डेल की इनोवेटिव गो-टू-मार्केट रणनीति के शिल्पकार के रूप में पहचाने जाने वाले आलोक ने डेल को सम्पूर्ण तकनीकी समाधान प्रदान करने वाली कंपनी में परिवर्तित कर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जगत में महत्वपूर्ण पहचान बनायी है।

तकनीक की गहरी समझ रखने वाले आलोक ओहरी को एक विजनरी और तेज तर्रार व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। वह बाजार के मूड को भांपने और ग्राहकों की माँग के अनुरूप व्यावसायिक रणनीति बनाने में अत्यंत कुशल हैं। ग्राहकों की बदलती जरूरतों को समय से पहले समझ लेने वाले आलोक ओहरी को आईटी क्षेत्र का दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता कहा जाता है।

आलोक ओहरी वर्तमान में डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक हैं। 2013 में उन्हें डेल के भारतीय व्यवसाय को सँभालने की जिम्मेदारी दी गई थी। वह डेल इंडिया में बिक्री, व्यापार रणनीति एवं विकास, व्यावसायिक संचालन, विपणन और विनिर्माण जैसे महत्वपूर्ण कार्यों का नेतृत्व करते हैं। भारत में डेल की इनोवेटिव गो-टू-मार्केट रणनीति के शिल्पकार के रूप में पहचाने जाने वाले आलोक ने डेल को सम्पूर्ण तकनीकी समाधान प्रदान करने वाली कंपनी में परिवर्तित कर भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी जगत में महत्वपूर्ण पहचान बनायी है। आलोक ओहरी प्रौद्योगिकी, बाजार और व्यापार की गतिशीलता में गहरी रूचि रखते हैं और लीक से हटकर सोचना पसंद करते हैं। आलोक के नेतृत्व में डेल इंडिया वैश्विक स्तर पर डेल के लिए सबसे तेजी से बढ़ने वाला व्यवसाय बन गया है। उन्होंने एक मजबूत और व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र की स्थापना की शानदार पटकथा लिखी है जो डेल इंडिया की सफलता के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। डेल में अपने अब तक के कार्यकाल में उन्होंने

आलोक ओहरी
प्रेसिडेंट एवं एमडी, डेल इंडिया

एक मजबूत और प्रतिभा संपन्न टीम खड़ी कर कंपनी के व्यावसायिक विकास को प्रभावशाली आधार प्रदान किया है।

डेल में शामिल होने से पहले आलोक आईबीएम, एएमडी और ईएमसी जैसी कंपनियों में अहम् पदों पर काम कर चुके हैं। आईटी के क्षेत्र में उन्हें लगभग 3 दशकों का सुदीर्घ अनुभव है। वह कई औद्योगिक निकायों के सदस्य हैं और प्रभावी वक्ता भी हैं। वह एसोचैम की नेशनल काउंसिल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग समिति के अध्यक्ष, नैसकॉम की कार्यकारी परिषद के सदस्य और इंडियन रिटेल फोरम की संचालन समिति के सदस्य भी हैं। 2013 में आईटी उद्योग में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए उन्हें सम्मानित किया गया था और 2019 में मोस्ट इनोवेटिव सीईओ का पुरस्कार भी प्राप्त कर चुके हैं। आलोक भारत सरकार के अटल इनोवेशन मिशन में सुपर मेंटर के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वह शिक्षा के क्षेत्र में नवोन्मेषी स्टार्टअप्स, रिवर्स सप्लाई चेन/लॉजिस्टिक्स, कंज्यूमर रिटेल के सलाहकार बोर्ड में भी शामिल हैं। आलोक डेटा सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बोर्ड में होने के अलावा, डेल टेक्नोलॉजीज इंडिया के बोर्ड में एक स्थायी निदेशक और अध्यक्ष हैं। उत्कृष्ट व्यावसायिक दूरदर्शिता और प्रभावशाली प्रबंधन रणनीति ही एकमात्र कारण है, जिसकी वजह से आलोक ओहरी डेल इंडिया का नेतृत्व पिछले 8 सालों से कर रहे हैं। उनकी इन्हीं व्यावसायिक और तकनीकी कुशलताओं से प्रभावित होकर कंपनी ने उन्हें डेल इंडिया का स्थायी निदेशक बनाया है।

◆◆◆

नवाचार, गुणवत्ता और विश्वसनीयता का पर्याय

फिलिप्स इंडिया

बाजार में फिलिप्स के उत्पादों की भारी माँग है, क्योंकि फिलिप्स ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया है। यह कंपनी उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण में ही यकीन करती है।

– आलोक रंजन तिवारी

किसी भी ब्रांड को बाजार में प्रवेश करने के पहले अपने ग्राहकों से संवाद करना पड़ता है। भावनात्मक रिश्ते बनाने पड़ते हैं। 123 साल पुराने ग्लोबल ब्रांड फिलिप्स ने भारतीय बाजार में प्रवेश किया तो यही किया। आज कई ऐसे भारतीय परिवार हैं, जो शायद ही जानते हैं कि फिलिप्स भारतीय कंपनी नहीं है। लेकिन अपने ग्राहकों के साथ पीढ़ी–दर–पीढ़ी के कालजयी रिश्ते ही सही मायने में फिलिप्स की ब्रांड वैल्यू हैं। 1930 में कोलकाता में एक सेल्स आउटलेट के साथ फिलिप्स ने भारत में प्रवेश किया था। फिलिप्स इंडिया लिमिटेड नीदरलैंड की रॉयल फिलिप्स की एक सहायक कंपनी है, जो लोगों के स्वास्थ्य में सुधार लाने, स्वस्थ जीवनशैली प्रदान करने और रोग के रोकथाम से लेकर निदान, उपचार और घरेलू देखभाल के साथ – साथ स्वास्थ्य निरंतरता को बेहतर बनाने की दिशा में काम करती है। यह कंपनी अपने ग्राहकों को एकीकृत समाधान देने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी, गहन नैदानिक और उपभोक्ता अंतर्दृष्टि का शानदार उपयोग कर डायग्नोस्टिक इमेजिंग, इमेज–गाइडेड थेरेपी, रोगी निगरानी और स्वास्थ्य सूचना विज्ञान के साथ–साथ उपभोक्ता स्वास्थ्य तथा घरेलू देखभाल के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभाती है। डिवाइस, सिस्टम, सॉफ्टवेयर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और उन्नत एनालिटिक्स को एक साथ लाकर, कंपनी अपने ग्राहकों को आधुनिक तकनीक से निर्मित गुणवत्तापूर्ण उत्पाद मुहैया कराती है जो दुनिया भर के उपभोक्ताओं की जीवनशैली को

फिलिप्स इंडिया द्वारा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार और रोग के रोकथाम, निदान और उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए काम किया जा रहा है।

स्वस्थ और शानदार बनाने में मदद करती है। फिलिप्स अस्पतालों और अस्पताल समूहों के साथ दीर्घ रणनीतिक साझेदारी में भी प्रवेश करती है, जिसका उद्देश्य नए व्यापार मॉडल, एकमुश्त लेनदेन और निरंतर संबंधों के आधार पर अस्पतालों को एक समग्र समाधान प्रदान करना होता है। यह साझेदारी अस्पतालों के नैदानिक, परिचालकीय और व्यावसायिक आवश्यकताओं को पूरा करती है।

फिलिप्स द्वारा साउंड एंड विजन, पर्सनल केयर, मदर एंड चाइल्ड केयर, घरेलू उत्पाद, लाइटिंग, स्वास्थ्य और मोटर वाहन से सम्बंधित सैकड़ों उत्पादों का विनिर्माण किया जाता है। बाजार में फिलिप्स के उत्पादों की भारी माँग है क्योंकि फिलिप्स ने अपने उत्पादों की गुणवत्ता से कभी समझौता नहीं किया है। यह कंपनी उच्च गुणवत्तापूर्ण उत्पादों के विनिर्माण में ही यकीन करती है। भारत के बाजारों में फिलिप्स के ब्रांडों को लोग अटूट विश्वास और गुणवत्ता की नजर से देखते हैं। बात चाहे फिलिप्स के रेडियो की हो या टीवी और मॉनिटर की हो, कभी भी फिलिप्स के उत्पादों की माँग में कोई कमी नहीं देखी गई।

फिलिप्स इंडिया लिमिटेड व्यवसाय करने के साथ – साथ सामाजिक जिम्मेदारी को भी बखूबी निभाती है। वर्ष 2019 में फिलिप्स ने निमोनिया के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए एक सीएसआर अभियान 'हर सांस में जिंदगी' की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों के माता–पिता और परिवार तक पहुँचना और निमोनिया की गंभीरता पर उन्हें संवेदनशील बनाना है। निमोनिया 5 वर्ष की आयु तक के बच्चों में फैलने वाले प्रमुख संक्रामक रोगों में से एक है, जो शिशुओं की मृत्यु का एक प्रमुख कारण भी है। निमोनिया की बीमारी और उससे होने वाली मृत्यु, दोनों ही मामलों में विश्व स्तर पर भारत में सबसे अधिक मामले पाये जाते हैं। हर साल 30 मिलियन नए मामलों के साथ लगभग 1.5 लाख बच्चे निमोनिया के कारण अपनी जान गंवाते हैं। निमोनिया भारत में होने वाली सभी मृत्यु में लगभग छठे स्थान पर है जिसमें अधिकतर मामले पांच साल से कम उम्र के बच्चों के होते है। इस बीमारी के कारण हर चार मिनट में एक बच्चा अपनी जान गवां देता है। फिलिप्स इंडिया द्वारा लोगों के स्वास्थ्य में सुधार और रोग के रोकथाम, निदान और उपचार के माध्यम से स्वास्थ्य प्रणाली को सक्षम बनाने के लिए काम किया जा रहा है। फिलिप्स इंडिया का इस अभियान ने न केवल लोगों को इस बीमारी के बारे में जागरूक करने का काम किया है बल्कि बच्चों के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में भी महत्वपूर्ण सहयोग सुनिश्चित किया है।

◆◆◆

बेमिसाल नेतृत्व क्षमता के धनी

डेनियल मेजोन

डेनियल मेजोन ने ऐसे समय में फिलिप्स इंडिया का नेतृत्व संभाला जब कंपनी लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में तमाम चुनौतियों का सामना कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी उत्कृष्ट योग्यता, पात्रता और क्षमता के माध्यम से फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को शानदार मुकाम पर पहुँचाने का अत्यंत सराहनीय कार्य किया है।

डेनियल मेजोन, फिलिप्स भारतीय उपमहाद्वीप के वाइस चेयरमैन और मैनेजिंग डॉयरेक्टर हैं। उनके पास हेल्थकेयर इंडस्ट्री में लगभग 2 दशकों का सुदीर्घ अनुभव है। रॉयल फिलिप्स में अपने नौ वर्षों के अब तक के कार्यकाल में डेनियल ने महत्वपूर्ण भूमिकाओं का निर्वहन किया है। भारत आने से पहले वह लैटिन अमेरिका में फिलिप्स हेल्थकेयर के उपाध्यक्ष और महाप्रबंधक थे। वहाँ उन्होंने कंपनी के स्वास्थ्य सेवाओं का नेतृत्व किया। डेनियल ने अपने शानदार नेतृत्व कौशल के माध्यम से लैटिन अमेरिका के बाजारों में फिलिप्स के उत्पादों को लोकप्रिय बनाने में कोई कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने फिलिप्स का नेतृत्व करते हुए मार्केटिंग और ग्राहक सेवाओं को रोचक प्रारूप में बदलकर तमाम उपलब्धियाँ अर्जित की है। फिलिप्स में अपने कैरियर की शुरुआत करने से पहले डेनियल मेजोन जीई हेल्थकेयर में 12 साल तक काम कर चुके हैं। वह जीई हेल्थकेयर में कंपनी के संचालन से लेकर प्रोडक्ट डेवलपमेंट, सेल्स – मार्केटिंग,

गुणवत्ता और व्यावसायिक रणनीति सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी संभाल चुके हैं।

डेनियल मेजोन ने आधिकारिक रूप से 3 अक्टूबर, 2017 को फिलिप्स इंडिया लिमिटेड के उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक की जिम्मेदारी संभाली। लगभग 4 साल की अपनी अब तक की भारतीय पारी में डेनियल ने तमाम नए उत्पादों को बाजार में उतारने से लेकर बिक्री और विपणन से सम्बंधित अनेक विषयों पर विशेष ध्यान दिया है। स्वभाव से सरल और सहज रहने वाले डेनियल मेजोन के चेहरे पर मुस्कराहट बनी रहती है। वह अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों के बीच काफी लोकप्रिय भी हैं। डेनियल ने ऐसे समय में फिलिप्स इंडिया का नेतृत्व संभाला जब कंपनी लोगों को स्वस्थ जीवनशैली और सस्ती स्वास्थ्य सेवाएँ उपलब्ध कराने में तमाम चुनौतियों का सामना कर रही थी। लेकिन उन्होंने अपनी योग्यता, पात्रता और क्षमता के माध्यम से फिलिप्स इंडिया लिमिटेड को शानदार मुकाम पर पहुँचाने का अत्यंत सराहनीय कार्य किया। आज व्यापक स्तर पर लाखों – करोड़ों भारतीयों तक फिलिप्स के उत्पादों की पहुँच है।

कोरोना महामारी के बीच भी डेनियल के नेतृत्व में कंपनी ने शानदार काम किया। कंपनी के कनेक्टेड केयर सॉल्यूशंस की मांग में लगातार इज़ाफा देखने को मिला। इस सेक्टर में यह कंपनी पब्लिक–प्राइवेट–पार्टनरशिप (पीपीपी) के तहत काम कर रही है और इसके पहले से ही फिलिप्स करीब 100 पीपीपी प्रोजेक्ट्स में शामिल है। कंपनी का लक्ष्य ऐसी पार्टनरशिप को बढ़ाकर 200 तक ले जाने का है। फिलिप्स ने पुणे में हेल्थकेयर इनोवेशन सेंटर बनाया है। इसका इस्तेमाल दुनिया के तमाम देशों में निर्यात के लिए हब के तौर पर किया जा रहा है। कंपनी कई और तरह के उत्पादों को भी भारत से निर्यात करने के बारे में सोच रही है। डेनियल ने अपने प्रभावी नेतृत्व के माध्यम से भारत में फिलिप्स के समग्र व्यावसायिक विकास को नई ऊँचाई प्रदान की है। बेहद कम समय में ही वह भारतीय बाजारों में होने वाले उतार – चढ़ाव को समझ गये।

डेनियल मेजोन के पास टेक्सास ए एंड एम यूनिवर्सिटी से इंजीनियरिंग में स्नातक की डिग्री है। उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी जनरल मैनेजमेंट प्रोग्राम से एक्जीक्यूटिव डिग्री और मियामी यूनिवर्सिटी से एग्जीक्यूटिव एमबीए की डिग्री प्राप्त है। अपने खाली समय में मेजोन अपने परिवार के साथ समय बिताने तथा सॉकर, स्कूबा डाइविंग और गोल्फिंग सहित अपने पसंदीदा खेलों का अभ्यास करने का आनन्द लेते हैं।

◆◆◆

रवि दोशी
डायरेक्टर, ओसवाल इंडस्ट्रीज

व्यावसायिक उत्कृष्टता के प्रबल पक्षधर

रवि दोशी

- संजय सिंह

रवि दोशी ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक (विपणन) हैं। वह मुंबई स्थिति ओसवाल समूह के क्षेत्रीय कार्यालय से कंपनी के विपणन सम्बन्धी कार्यों को संपन्न करते हैं। रवि ने लंदन मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी से मास्टर्स (इंटरनेशनल बिजनेस) की डिग्री, कील यूनिवर्सिटी–जर्मनी से सर्टिफिकेट कोर्स और यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से बीईसी सर्टिफिकेशन प्राप्त किया है। वह कुशल तरीके से जर्मन, स्पेनिश और इतालवी भाषा समझते और बोलते हैं। उन्हें विश्व स्तर पर तेल, गैस और ऊर्जा के विपणन के क्षेत्र में 18 से अधिक वर्षों का सुदीर्घ अनुभव है। रवि की रचनात्मक उद्यमशीलता और प्रभावी नेतृत्व क्षमता ने ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को राष्ट्रीय स्तर पर शीर्ष वाल्व निर्माता के रूप में उभरने में मदद की है और इसे वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त ब्रांड बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है।

उच्च शिक्षित एवं कुशल विपणन रणनीतिकार रवि दोशी के नेतृत्व में ओसवाल समूह से सम्बंधित सभी कंपनियों ने शानदार सफलता प्राप्त की है। रवि ओसवाल समूह के व्यापारिक सम्बन्धों की मजबूती के लिए ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री के सभी दिग्गज व्यक्तियों के जुड़े हुए हैं। वह कम्पनी के वैश्विक अधिग्रहण और प्रौद्योगिकी साझेदारी का भी काम देखते हैं। बातचीत में उन्होंने बताया कि व्यावसायिक गतिविधियों के कारण वह दुनिया के कई देशों की यात्रा करते रहते हैं। लेकिन, जब से कोरोना महामारी ने अपने पैर फैलाये हैं तब से वह किसी भी विदेशी यात्रा पर नहीं जा रहे हैं।

रवि दोशी ने अपने बहुआयामी नेतृत्व कौशल के माध्यम से ओसवाल समूह की अन्य कंपनियों के व्यावसायिक विकास को प्रभावी रूप में आगे बढ़ाया है। उन्होंने ओसवाल इंफ्रास्ट्रक्चर्स लिमिटेड (ईपीसी कंपनी), मेटल फोर्ज इंडिया (स्पूल, पाइप, फिटिंग और फ्लैंग्स कंपनी) और भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक चिकित्सा केंद्रों में से एक निम्बा नैचुरोपैथी को व्यावसायिक धरातल पर स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

> **“ रवि दोशी की रचनात्मक उद्यमशीलता और प्रभावी नेतृत्व क्षमता ने ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भारत में शीर्ष वाल्व निर्माता के रूप में उभरने में मदद की है और इसे वैश्विक स्तर पर भी मान्यता प्राप्त ब्रांड बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है।**

ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड

ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड दुनिया की उन चंद कंपनियों में से एक है जो गेट, ग्लोब, चेक एंड बॉल, क्रायोजेनिक और प्रेशर सील वाल्व के अग्रणी निर्माता के रूप में पिछले 4 दशकों से व्यावसायिक स्तर पर सक्रिय है। बाजार में ओसवाल के वाल्वों की भारी माँग है। एबीबी, ओएनजीसी, भारत पेट्रोलियम, हनीवेल, इंडियन ऑयल, कुवैत ऑयल कम्पनी समेत देश और दुनिया की सैकड़ों कम्पनियाँ ओसवाल की नियमित ग्राहक हैं।

ओसवाल द्वारा एएसटीएम, डीआईएन, एनएसीई, बीएस और जेआईएस मानकों पर खरा उतरने वाले वाल्वों के लिए हेस्टलॉय, इनकोनेल, मोनेल, प्रीसिपिटेटिंग हार्डनिंग एलॉयज, स्टेनलेस स्टील, लो अलॉय स्टील और कार्बन स्टील की कास्टिंग का विनिर्माण भी किया जाता है।

ओसवाल इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड

भारत के बुनियादी ढांचे के विकास में योगदान करने की दृष्टि से स्थापित यह कम्पनी ओसवाल इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 100% स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो पिछले तीन दशकों से भारत और अन्य देशों की प्रमुख औद्योगिक निकायों को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद एवं सेवाएं प्रदान कर रही है। हाल के वर्षों में, भारत ने बिजली एवं ऊर्जा, तेल एवं गैस, रिफाइनरियों, सिटी गैस वितरण, परिवहन, संचार और सभी प्रमुख क्षेत्रों में उल्लेखनीय वृद्धि देखी है।

मेटल फोर्ज इंडिया

कम्पनी के विजनरी नेतृत्वकर्ता पारस दोशी द्वारा 1979 में स्थापित मेटल फोर्ज इंडिया ने किफ़ायती और गुणवत्तापूर्ण पाइप फिटिंग के आपूर्तिकर्ता के रूप में व्यावसायिक जगत में शानदार प्रतिष्ठा अर्जित की है। इस कम्पनी की मुख्य विशेषता जो उसे दूसरों से अलग खड़ा करती है, वह है उच्च व्यावसायिक मूल्य और ग्राहक संतुष्टि। मेटल फोर्ज ने कभी भी अपने व्यावसायिक हितों की पूर्ति के लिए कंपनी के मूल्यों – सिद्धांतों से समझौता नहीं किया है। जिस दौर में लोग अपने आर्थिक हितों को पूरा करने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं, उस दौर में मेटल फोर्ज की व्यावसायिक ईमानदारी इसे विश्वसनीय ब्रांड बनाने में महती भूमिका निभा रही है।

निम्बा नेचर क्योर

प्राचीन भारतीय शास्त्रों में निम्बा को एक लौकिक वृक्ष बताया गया है जिसमें स्वास्थ्य लाभ के असीम तत्व मौजूद हैं। इसे पौष्टिक और चिरस्थायी स्वास्थ्य का परिचायक भी कहा जाता है। भारत के सबसे बड़े प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र के रूप में निम्बा नेचर क्योर मन, मस्तिष्क और शरीर के तालमेल से तमाम बीमारियों का उपचार करता है। यह गुजरात के मेहसाणा जिले में स्थित है। ओसवाल समूह द्वारा संचालित इस नेचर क्योर में लगभग 300 लोग काम करते हैं। यह पूरी तरह गैर – लाभकारी संस्था है। यहाँ पर देश – विदेश के अलग – अलग जगहों से लोग आते हैं और शांत वातावरण में कई दिनों तक रहते हैं। प्रचुर हरियाली और वातावरणीय शुद्धता से परिपूर्ण यह नेचर क्योर प्राकृतिक शक्तियों को अत्यधिक महत्त्व देता है। निम्बा नेचर केयर जीवन के पांच बुनियादी तत्वों – पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश के महत्वपूर्ण संतुलन को बनाये रखने के लिए प्रतिबद्ध है। यहाँ कुशल पेशेवरों द्वारा शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य का समन्वेषण किया जाता है। ◆◆◆

Our learning is best when it teaches humanity but to be proud of learning is the greatest ignorance in the world.

With Best Compliments from

Umesh Gandhi

Builders & Developers

DEEPAK BUILDERS

POONAM BUILDERS

AVON BUILDERS

GEETA BUILDERS

DEEPDHARSHAN BUILDERS PVT. LTD.

JITEN AGRO LAND & FARM PVT. LTD.

SUNCITY LAND & INFRASTRUCTURE PVT.LTD

SUNRISE PARTY HALL

Builders, Developers & Hospitality Business

Office: B/203 Goyal Shopping Arcade, S.V.Road, Borivali (West), Mumbai - 400 092.

Tel No. 022 - 61363636 Fax No. 022 - 61363600

Email :- poonambuilders@gmail.com

डैनियल क्रेग अपनी आखिरी बॉन्ड फ़िल्म 'नो टाइम टू डाय' को लेकर चर्चा में

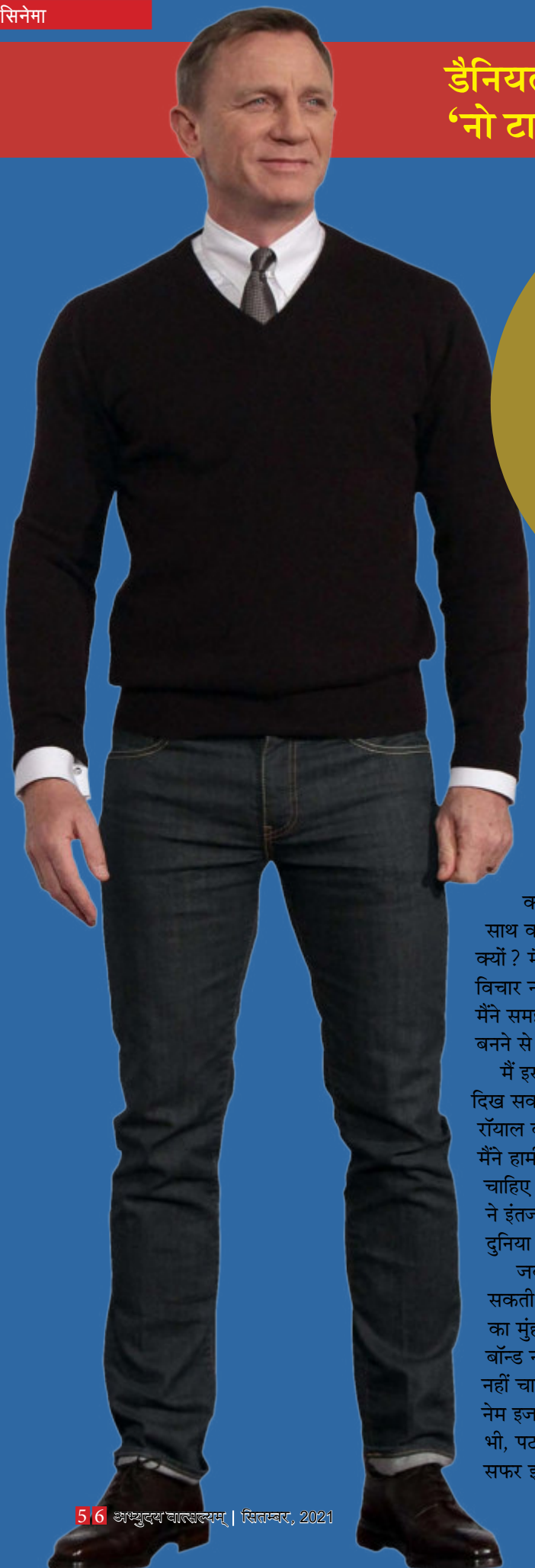

खुद को कीमती बनाने का एक ही काम है बेशकीमती काम करें

मेरी अजीज एक दोस्त थीं, जो कास्टिंग डायरेक्टर भी रहीं। उन्हीं ने मुझे ड्रामा स्कूल में काफी कुछ सिखाया था, उनका तरीका आक्रामक था, लेकिन वे बहुत ध्यान रखनी वाली भी थीं। जब वो नहीं रहीं तो मैं उन्हें कांधा देने गया था। वहां मेरी मुलाकात बारबरा ब्रोकली से हुई। बारबरा बॉन्ड फिल्मों की निर्माता हैं। वो मुझसे आगे होकर मिलीं। मैं यह बात भूल भी गया। लगभग छह महीने बाद उनका मुझे कॉल आया कि क्या हम कॉफी पर मिल सकते हैं? मैंने उन्हें हां कह दिया। जब हम मिले तो उन्होंने सीधे कहा– क्या तुम अगले जेम्स बॉन्ड बनना चाहोगे? मेरे भाव ऐसे थे जैसे मेरे साथ कोई मजाक हो रहा है ... मैंने उसी लहजे मैं खुद से सवाल किया .... मैं ही क्यों? मैंने उनसे कहा कि मैंने कभी किसी इंटरनेशनल स्क्रिप्ट पर काम करने पर विचार नहीं किया। उन्होंने कसीनो रॉयाल की पटकथा मुझे दी जिसे दस मिनट में मैंने समझा और उसके लिए तैयार हो गया। बाद में मैंने सोचा कि आखिर मैं बॉन्ड बनने से हिचक क्यों रहा था। दरअसल मैं नकल करने से डर रहा था।

मैं इस फिल्म में पियर्स (ब्रॉसनन) नहीं बन सकता था ना ही शॉन (कॉनरी) दिख सकता था। मैं यहां केवल वही करना चाहता था जो मैं हूँ। जैसे ही मैंने कसीनो रॉयाल की स्क्रिप्ट पढ़ी, मुझे समझ में आ गया कि मैं इसे कैसे निभाऊंगा और मैंने हामी भर दी। नकल आपको सीमित कर देती है, इससे हमेशा बचकर रहना चाहिए। इसके बाद भी मैंने करीब साल भर लिया खुद को तैयार करने में। बारबरा ने इंतजार किया ... और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। मुझे पता था कि इसके बाद मेरी दुनिया बदलने वाली है। इसकी तैयारी में कोई कोताही नहीं बरती।

जब पूरी तरह तैयार हुआ तब ही काम शुरू किया। तैयारी हड़बड़ी में नहीं हो सकती थी, तैयारी को भी वक्त चाहिए। खुद को तैयार करने के लिए कभी वक्त का मुंह नहीं देखना चाहिए। मैंने निर्माताओं से साफ कह दिया था कि मैं ऐसे ही बॉन्ड नहीं बनूंगा। मैंने उनसे इजाजत मांगी कि मुझे हर चीज में शामिल करें। मैं नहीं चाहता था कि मैं सेट पर जाऊं और केवल यह बोल के घर आ जाऊं कि माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड। मुझे तो हर चीज के मायने जानने थे। मैंने यही किया भी, पटकथा से लेकर फिल्मांकन तक बॉन्ड फिल्मों को जाना। तभी शायद यह सफर इस तरह से पूरा हो पाया है। ◆◆◆

(द न्यू यॉर्कर फेस्टिवल के मंच पर डॅनियल क्रेग)

महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये एक साल तक नहीं हो सकता इंतजार : सुप्रीम कोर्ट

उच्चतम न्यायालय ने एनडीए की प्रवेश परीक्षा में महिला उम्मीदवारों को अगले साल से शामिल करने की अनुमति देने के केंद्र के अनुरोध को खारिज कर दिया। शीर्ष अदालत ने कहा कि वह नहीं चाहती कि महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया जाए तथा महिलाओं को एनडीए में शामिल करने के लिये एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती।

केंद्र ने शीर्ष अदालत को बताया था कि महिला उम्मीदवारों को राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में प्रवेश परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाली अधिसूचना अगले साल मई तक जारी की जाएगी। न्यायमूर्ति एस के कौल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि आपातकालीन स्थितियों से निपटने के लिए सशस्त्र बल सबसे अच्छी प्रतिक्रिया टीम है और उम्मीद है कि बिना देरी किए महिलाओं को एनडीए में शामिल करने का मार्ग प्रशस्त करने के लिए आवश्यक व्यवस्था की जाएगी।

न्यायालय ने कहा कि रक्षा विभाग को यूपीएससी के सहयोग से जरूरी काम करना चाहिए। शीर्ष अदालत ने याचिकाकर्ता कुश कालरा की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता चिन्मय प्रदीप शर्मा की दलीलों पर गौर किया और कहा कि महिलाओं को एनडीए में शामिल करने को एक साल तक प्रतीक्षा नहीं की जा सकती। अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि महिलाओं के प्रवेश की सुविधा के लिए एक अध्ययन समूह का गठन किया

गया है, और इसे सुविधाजनक बनाने के लिए आवश्यक तंत्र मई 2022 तक लागू किया जा सकता है। एएसजी ने 14 नवंबर को होने वाली अगली एनडीए प्रवेश परीक्षा को छोड़ने की अपील की।

पीठ ने कहा, "हम आपकी समस्या ओं को समझते हैं। मुझे यकीन है कि आप लोग समाधान खोजने में सक्षम हैं। परीक्षा देने के इच्छुक उम्मीदवारों की आकांक्षाओं को देखते हुए केंद्र से इस अनुरोध को स्वीकार करना हमारे लिए मुश्किल है।" पीठ ने कहा, "सशस्त्र सेवाओं ने बहुत कठिन परिस्थितियों का सामना किया है। आपात स्थिति से निपटना उनके प्रशिक्षण का एक हिस्सा है। हमें यकीन है कि वे इस आपातकालीन स्थिति से पार पाने में भी सक्षम होंगे।"

गोवा की पूरी पात्र आबादी का अक्टूबर के अंत तक पूर्ण टीकाकरण – प्रमोद सावंत

गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा की पूरी पात्र आबादी का कोरोना वायरस संक्रमण रोधी पूर्ण टीकाकरण अक्टूबर तक हो जाएगा। सावंत ने प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी के स्वागत संबोधन में यह बात कही। उन्होंने कहा, "31 अक्टूबर तक गोवा देश का ऐसा पहला राज्य बन जाएगा जहां पूरी पात्र आबादी को टीके की दूसरी खुराक दे दी गई हो। हमने सौ प्रतिशत लोगों को टीके की पहली खुराक दे दी है और अबतक 42 प्रतिशत लोगों को दूसरी खुराक भी दी जा चुकी है।" उन्होंने कहा कि राज्य में केवल छह प्रतिशत टीके ही बर्बाद हुए हैं, जो अपने आप में एक उपलब्धि है। मुख्यमंत्री सावंत ने कहा कि टीकाकरण अभियान को टीका उत्सव कार्यक्रम के जरिए गति प्रदान की जा रही है और इसे राज्य के विभिन्न गांवों तक पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के जन्म दिन के मौके पर राज्य में रिकॉर्ड तोड़ टीके लगाए गए। सीएम ने बताया कि धार्मिक नेताओं और प्रभावशाली लोगों को इसमें शामिल किया है ताकि लोगों को टीकाकरण कराने के लिए प्रेरित किया जा सके। ◆◆◆

तालिबान आते ही ड्रग्स ट्रैफिकिंग बढ़ी

गुजरात में पकड़ी गई 21 हजार करोड़ की हेरोइन

जअफगानिस्तान में तालिबानी हुकूमत के बाद नशे के कारोबार का ठिकाना भारत को बनाने की साजिश का बड़ा मामला सामने आया है। राजस्व खुफिया निदेशालय ने गुजरात के कच्छ के मुंद्रा पोर्ट से 3,000 किलो हेरोइन जब्त की है। इसकी अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत 21 हजार करोड़ रुपए बताई जा रही है।

यह देश में ड्रग की सबसे बड़ी बरामदगी तो है ही, साथ ही अफगानिस्तान में तालिबानी कब्जे के बाद दुनिया में ड्रग्स की खेप की सबसे बड़ी जब्ती भी है। राजस्व खुफिया निदेशालय के मुताबिक ड्रग दो कंटेनर्स से जब्त की गई है। एक में 2,000 किग्रा और दूसरे में 1,000 किग्रा हेरोइन है। जब्त की गई हेरोइन को डीआरआई के कंट्रोल में रखा गया है। अफगानिस्तान से रवाना यह खेप 13 सितंबर को ईरान के बंदर अब्बास बंदरगाह से गुजरात रवाना हुई थी और इसे आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा पहुंचना था।

विजयवाड़ा की कंपनी के नाम आया था कंसाइनमेंट

मुंद्रा से जब्त हेरोइन विजयवाड़ा की मेसर्स आशी ट्रेडिंग कंपनी के पते पर जानी थी। 17 सितंबर को गिरफ्तार इस कंपनी के मालिक एम. सुधाकर और उनकी पत्नी दुर्गपूर्णा राजस्व खुफिया निदेशालय की रिमांड पर हैं। आशी ट्रेडिंग कंपनी को पिछले साल काकीनाडा पोर्ट से चावल एक्सपोर्ट के लिए रजिस्टर्ड कराया गया था। इसके पते पर हेरोइन का कंसाइनमेंट टैल्कम स्टोन के नाम पर मंगाया गया था। हालांकि, कंपनी का कहना है कि जिन कंटेनर्स में हेरोइन पकड़ी गई है उन्हें चेन्नई जाना था। इन पर बतौर एक्सपोर्टर कंधार के हसन हुसैनी ट्रेडर्स का नाम दर्ज है। इस बीच, अडानी पोर्ट के प्रवक्ता ने कहा है कि पोर्ट में कंटेनरों की जांच पोर्ट संचालक कंपनी नहीं, बल्कि सक्षम एजेंसियां ही कर सकती हैं।

इस मामले में दिल्ली– एनसीआर से भी कुछ अफगान नागरिकों को हिरासत में लिया गया है। वहीं अहमदाबाद, दिल्ली, चेन्नई, गांधीनगर और मांडवी में भी तलाशी ली गई है। दूसरी तरफ प्रवर्तन निदेशायल इस मामले में मनी लॉन्ड्रिग की भी जांच करेगा।

भारत के रास्ते हेरोइन तस्करी का पुराना रूट

6 जून 2021 से लेकर 19 जुलाई तक भारत में करीब सवा सौ करोड़ की हाई क्वालिटी की 18 किलो हेरोइन पकड़ी गई थी। अब करीब 3,000 किग्रा हेरोइन पकड़े जाने से एक्सपर्ट्स की ये आशंका सही साबित हो गई है कि अफगानिस्तान में सत्ता बदलने के बाद ड्रग्स तस्करी में बेतहाशा इजाफा होगा। अफगानिस्तान में तालिबान खुद अफीम और हेरोइन की तस्करी से जुड़ा है। गृह युद्ध से बचने के लिए और विदेशी मदद नहीं मिलने के चलते तालिबान अब ड्रग्स ट्रेड को कई गुना बढ़ा सकता है।

जून में भी आया था आंध्र प्रदेश की इसी कंपनी के पास 25 टन का कंसाइनमेंट

एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक इस साल जून में भी विजयवाड़ा की इसी कंपनी के पते पर 25 टन सेमी कट टैल्कम पाउडर ब्लॉक्स आए थे। इसे दिल्ली के एक कारोबारी को कथित तौर पर एक ट्रक से भेजा गया था। हालांकि वह ट्रक मुंद्रा पोर्ट से दिल्ली के रास्ते में किसी टोल से नहीं गुजरा। दिल्ली के उस कारोबारी की पहचान भी अब फर्जी बताई जा रही है, जिसे यह भेजा गया था। वहीं, विजयवाड़ा कमिश्नर ने कहा कि कंपनी के लाइसेंस के लिए यहां के पते के अलावा और कोई संबंध नहीं मिला है। ◆◆◆

KALYANI
DRIVING INNOVATION

With Best Compliments

innovation at the heart

EXPANDING HORIZONS

BHARAT FORGE

Mundhwa, Pune - 411 036, INDIA www.bharatforge.com | www.kalyanigroup.com

TITELNO. MAHHINO7214/13/A2009-TC ■ REGISTRATION NO : MAHHIN/2009/30744
BY OFFICE THE REGISTRAR OF NEWS PAPERS FOR INDIA,
MINISTRY OF INFORMATION & BRODCASTING, GOVT.OF INDIA